अखिल भारतीय तृणमूल कॉन्ग्रेस

जनगण की क्षमता
बंगाल में चाहिए ममता

इस्तहार २०१६

तृणमूल मतलब खुली हवा
दुःशासन का मिटे निशान
तृणमूल मतलब राम और रहिम,
सिख-ईसाई सब समान।

तृणमूल मतलब भर पेट भोजन
खाद्य साथी कहे पुकार
तृणमूल मतलब सबुज साथी और
कन्याश्री की जय-जयकार।

तृणमूल मतलब युवा सोच
युवाश्री का है कमाल
तृणमूल मतलब अच्छी सेहत
बिना खर्च के अस्पताल।

तृणमूल मतलब रायबेंश में छौ
और लोकप्रिय बाऊल गान
तृणमूल मतलब किसान के घर
भरा रहे हमेशा धान।

निवेदन

पश्चिम बंगाल के लोगों की विरासत को साथ लेकर माँ-माटी-मानुष के आशीर्वाद, शुभकामनाओं एवं मेहरबानी की बदौलत वर्ष २०११ में २० मई को ३४ वर्षों के वामपंथी कुशासन के हाथ से बंगाल को मुक्त कराकर हमारी परिवर्तन की सरकार ने कदम बढ़ाना शुरू किया। लोगों के लिए लोगों की सरकार - यही हमारी आकांक्षा थी। आपके हार्दिक सहयोग तथा आप सभी के सक्रिय प्रयास से वह आकांक्षा पूरी हुई थी।

हम कुछ ही दिनों में बांग्ला शुभ नववर्ष १४२३ मनाने जा रहे हैं। बांग्ला शुभ नववर्ष की आप सभी को अग्रिम अभिनंदन एवं शुभकामनाएँ।

आज प्रायः साढ़े चार वर्ष के उपरान्त जब हम सोलहवें आम विधानसभा चुनाव के सम्मुखीन होने जा रहे हैं, तब गर्व के साथ कह सकते हैं कि सिर्फ़ साढ़े चार वर्ष के अल्प समय में हमारी सरकार जो काम कर सकी है वह महज वर्ष २०११ में किए गए बादों का पालन ही नहीं बल्कि और भी नए-नए काम किए गए हैं, जिससे बंगाल अग्रसर हो रहा है। इन साढ़े चार वर्षों में बहुत सारे काम हुए हैं, वे सिर्फ़ बंगाल की उन्नति के ही साक्षी नहीं हैं, बल्कि बंगाल के लोगों को दिए हैं - सामाजिक और सांगठनिक राहत। गणतंत्र का चेहरा खिल उठा है। विरोधियों के कुत्सा प्रचार और प्राकृतिक एवं आर्थिक संकट में केन्द्र सरकार का विषमतापूर्ण आचरण हमें दबा नहीं सका।

आज बंगाल ने अपना खोया हुआ गौरव फिर से पा लिया है। बंगाल आज विकास, प्रगति और आपसी संबंधों की रक्षा के लिए देश के एक श्रेष्ठ स्थान पर पहुँच गया है। यह काम जन साधारण के विश्वास, आस्था एवं भरोसे से ही संभव हुआ है। माताओं-भाइयों-बहनों का काम के प्रति व्यक्त किए गए विश्वास ने ही काम के प्रति हमें आस्थावान होने में काफी मदद दी है। राजनीतिक हकों की रक्षा के लिए हम आम लोगों के साथ थे, हैं और निरंतर रहेंगे।

विगत ३४ वर्षों के शासनकाल में सीपीएम सरकार ने शासन के नाम पर एक दलीय शासन-व्यवस्था कायम करके हमारे चहेते राज्य पश्चिम बंगाल को एक गतिहीन, उन्नतिविहीन तथा दिशा हीन राज्य में बदल दिया था। सिंगूर-नन्दीग्राम-नेताई से लेकर साईंबाड़ी,

मरिचझांपी-बानतला-धानतला तक सभी जगह सरकारी मदद से दलीय संत्रास चल रहा था। इसीलिए उस समय के लोगों की सबसे बड़ी आकांक्षा थी - विकास में विश्वासी, प्रगतिमूलक विचारधारा के निर्माता की एक ऐसी सरकार जहाँ संत्रास का नामोनिशान नहीं होगा और आम लोग खुली हवा में साँस ले सकेंगे और मन-प्राण के साथ होगा जन साधारण के लिए काम और काम।

अगर सच कहा जाय तो साढ़े तीन दशकों तक कुशलतापूर्वक अकर्मण्यता से एक राज्य को जिस तरह से पीछे धकेल दिया गया था, ऐसे माहौल में काम करना बेहद कठिन था।

''को-आर्डिनेशन कमिटी'' के नाम की एक चक्की में डालकर प्रशासन के हर स्तर पर काम में लालफीताशाही ला दी गयी थी। पूर्ववर्ती सीपीएम सरकार ने काम न करने की एक ठोस परंपरा तैयार कर दी थी। काम शुरू करते समय हमने पाया कि बहुत सारी फाइलें नदारद हैं। जो कुछ मौजूद भी था, उन्हें ढूँढ कर निकालने में प्रायः दो वर्ष लग गए। अगर सही रूप में देखा जाय, तो हमें काम करने का समय २५ से ३० महीने ही मिले। इतने कम समय में राज्य में आमूल परिवर्तन और कायाकल्प करते हुए हर तरफ हमने सोना उत्पन्न किया।

सत्ता में आने से पहले विज्ञापन में हमने जो-जो काम करने का वादा किया था, उसका काफी अंश न सिर्फ पूरा हुआ, बल्कि हमने और भी नए-नए बेशुमार काम ढूँढ़ निकाले हैं। इन कामों की खोज बहुत पहले ही हो जानी चाहिए थी। कुल मिलाकर एक असंभव को संभव बनाया गया।

उन दिनों के लोगों की उस प्रत्याशा को ध्यान में रखते हुए हमने सभी राजनीतिक वादों को सिर्फ़ पूरा ही नहीं किया बल्कि कथनी और करनी में एक सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया है।

यदि ध्यान से देखा जाय अथवा हमारे आँकड़े यदि ढंग से देखे जाएँ तो यह देख सकेंगे कि वामफ्रंट सरकार ३४ वर्षों में जो काम नहीं कर सकी अथवा जिन कामों की ओर उनकी नजर नहीं गयी, वे सभी काम हमने मात्र ५ वर्षों में कर दिखाए हैं। यह सिर्फ़ जबानी कथन नहीं है। माटी के लिए, मानुष के लिए सरोकार न रहने पर तथा काम करने की मानसिकता न होने पर यह संभव नहीं था। स्वाधीनता के पश्चात् पश्चिम बंगाल के सामाजिक और राजनैतिक इतिहास का जरा सा अध्ययन करने पर देख सकेंगे कि इसके आगे की सरकारें विभिन्न तरीके से पश्चिम बंगाल को अन्य राज्यों की तुलना में पीछे धकेल दिया था।

हमारा परिचय है - हमारा काम और हमारी उन्नति का मूलमंत्र है - हमारा साफ-सुथरा ढांचागत परिवर्तन। इसके साथ ही अन्य राज्यों की ओर नजर दौड़ाएँ तो देखेंगे कि बीजेपी, सीपीएम, कांग्रेस इत्यादि सभी दुर्नीति, दमन नीति तथा कर्म विमुखता के दोष से ग्रस्त हैं। एकमात्र हम लोगों ने ही जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि के रूप में लोगों के विचारों को सम्मान दिया है। इसीलिए, इस बार भी मतदान के पूर्व एक आवेदन है, क्योंकि बंगाल के विकास को निरंतर जारी रखने के लिए तृणमूल सरकार ही एकमात्र विकल्प है। एक और शक्तिशाली उन्नत तृणमूल सरकार - जिसे बनाएँगे आप लोग।

क्षमता में आने के बाद हमारा पहला काम था सिंगुर की जमीन का अधिग्रहण करके अनिच्छुक किसानों को उनकी जमीन लौटाना। इस उद्देश्य के साथ हमने विधानसभा में अपना पहला विल (सिंगुर की जमीन का अधिग्रहण बिल) पास किया। क्योंकि हम

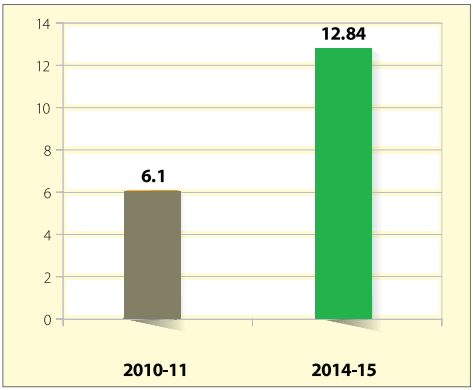

राष्ट्र के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है प्रति व्यक्ति आय बंगाल में

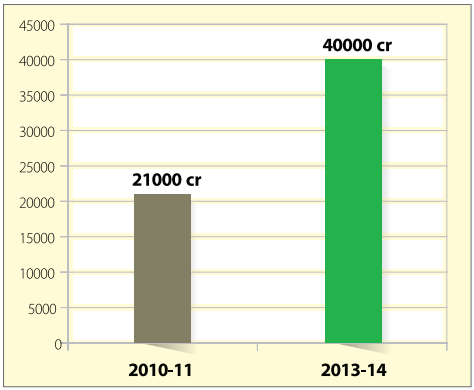

सिर्फ़ तीन सालों में दुगुनी हुई कर की वसूली

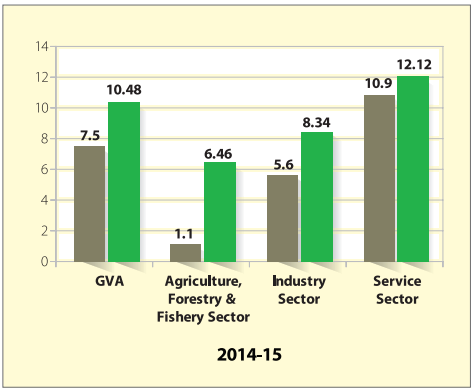

सर्वांगीण विकास, उद्योग, कृषि एवं सेवा के विकास की दर में बंगाल है काफी आगे

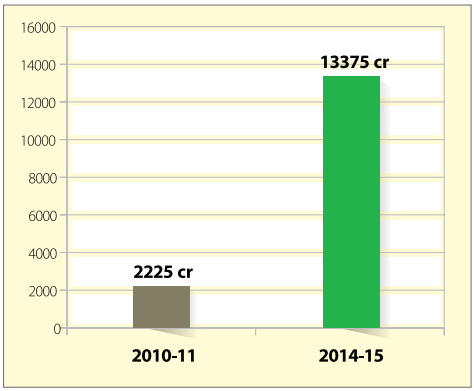

सम्पदा का सृजन बढ़ा है 6 गुणा

भारत पश्चिम बंगाल

जबरदस्ती जमीन अधिग्रहण के खिलाफ हैं। इस बिल का मामला फिलहाल महामहिम उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है। हम वादा करते हैं कि सिंगुर की समस्या के समाधान में हम कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे तथा समाधान होने तक हम सिंगुर वासियों के संग खड़े रहेंगे और वह भी सहयोग का हाथ बढ़ाकर। सिंगुर के अनिच्छुक किसानों एवं खेतीहर मजदूरों को उनका हक और सम्मान अवश्य मिलेगा। अनिच्छुक किसानों की जमीन लौटाना हमारा प्राथमिक लक्ष्य है।

बीमार पड़े एवं बंद चाय बागानों के श्रमिकों के हितों एवं चाय बागानों के पुनर्गठन के लिए हमारी सरकार ने १०० करोड़ रुपये का कोष तैयार किया है एवं चाय बागानों के श्रमिकों को सिर्फ़ ४७ पैसे की दर से अनाज दिए जा रहे हैं।

वहीं दूसरी ओर, श्रमिक वर्ग के हितों के लिए सरकार ने डनलप एवं जेसप औद्योगिक घरानों का अधिग्रहण किया है। जब तक कि अनुमोदित बिल को विधानसभा में मंजूरी नहीं मिल जाती तबतक श्रमिकों को रु.१०००० (दस हजार रुपये) हर महीने दिए जाएँगे।

हमारा राजनैतिक दल प्रगति, विकास तथा धर्मनिरपेक्षता का प्रबल विश्वासी रहा है। हम सभी हमेशा से जन साधारण के पक्ष में काम करने में विश्वास रखते हैं। इसीलिए बंगाल को जिन लोगों ने वंचित व लांछित किया है और आतंक के एक वातावरण का निर्माण किया है, उन सीपीएम, कांग्रेस, बीजेपी दल के कुप्रचार के बावजूद हम अपने काम को आगे बढ़ाने में सफल हुए हैं। माँ-माटी-मानुष के आशीर्वाद, शुभकामनाओं तथा मेहरबानियों से नए बंगाल के सृजन का जो सपना हमने देखा था, उसमें से अधिकांश सपने साकार हुए हैं। ये सपने साकार इसलिए हुए हैं क्योंकि आप हमारे साथ हैं। आपने हम पर भरोसा किया है, इसीलिए हमें संघर्ष करने का साहस मिला है। अतः आगामी विधानसभा चुनाव में हम सिर्फ़ एक राजनैतिक दल के रूप में नहीं लड़ेंगे, बल्कि जन साधारण के साथ और जन साधारण के हित के लिए लड़ेंगे।

क्षमता के आने के बाद से पिछले साढ़े चार वर्षों में हमने लगातार दिन-रात काम किए हैं। जबकि हमारे राज्य में सीपीएम, कॉन्ग्रेस, बीजेपी जैसी राजनीतिक पार्टियाँ सिर्फ़ विरोधिता करने के उद्देश्य से हमारे खिलाफ अनैतिक गठबंधन तैयार कर रही हैं। वर्ष २०१६ के विधानसभा चुनाव को देखते हुए एक अनौतिक स्वार्थपूर्ण तथाकथित अलिखित गठबंधन तैयार हो रहा है। दिवालिया राजनीति, दिवालिया नीति एवं समझौते के गठबंधन के नाम पर राजनीतिक वजूद तलाशने की यह है एक बेकार कोशिश।

हम विश्वास करते हैं मानुष के महागठबंधन पर। गणतंत्र देश के नागरिक ही हैं '१००'। इसलिए हम अकेले ही यह चुनाव लड़ रहे हैं अपने प्रिय माँ-माटि-मानुष के १०० फीसदी को साथ लेकर।

मानुष का महागठबंधन हमारा पथ-प्रदर्शक बनेगा।

लोगों को नुकसान पहुँचे, ऐसा कोई भी काम मेरे द्वारा नहीं होगा - यह विश्वास जैसे जन साधारण का मेरे ऊपर है, उसी प्रकार मेरा है जनसाधारण के ऊपर।

दुनिया में जबतक हम काम करने में सक्षम रहेंगे, तब तक लोगों के लिए काम करते जाएँगे - यह मेरा वादा है। इस वादे से मुझे कोई भी विचलित नहीं कर सकता। यही हमारा जीवन है, यही हमारा संग्राम है और यही हमारी जान है।

इन साढ़े चार वर्षों के दौरान ऋण का बोझ सिर पर रखकर सदैव जनता का काम करने का मैंने प्रयास किया है, और आगे भी करूँगी। यदि हमारे ऊपर यह विश्वास है, तो माँ-माटी-मानुष सभी नागरिकों से मेरा निवेदन है कि सवेरे-सवेरे अपना वोट डालें। प्रसन्न चित्त होकर जोड़ा फूल को वोट दें, बंगाल को आगे ले जाने में योगदान दें।

आपके आशीर्वाद, शुभकामनाओं एवं कृपा की हम कामना करते हैं।

आप जो राय देंगे, वह मैं सिर आँखों पर रखूँगी।

आपकी

११ मार्च, २०१६

पहले की वामफ्रन्ट सरकार द्वारा छोड़े गए प्रायः दो लाख करोड़ ऋण का बोझ अपने कंधों पर लेकर भी हमने अपनी प्रगति की रफ्तार को जारी रखा। हमें आर्थिक स्वाधीनता नहीं मिली। इतने बड़े ऋण का बोझ लेकर हम कैसे कार्य कर सकेंगे, यह दुश्चिंता शुरू में बनी हुई थी। इन साढ़े चार वर्षों में प्रायः एक लाख करोड़ कर्ज चुकाकर भी आम लोगों के आशीर्वाद से हम सिर उठाकर खड़े हैं। इन पाँच वर्षों में शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, कृषि, व्यापार, उद्योग, संस्कृति, छोटे, मझोले एवं कुटीर उद्योगों आदि के क्षेत्रों में काफी प्रगति हुई है। नागरिक सेवाओं में सुधार हुआ है। अल्प संख्यक समुदाय एवं आदिवासी व अनुसूचित जाति/जनजातियों के लोगों की सर्वांगीण सामाजिक उन्नति नजर आ रही है। इन पाँच वर्षों में हमें जो उपलब्धि हासिल हुई है, वह है पश्चिम बंगाल की कार्य संस्कृति में पुनरुद्धार। हमारे सभी मंत्रालयों में हम अनुशासन की भावना का संचार कर सके हैं और साथ ही ''सरकारी काम'' के संबंध में आम लोगों के दृष्टिकोण में आमूल परिवर्तन लाने में सफल हुए हैं। मंत्री से लेकर विभागीय अधिकारी तक सबको साथ लेकर सिर्फ़ कोलकाता में ही नहीं बल्कि जिलों-जिलों में १०५ से अधिक प्रशासनिक बैठकों के जरिए आम लोगों के साथ सरकारी संबंधों को स्वाभाविक किया गया है। सरकारी अधिकारियों के ऊपर से अनावश्यक राजनीतिक दबाव कम करके उनके कामों में पर्याप्त स्वाधीनता दी गयी है। काम के समय निर्दिष्ट कार्य निष्पादन पर बल दिया गया है तथा काम में लापरवाही के लिए जवाबदेही तय करने की व्यवस्था की गयी है। उद्योगों में विनिवेश के क्षेत्र में ''सिंगल विण्डो क्लीयरेंस'' चालू की गयी है, जिसकी वजह से लालफीताशाही काफी कम हुई है।

इस बीच, बंगाल के सभी क्षेत्रों के आम लोगों पर किसी प्रकार के कर का बोझ न डालते हुए ९ करोड़ जनसंख्या में से ८ करोड़ लोगों को किसी न किसी प्रकार की सरकारी जन कल्याणकारी सेवा प्रदान कर हमारी माँ-माटी-मानुष की सरकार ने जनसाधारण को साथ लेकर बंगाल के सरकारी कामों में एक नए जोश का संचार किया है। इसके लिए प्रशासन को साथ लेकर हमें कम पापड़ नहीं बेलने पड़े। राज्य स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर तक के हमारे प्रशासनिक अधिकारियों से सभी प्रकार का सहयोग हमें मिला है, इसीलिए हमारे लिए इतना काम करना संभव हुआ है। तृणमूल कांग्रेस दल ने कभी मेरे अथवा हमारे सरकारी कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया है, बल्कि दल के कार्य में भी हमें समय नहीं देना पड़ा। इसके फलस्वरूप अपना पूरा समय आम लोगों के लिए काम करने में मैं लगा सकी। दल के कार्यकर्ताओं ने कभी भी सरकारी काम में हमें बाधा नहीं पहुँचायी है। इस वजह से आम लोगों के काम स्वाधीनतापूर्वक करने और प्रशासनिक स्तर पर निर्णय लेने का जो अवसर मुझे मिला है, उससे हमारे काम में आसानी हुई है।

उद्योग में हम अभी आगे हैं। वामफ्रंट के शासनकाल में जहाँ ''औद्योगिक आउटपुट'' १२%

से घट कर २% आ गया था, वहीं मेरी सरकार के शासनकाल में बंगाल में निवेश का बुलंद दरवाजा खुल गया है। बंगाल के औद्योगीकरण को लेकर जो प्रतिकूल हवा चल रही थी, वह थम गयी है। औद्योगीकरण का जो मार्ग वामफ्रंट के शासनकाल में अवरुद्ध हो गया था, अब दुनिया के लिए प्रशस्त हो चुका है। २०१६ के जनवरी महीने में कोलकाता में शिखर वाणिज्य सम्मेलन द्वितीय बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट का आयोजन सफलतापूर्वक किया गया। इसबार का यह सम्मेलन आकार एवं विस्तार में काफी बड़ा था। इस सम्मेलन में ४८ घण्टे में १४३ ''बिजनेस-टू-बिजनेस'' मीटिंग हमने की है, ६८ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए और कुल ₹२,५०,२५३.७४ करोड़ रुपये निवेश का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। पिछली बार २०१५ में प्रथम विश्वबंग वाणिज्य सम्मेलन में कुल २.४३ लाख करोड़ रुपये के निवेश-प्रस्ताव में से प्रायः ७५ हजार करोड़ रुपये का प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार की परियोजनाओं के बाबद प्राप्त हुआ था। इस बार के समिट में अधिकांश प्रस्ताव निजी क्षेत्र से आया है। राज्य के मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र से ₹१,१६,९५८ करोड़ का निवेश प्रस्ताव आया था, जबकि संरचना क्षेत्र से ₹३७,४८२ करोड़ का। इसके अलावा, हमारा लंदन सफर असाधारण रूप से सफल होने की वजह से पहली बार दुनिया में राज्य की छवि उज्ज्वल हुई है। इसके अतिरिक्त २०१४ के अगस्त महीने में सिंगापुर में आयोजित ''बिजनेस मीट'' में विभिन्न देशों के निवेशकों के साथ राज्य के व्यवसाइयों के १३ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुए, जिनकी प्रगति की ओर भी हमारा ध्यान है। उल्लेखनीय निर्माण, भारी उद्योग, छोटे-मझोले-कुटीर उद्योग, खान, स्वास्थ्य और शिक्षा, शक्ति और प्राथमिक गैस, परिवहन और पर्यटन, नागरिक सुविधा, खाद्य प्रसंस्करण, आर्थ सेवा, मत्स्य व्यापार, प्राणी संरक्षण एवं प्रौद्योगिकी आदि सभी क्षेत्रों में वृहद् निवेश एवं रोजगार के अवसर हैं।

हमें ज्ञात है कि उद्योग के वास्तविक संचालन शक्ति का स्रोत है- मानव। हमने देखा है कि पहले की बन्द-संस्कृति के डर से उद्योगपति इस राज्य में उद्योग लगाने का साहस नहीं जुटा पाते थे। उस कर्महीन बन्द से हमने बंगाल को आजाद किया है। उद्योग सृजन का मार्ग अब आसान हो गया है। हमने जान लिया है कि उन्नति की प्राथमिक जरूरत है अच्छी संरचना। छोटे-मझोले-कुटीर उद्योग, बुनाई उद्योग, पर्यटन, सूचना प्रौद्योगिकी इत्यादि क्षेत्रों में हमने नई ढांचागत सुविधाएँ तैयार करने पर जोर दिया है।

हम समझ गए हैं कि ''कर्महीन युवाशक्ति'' नहीं बल्कि रोजगारप्राप्त युवाशक्ति ही उन्नति का एकमात्र समाधान है। इसीलिए, वर्तमान आर्थिक नीतियों में आवश्यक सुधार किए गए हैं। इन चार वर्षों में बेशुमार बेरोजगारों को रोजगार मिले हैं। देश के आर्थिक विकास में इसकी भूमिका सार्थक व अहम् है।

वामफ्रंट के शासन काल में सुपरिचित नारा था - ''कृषि हमारी बुनियाद है''। परन्तु वर्ष

२०१०-११ में एक किसान की वार्षिक आमदनी थी - ९३ हजार रुपये। तृणमूल सरकार के शासनकाल में दिहाड़ी मजदूर की मजदूरी में उल्लेखनीय वृद्धि से वर्ष २०१४-१५ में एक किसान की सालाना आमदनी प्रायः एक लाख साठ हजार रुपये हो गयी है। आने वाले दिनों में किसानों की सालाना आमदनी और भी दुगुनी करने का लक्ष्य हमने रखा है। किसान अपनी फसल की बिक्री सीधे बाजार में लाकर कर सकें, इसके लिए किसान मण्डी, किसान बाजार आदि की व्यवस्था की गयी है। ६९ लाख से अधिक किसानों को ''किसान क्रेडिट कार्ड'' प्रदान किए गए हैं। खाद्य फसल के उत्पादन में पश्चिम बंगाल लगातार चार बार राष्ट्रीय स्तर का ''कृषि कर्मण'' पुरस्कार हासिल किया है। इसके अलावा कृषि महा विद्यालय का निर्माण करके कृषि संबंधी समग्र विकास की कोशिश की जा रही है। कृषि यदि सचमुच हमारी बुनियाद हो, तो उसका उचित मूल्यांकन न होने से हमारी सभ्यता, संस्कृति सभी तो मूल्यहीन हो जाएँगी।

आर्थिक प्रतिकूलता को दूर कर बंगाल आज सुनाम के साथ अग्रसर है। कई मंत्रालय राष्ट्रीय गर्व के रूप में प्रधान शक्ति व प्रथम स्थान से सम्मानित हैं। लगातार चार वर्षों तक कृषि कर्मण पुरस्कार में बंगाल प्रथम, लघु उद्योग में बंगाल प्रथम, कुशलता विकास में बंगाल प्रथम, ग्रामीण सड़क, खअध तथा स्वच्छ भारत कार्यक्रम में ''निर्मल बांगला'' नाम से बंगाल प्रथम है। जंगल महल तथा दार्जिलिंग में शान्ति स्थापना के प्रयास में बंगाल देश भर में एक मॉडल है। यह सोचकर भी अच्छा लगता है कि बंगाल को विश्व बंगाल के रूप में प्रतिष्ठित करने के लक्ष्य के साथ हमारी निर्दिष्ट कार्यसूची है। इन चार वर्षों में बंगाल में प्रायः ६८ लाख रोजगार और ९८ करोड़ कार्यदिवस का सृजन हुआ है। २ लाख और रोजगार सृजन को मूर्त्त रूप देने के पथ पर हम हैं। १०० दिन रोजगार कार्यक्रम में भी बंगाल प्रथम है।

सभी सम्प्रदाय के लोगों को दंगों से रिहाई दी गयी है। प्रशासन और जन साधारण के सहयोग से सभी उत्सव खासकर दुर्गापूजा, ईद, कालीपूजा, मुहर्रम, छठपूजा, रास यात्रा, जगधात्री पूजा से लेकर बड़ा दिन तक सभी उत्सव शान्तिपूर्वक मनाए गए। गंगासागर मेले में लाखों-लाखों तीर्थयात्री शामिल हुए और सकुशल लौट गए हैं। कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है, जिससे उत्सव के दिनों में लोगों को आघात पहुँचा हो। आम लोगों की खुशियों को महत्वपूर्ण मानते हुए हमारी सरकार ने ३६५ दिन निरंतर काम किया है, ताकि सभी वर्ग के लोग खुश रह सकें।

अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अभी सामाजिक और आर्थिक रूप से अधिक सुरक्षित हैं। इसके साथ ही साथ, इन दिनों अनुसूचित जाति/जनजाति तथा ओबीसी के लोगों के विकास को भी देखा जा सकता है। जंगल महल के लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य आदि विषयों पर विशेष

जोर दिया गया है। पश्चिमी मिदनापुर के भरसाघाट पर १.४७२ कि.मी. लम्बा बहु प्रतीक्षित जंगलकन्या पुल का निर्माण किया गया है। उल्लेखनीय है कि ''खाद्य साथी'' परियोजना के अन्तर्गत बंगाल के ९ करोड़ में से ७ करोड़ लोगों को २ रुपये प्रति किलो के हिसाब से चावल और आटा दिया जा रहा है। इसमें से अधिकांश जंगल महल तथा अनुसूचित जाति-जनजाति संप्रदाय के लोग हैं। इतना ही नहीं, आजादी के छः दशक बाद भी बहुत से लोग अपनी ''राष्ट्रीयता'' को लेकर चिंतित थे। हमने कोशिश करके उन्हें अपने देश वापस भेजा है। ''छीटमहल'' नामक अंधकार से उन्हें बाहर निकालने में हम सफल हुए हैं।

लोग परिवर्तन चाहते थे। हमने उसी परिवर्तन को लक्ष्य बनाकर अपना सफर शुरू किया था। परिवर्तन के मार्ग में धर्मनिरपेक्षता, सुशासन, उत्कृष्ट शिक्षा से शासन व्यवस्था, सबके घरों में रोशनी, खाद्यसाथी से सबुज साथी, जल साथी से कन्याश्री, युवश्री से शिक्षाश्री, उद्योग से कृषि, खेल-कूद से संस्कृति, सड़क से जमीन का पट्टा, ओबीसी आरक्षण से लेकर शंसापत्र का ाशिश्रष रींशींीरींळेप परिवहन व्यवस्था से नगर विकास, ग्राम से शहर तक सभी जगह माँ-माटी-मानुष सरकार का विशाल कर्मयज्ञ चला है। पहाड़ से जंगल तक समूचे बंगाल में लोगों के गणतांत्रिक अधिकार की स्थापना हुई। फिलहाल राज्य में अकाल, बाढ़ या लोडशेडिंग की छाया भी नहीं पड़ी है।

हमने २० मई, २०११ को सत्ता में आने के बाद निरंतर उन्नति का इतिहास लिखना शुरू किया है। आज सही अर्थों में तृणमूल सरकार बंगाल को उन्नति के शिखर पर ले गयी है। सैकड़ों बाधाओं के बावजूद साढ़े चार वर्षों में हमने जो कार्य किये हैं, वे दिए गए ग्राफों पर नजर डालने से ही स्पष्ट हो जाएँगे।

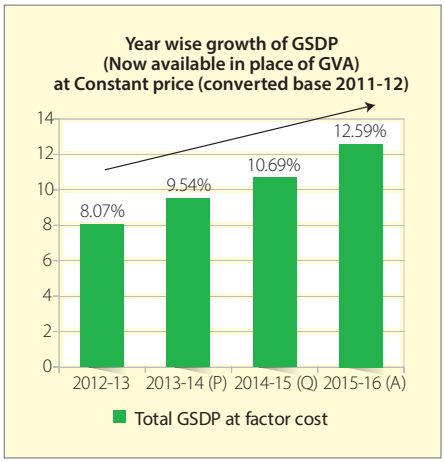
Year wise growth of GSDP
(Now available in place of GVA)
at Constant price (converted base 2011-12)
14
12
10
8
6
4
2
0
8.07%
9.54%
10.69%
12.59%
2012-13
2013-14 (P)
2014-15 (Q)
2015-16 (A)
Total GSDP at factor cost

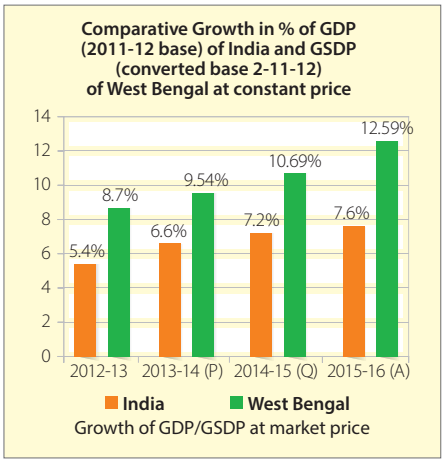
Comparative Growth in % of GDP
(2011-12 base) of India and GSDP
(converted base 2-11-12)
of West Bengal at constant price
14
12
10
8
6
4
2
0
5.4%
8.7%
6.6%
9.54%
7.2%
10.69%
7.6%
12.59%
2012-13
2013-14 (P)
2014-15 (Q)
2015-16 (A)
India
West Bengal
Growth of GDP/GSDP at market price

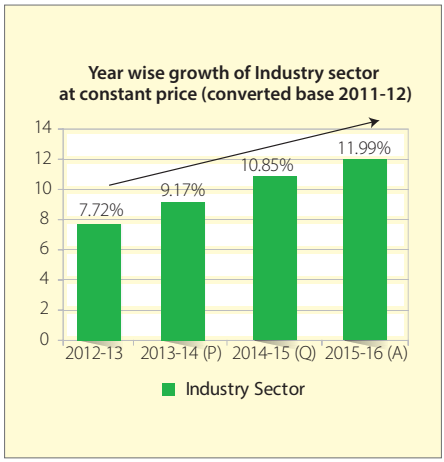
Year wise growth of Industry sector
at constant price (converted base 2011-12)
14
12
10
8
6
4
2
0
7.72%
9.17%
10.85%
11.99%
2012-13
2013-14 (P)
2014-15 (Q)
2015-16 (A)
Industry Sector

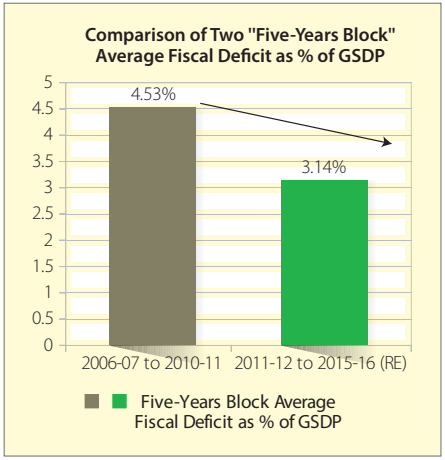
Comparison of Two "Five-Years Block" Average Fiscal Deficit as % of GSDP
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
4.53%
3.14%
2006-07 to 2010-11
2011-12 to 2015-16 (RE)
Five-Years Block Average Fiscal Deficit as % of GSDP

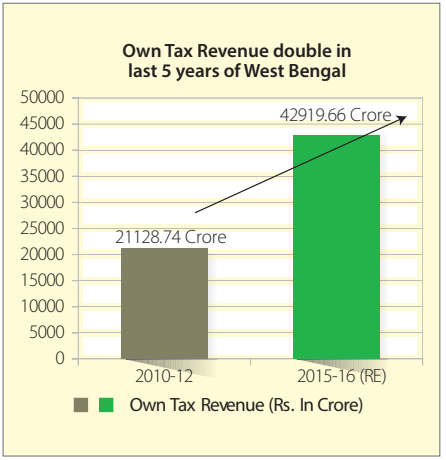
Own Tax Revenue double in last 5 years of West Bengal
50000
45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
42919.66 Crore
21128.74 Crore
2010-12
2015-16 (RE)
Own Tax Revenue (Rs. In Crore)

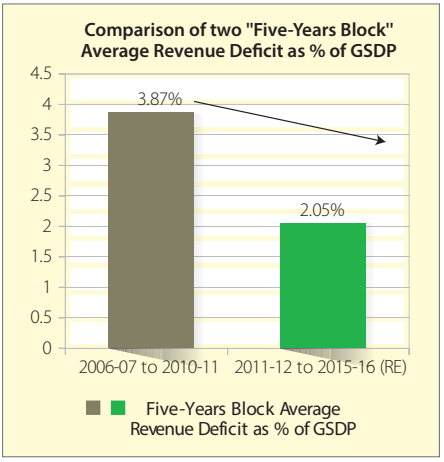
Comparison of two "Five-Years Block" Average Revenue Deficit as % of GSDP
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
3.87%
2.05%
2006-07 to 2010-11
2011-12 to 2015-16 (RE)
Five-Years Block Average Revenue Deficit as % of GSDP

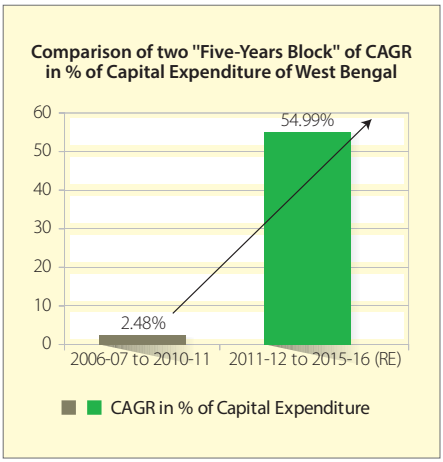

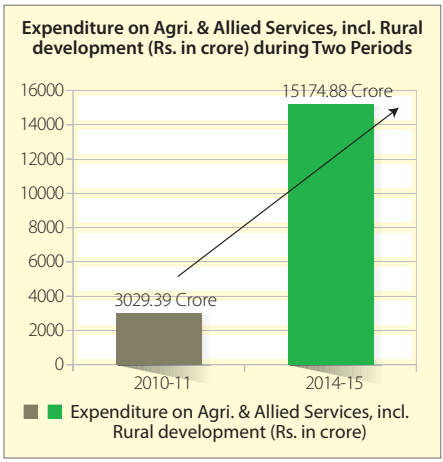

Comparison of two "Five-Years Block" of CAGR in % of Capital Expenditure of West Bengal
60
50
40
30
20
10
0
54.99%
2.48%
2006-07 to 2010-11
2011-12 to 2015-16 (RE)
CAGR in % of Capital Expenditure

Expenditure on Agri. & Allied Services, incl. Rural development (Rs. in crore) during Two Periods
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
15174.88 Crore
3029.39 Crore
2010-11
2014-15
Expenditure on Agri. & Allied Services, incl. Rural development (Rs. in crore)

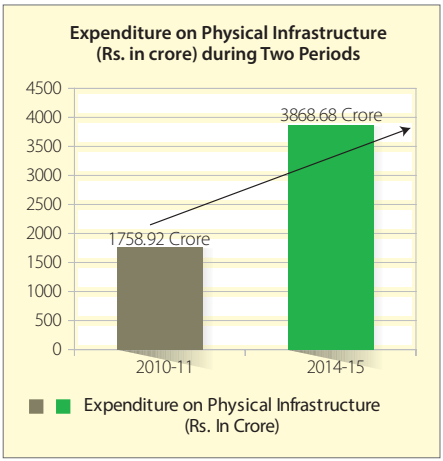

Expenditure on Physical Infrastructure (Rs. in crore) during Two Periods
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
3868.68 Crore
1758.92 Crore
2010-11
2014-15
Expenditure on Physical Infrastructure (Rs. In Crore)

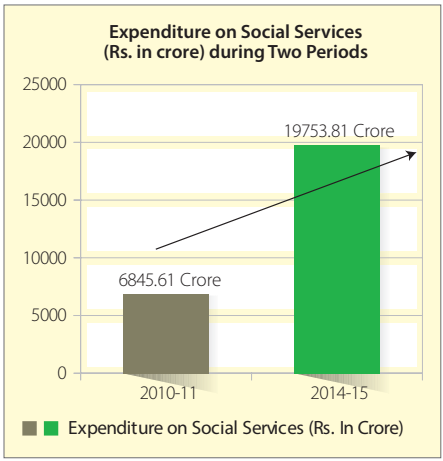

Expenditure on Social Services (Rs. in crore) during Two Periods
25000
20000
15000
10000
5000
0
19753.81 Crore
6845.61 Crore
2010-11
2014-15
Expenditure on Social Services (Rs. In Crore)

विषय-सूची

सुशासन एवं कानून-व्यवस्था	१५-२८
स्वास्थ्य	२९-३६
शिक्षा	३७-४६
उद्योग	४७-५४
लघु उद्योग	५५-६२
महिला एवं शिशु कल्याण	६३-६६
ग्रामीण विकास	६७-७४
शहरी विकास	७५-८२
संस्कृति, खेल-कूद व युवाकल्याण	८३-९२
कृषि, भूमि-सुधार, बागवानी, मत्स्य पालन तथा प्राणी संसाधन विकास	९३-१००
अल्पसंख्यकों का विकास	१०१-१०८
जंगलमहल, पहाड़ एवं चाय-बागान	१०९-११८
पिछड़े वर्ग का कल्याण व आदिवासियों का विकास	११९-१२२
आवासन	१२३-१२४
लोक निर्माण एवं परिवहन	१२५-१२८
पर्यटन	१२९-१३८

सुशासन एवं कानून-व्यवस्था

हमारे सत्ता में आने से पहले ही पश्चिम बंगाल की कानून-व्यवस्था सम्पूर्ण रूप से बिगड़ी हुई थी। महिलाओं की सुरक्षा से लेकर सड़क दुर्घटना तक या आम लोगों की दैनिक सुरक्षा की बात हो, किसी भी मोर्चे पर पिछली सरकार अपनी विश्वसनीयता साबित नहीं कर पायी थी। हमनें कहा था, 'बदला नहीं, बदलाव चाहिए', अर्थात् हमनें बंगाल का सम्पूर्ण परिवर्तन चाहा था। इसलिए सत्ता में आने के बाद सबसे पहले अपने इसी वादे को पूरा करते हुए कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए कदम उठाया गया। इसका परिणाम सुशासन के रूप में हुआ है। इन साढ़े चार वर्षों में विभिन्न प्रयासों के माध्यम से इस सुशासन को और गतिशील एवं संगठित बनाया गया है।

सिर्फ घोषणा ही नहीं, वास्तव में अनेकों कार्य किए हैं। आइए, उन सभी सांगठनिक प्रक्रियाओं के सम्पूर्ण परिणाम पर एक नज़र डालते हैं।

- प्रशासनिक बैठक एवं परिसेवा प्रदान कार्यक्रम : तृणमूल सरकार को सिर्फ कोलकाता की चहारदीवारी में कैद न करके लोगों के घर-घर तक पहुंचाने के लिए हमारी सरकार ने जिले-जिले में परिसेवा प्रदान कार्यक्रमों एवं प्रशासनिक बैठकों की शुरुआत की। इस बीच हमनें १०५ प्रशासनिक बैठकों एवं उससे अधिक परिसेवा प्रदान कार्यक्रमों का आयोजन किया है।

- भविष्य के कार्यों की अग्रिम योजना: वर्तमान सरकार ने ही सबसे पहले २०१४ से प्रत्येक विभाग में समयानुसार कार्य निर्दिष्ट कर वार्षिक प्रशासनिक कैंलेंडर को प्रकाशित किया।

- सामाजिक उत्तरदायित्व : लोगों की प्राप्य सेवा को सटीक समय पर उपलब्ध कराने को सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान सरकार ने 'द राइट टू सर्विसेज एक्ट' को शुरू किया है।

- सहज सेवा : हमारी सरकार आम लोगों के लिए ४३ मामलों में 'गजेटेड अधिकारी' द्वारा अनुप्रमाणन (ऐटेस्टेशन), ३१ मामलों में हलफनामा (एफिडेविट) एवं सरकारी कर्मचारियों के लिए ५ मामलों में अनुप्रमाणन/हलफनामा देने की परम्परा को खत्म किया है। अब से इन सभी मामलों में स्व-अनुप्रमाणन/स्व-घोषणा (सेल्फ ऐटेस्टेशन/सेल्फ-डिक्लेरेशन) ही पर्याप्त है। इस तालिका को भविष्य में और विस्तारित किया जाएगा।

- बंध का मार्ग बंद : वर्तमान सरकार के शासन में, कार्य-संस्कृति में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। कार्य नुकसान करनेवाले बंद के कारण पिछली सरकार के शासन में बड़े पैमाने पर नष्ट हुआ श्रम दिवस, वर्तमान में शून्य तक पहुंच गया।

- ई-गवर्नेंस : वर्तमान राज्य सरकार सूचना एवं प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स सम्पर्क को उपयोग में लाकर विभिन्न तथ्यों, शिकायतों के निवारण एवं सरकारी परिसेवा जैसे गवर्न्मेंट टू कस्टमर (क्र२क), गवर्न्मेंट टू बिजनेस (क्र२ए), गवर्न्मेंट टू गवर्नमेंट (क्र२क्र) इत्यादि को सीधे मूल उपभोक्ता तक पहुंचाने में सक्षम हुई है। इससे, एक ओर जहां सरकारी सेवा प्रदान करने में तेजी आई है, वहां सरकारी कार्यों में पारदर्शिता, दक्षता एवं सुविधा कई गुणी बढ़ी है।

इस उद्देश्य से माँ-माटी-मानुष की सरकार के विभिन्न विभागों ने कई कदम उठाए हैं। उसके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं:

- वित्त एवं आबकारी विभाग आई. एफ. एस. एम. (इंटिग्रेटेड फिनान्सियल मैनेजमेंट सिस्टम) के तहत
    - ई-वितरण (ऑनलाइन वित्त वितरण)
    - ई-सी.टी.एस (ऑनलाइन केंद्रीकृत कोषागार व्यवस्था)
    - ई-प्रदान (ऑनलाइन वित्त प्रदान)
    - ई-बिलिंग
    - एच.आर.एम.एस (ऑनलाइन मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली) इत्यादि

राजस्व प्रणाली और बेहतर बनाने में सक्षम हुए हैं।

इसके अलावा, विभाग की अन्य पहलों में निम्न उल्लेखनीय हैं :

- डब्ल्यू. एफ. टी. एस. (ऑनलाइन वर्क फ्लो-बेस्ड फाइल ट्रैकिंग सिस्टम)
- जी. आर. आई. पी. एस. (गवर्न्मेंट रिसिट्स पोर्टल सिस्टम)
- ई-टेंडरिंग
- ई. सी. एस. (इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम)
- ई-संलग्निकरण
- ई- आबकारी
- सी. ओ. एस. ए. (वेतन एकाउंट का कम्प्यूटराइजेशन) इत्यादि।

पूरी अर्थव्यवस्था और भी पारदर्शी हुई है।

- उद्योग एवं वाणिज्य विभाग 'शिल्प साथी' ई-गवर्नेंस के माध्यम से निवेशकों को हर प्रकार का सहयोग प्रदान कर रहा है।
- इसके अतिरिक्त सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग कागज-विहीन कार्यालय के तहत ई-ऑफिस एवं ई-डिस्ट्रिक्ट तथा ऑनलाइन संलग्निकरण के लिए सम्पूर्ण राज्य एवं

जिला कलेक्ट्रेट इत्यादि में डी. एम. एस. (इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम) चालू किया गया है।

- इसके अलावा विभिन्न सेवामूलक परियोजनाओं को भी ई-गवर्नेंस के तहत शामिल किया गया है:
  - कन्याश्री वृत्ति प्रदान (महिला एवं शिशु कल्याण विभाग)
  - शिक्षाश्री वृत्ति तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति प्रमाणपत्र प्रदान करना इत्यादि सम्पूर्ण रूप से ई-गवर्नेंस द्वारा परिचालित है (पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं आदिवासी विकास विभाग)
  - युवाश्री भत्ता प्रदान करना (श्रम विभाग)
  - लोक प्रसार परियोजना में भत्ता प्रदान करना (सूचना एवं संस्कृति विभाग)
  - खाद्य साथी (खाद्य एवं आपूर्ति विभाग)
  - माटिर कथा (कृषि विभाग)
  - अल्पसंख्यक वृत्ति प्रदान करना (अल्पसंख्यक मामलों का विभाग)
  - १०० दिन के कार्य को मंजूरी (पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग), वृद्धावस्था भत्ता, विधवा भत्ता, विकलांग भत्ता प्रदान करना इत्यादि।

  सम्पूर्ण रूप से ई-गवर्नेंस द्वारा परिचालित है।

इसकी स्वीकृति हाथों-हाथ मिल गई है। तृणमूल सरकार ने ई-गवर्नेंस में अग्रणी भूमिका के लिए जिन पुरस्कारों को प्राप्त किया है, वे हैं:

- ई-रेडीनेस - के लिए डेटाकोएस्ट पुरस्कार
- डब्लू. एफ. टी. एस. (ऑनलाइन वर्क फ्लो - बेस्ड फाइल ट्रैकिंग सिस्टम) - के लिए सी. एस. आई. निहिलेन्ट पुरस्कार २०१३-१४
- वाणिज्य कर के मामले में ई-पहल हेतु राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार २०१४-१५
- ई-आबकारी के लिए स्कोच प्लैटिनम उत्कर्ष पुरस्कार २०१४ इत्यादि

इतना ही नहीं, हमारी सरकार प्रत्येक मामले में ई-गवर्नेंस की सुविधा आम-जनता तक पहुंचाने के लिए कृत-संकल्प है।

सुशासन एवं महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम :

- तृणमूल सरकार के समय विभिन्न नीतियों के निर्धारण एवं परियोजनाओं को तीव्र रूप से मूर्त रूप देने के लिए ९४ कैबिनेट मीटिंग एवं ५३ स्टैंण्डिंग कमिटी मीटिंग का आयोजन किया गया है, जबकि, पिछली सरकार के समय (२००६-२०११) ५९ कैबिनेट मीटिंग एवं ३० स्टैंण्डिंग कमिटी मीटिंग का आयोजन हुआ।

- इसके साथ ही माननीया मुख्यमंत्री ने प्रत्येक तीन महीने में एक के बाद एक राज्यस्तर के सभी विभागों एवं प्रत्येक जिलों के कार्यों की जानकारी लेकर आवश्यक निर्देश दिये हैं। इसके अलावा नियमित रूप से कार्यालय आधारित बैठकों का आयोजन भी किया गया है।

शांति व्यवस्था बनाना एवं कानूनी शासन की स्थापना :

- सम्पूर्ण पश्चिम बंगाल में आज कानून व्यवस्था लागू हुई है। जंगल महल से पहाड़ तक सभी स्थानों पर शांति विराजमान है।

- हावड़ा, विधाननगर, आसानसोल-दुर्गापुर, बैरकपुर एवं सिलीगुड़ी में हमने ५ नये पुलिस कमिशनरेट की स्थापना की है।

- तटवर्ती सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए पूरे राज्य में ८ नये तटवर्ती थानों की स्थापना की गई है।

- मानवीय दृष्टिकोण के साथ निरंतर सतर्कता रखते हुए लोगों की सहायता हेतु पुलिस व्यवस्था के परिचालन के लिए हमने कम्युनिटी पुलिसिंग पर विशेष बल दिया है। कोलकाता पुलिस ने ३ नई कम्युनिटी पुलिसिंग परियोजना यथा गोआल्ज, सम्पर्क एवं सुकन्या को शुरू किया है। आम जनता के साथ पुलिस के संबंध को सुदृढ़ करने के लिए जिलों में जंगलमहल कप, सुन्दरवन कप, हिमल-तराई-डुआर्स कप को प्रारम्भ किया गया है।

- इसके साथ ही राज्य में न्याय व्यवस्था को उन्नत बनाने के लिए ५१ महिला अदालतों के साथ कुल ८८ फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए गए हैं। ८ सीबीआई कोर्ट चालू किए गये हैं, जबकि और ३ कोर्ट शीघ्र ही चालू होंगे।

- कानून-व्यवस्था : राज्य में शांति एवं स्थिरता बनी हुई है। जंगलमहल एवं पहाड़ हशी-खुशी हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकोर्ड ब्यूरों (National Crime Record Bureu) के तथ्य के अनुसार कोलकाता महानगर महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर है। राज्य में महिलाओं के प्रति अपराध, डकैती, हत्या, चोट पुहंचाने जैसी घटनायें क्रमशः घटी है।

पश्चिम बंगाल के कानून-व्यवस्था में सुधार :

- वर्तमान सरकार के विगत साढ़े चार वर्षों के शासनकाल में पश्चिम बंगाल में कानूनी-व्यवस्था में अभूतपूर्वक सुधार हुआ है। National Crime Record Bureu के आंकड़ों के अनुसार पश्चिम बंगाल में विगत समय के साथ वर्तमान समय की तुलना करने या भारत के अन्य राज्य में घटे अपराध के साथ इस राज्य में घटे अपराध के साथ तुलना करने पर, सहज ही समझ में आता है कि पश्चिम बंगाल में कानून का राज स्थापित हुआ है।

पश्चिम बंगाल में आपराधिक घटना - वह समय और यह समय :

- सन् १९७७ से २००९ तक के समयकाल में पश्चिम बंगाल में कुल ५५,४०८ राजनैतिक हत्यायें हुई हैं - अर्थात् तब प्रतिदिन ५ राजनैतिक हत्यायें होती थीं। इसके साथ ही १९६७ से २०११ के बीच ४० राजनैतिक सामूहिक हत्या की घटनायें घटीं - जिनमें नक्सलबाड़ी, नेताई, राजारहाट, मरीचझापीं, साईंबाड़ी, सिंगुर, नन्दीग्राम, बानतला, नानूर, छोटो अंगारियां इत्यादि शामिल है।
- सन् २००६ से २०११ के बीच राज्य में भयावह अपराध की संख्या में करीब १०० फीसदी वृद्धि हुई थी, जबकि वर्तमान सरकार के शासन में २०११ से २०१४ के बीच, पिछले दिनों की तुलना में भयावह अपराधों की वृद्धि में ६० फीसदी की कमी आई है।
- सन् २००६ से २०११ के बीच राज्य में महिलाओं के प्रति घटनेवाले अपराधों की संख्या करीब १२७ फीसदी बढ़ी थी, जबकि वर्तमान सरकार के शासन में २०११ से २०१४ के बीच पिछले दिनों की तुलना में महिलाओं के प्रति घटे अपराधों की वृद्धि में ९६ फीसदी की कमी हुई है।

- बलात्कार जैसे घृणित अपराध वर्ष २०११ की तुलना में २०१४ में ३८ फीसदी कम हुए हैं। इसके साथ ही पार्क स्ट्रीट, कामदुनी जैसे मामलों में राज्य सरकार के कड़े कदम के कारण अपराधी पकड़े गये एवं उन्हें शीघ्र सजा हुई।
- उल्लेखनीय है कि महिलाओं के प्रति अपराध के मामले में पुलिस ने तेजी से चार्जशीट दायर किया। सालबनी में ४ दिन, बर्धमान में १० दिन एवं दक्षिण दिनाजपुर की घटना में २१ दिनों के भीतर चार्जशीट दायर करना अन्यतम उदाहरण है।
- जंगलमहल क्षेत्र में सिर्फ वर्ष २००९ एवं २०१० में ४०४ साधारण लोगों एवं ४८ पुलिस कर्मियों की हत्या हुई थी, लेकिन पिछले तीन वर्षों में जंगलमहल में इस तरह की कोई घटना नहीं घटी।
- वर्ष २००६ के जून महीने से २०११ के मई महीने के बीच राज्य में पुलिस द्वारा गोली चलाने की ३६५ घटनायें घटीं, जिससे ७० लोगों की मृत्यु एवं १०८ लोग घायल हुए। अब गोली चलाने की घटाना विरल है।

आपराधिक घटना - पूरे देश की तुलना में पश्चिम बंगाल

- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा वर्ष २०१४ में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार वर्ष २०१३ की तुलना में २०१४ में पूरे देश में आपराधिक घटनायें ८ फीसदी बढ़ी हैं। भारतीय दंड संहिता के तहत आपराधिक घटना सबसे अधिक मध्यप्रदेश एवं महाराष्ट्र (सम्पूर्ण देश का लगभग १९ फीसदी) में घटी हैं। इन राज्य की तुलना में पश्चिम बंगाल में आपराधिक घटनायें नगण्य हैं - मध्यप्रदेश की तुलना में ३२ फीसदी एवं महाराष्ट्र की तुलना में २५ फीसदी कम है।
- पूरे देश में सबसे ज्यादा बलात्कार की घटनायें मध्यप्रदेश एवं राजस्थान में घटी हैं। वर्ष २०१४ में पश्चिम बंगाल में घटी बलात्कार की घटना मध्यप्रदेश की तुलना में २४६ फीसदी कम एवं राजस्थान, उत्तरप्रदेश एवं महाराष्ट्र की तुलना में १३० फीसदी कम है।
- दिल्ली की तुलना में पश्चिम बंगाल में बलात्कार के घटनायें कम घटी हैं।

- इसके साथ ही दिल्ली शहर की तुलना में कोलकाता अत्यंत सुरक्षित है। वर्ष २०१४ में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार भारत के विभिन्न शहरों में घटे अपराधों (भारतीय दंड संहिता के तहत आपराधिक घटना) में २२.७ फीसदी दिल्ली में घटी, जबकि कोलकाता में मात्र ४.२ फीसदी घटना घटी। कोलकाता में मुम्बई व बैंगलुरु से काफी कम आपराधिक घटनायें घटी हैं।

ऐसे में यह कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में अब वास्तव में सुशासन कायम हुआ है।

वर्तमान में राज्य सरकार ने सभी प्रकार के अपराधों विशेष रूप से महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामले में शून्य सहनशीलता को अपनाया है।

इसी उद्देश्य से सम्पूर्ण राज्य में ८९ नये थानें स्थापित किए गये हैं। इसके अलावा ६५ महिला थाना को स्थापित किया गया है, जिनमें ३० महिला थानों ने कार्य करना शुरू कर दिया है।

साथ ही कोलकाता पुलिस के दायरे को भी विस्तारित किया गया है।

राज्य पुलिस में करीब डेढ़ लाख सिविक वालंटियरों एवं करीब साढ़े तीन हजार विलेज पुलिस वालंटियरों को नियुक्त करने के साथ करीब पचास हजार नये पदों का सृजन एवं करीब पांच हजार नये पदों को अनुमोदित किया गया है।

- मालिकाना आधार पर आवासीय परियोजना ''आकांक्षा'' (सरकारी कर्मचारियों के लिए) एवं ''प्रत्याशा'' (पुलिस कर्मचारियों के लिए) बनाने के लिए राज्य सरकार नि:शुल्क भूमि प्रदान की है।
- पुलिस कर्मचारियों की १५ वर्षों का कार्यकाल पूरा होने पर उनके लिए ''होम डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग'' की व्यवस्था की गई है।
- बेहतर प्रशासन के लिए न्यू अलीपुरदुआर जिला की स्थापना की गई है।
- सरकारी कर्मचारी के लिए प्रत्येक ५ वर्ष के अंतराल पर ''होम ट्रेवल कन्सेशन'' एवं प्रत्येक १० वर्ष के अंतराल पर विदेश भ्रमण की सुविधा के साथ ''लिव ट्रैवल कन्सेशन'' की व्यवस्था की गई है।
- राज्य प्रशासन के अधिकारियों की कार्यदक्षता को बढ़ाने के उद्देश्य से उनके लिए विदेश में प्रशिक्षण व्यवस्था की गई है। थ राज्य में जो युवा राष्ट्रीय एवं राज्यस्तर परीक्षा के माध्यम से प्रशासनिक पेशा से जुड़ना चाहते हैं, उनकी सहायता के लिए सॉल्टलेक के ए.टी.आई. में 'सिविल सर्विसेज स्टडी सेंटर' की स्थापना की गई हैं।

पेन्शन प्रदान :

- पेन्शन प्रदान के माध्यम से हमारी सरकार के विभिन्न विभागों ने पूरे राज्य में २३ लाख लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान किया है -
- राज्य का पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग प्रति महीने १९ लाख से अधिक लोगों को वृद्धावस्था भत्ता, विधवा भत्ता एवं विकलांग भत्ता प्रदान करता है।
- समाज कल्याण विभाग प्रति महीने १ लाख ६० हजार से अधिक लोगों को वृद्धावस्था भत्ता, विधवा भत्ता एवं विकलांग भत्ता प्रदान करता है।
- अनुसूचित जनजाति विकास विभाग प्रति महीने करीब १ लाख ३० हजार से अधिक अनुसूचित जनजाति के लोगों वृद्धावस्था भत्ता प्रदान करता है।

स्वास्थ्य साथी परियोजना :

- हमारी सरकार करीब ८० लाख सिविक पुलिस वालंटियरों, ग्रीन पुलिस वालंटियरों, सिविल डिफेंस वालंटियरों, प्रत्येक ग्राम पंचायत में विलेज पुलिस वालंटियरों, डिजैस्टर मैनेंजमेंट वर्क्स, आशा कार्यकर्ताओं, एस.एच.जी.एस, एनवीएफ/होमगार्ड, आईसीडीएस वर्क एवं सरकार के लिए ठेका/अस्थायी/दैनिक मजदूरों एवं उनके करीब ४ करोड़ परिवार के सदस्य के लिए ''स्वास्थ्य साथी'' परियोजना के माध्यम से स्वास्थ्य बीमा किया गया है। इस वर्ष यह १ अप्रैल से चालू होगी।
- इस परियोजना में परिवार की सदस्यों की कोई अधिकतम उम्र सीमा नहीं हैं एवं वर्ष में डेढ़ लाख रुपये एवं क्षेत्र विशेष में पांच लाख रुपये तक कवरेज की व्यवस्था है।
- राज्य सरकार ने इस परियोजना के खाते में वार्षिक एक हजार करोड़ रुपये व्यय निर्धारित किया है।

हॉकर साथी परियोजना :

तृणमूल सरकार शीघ्र ही हॉकर भाई-बहनों के लिए ''हॉकर साथी'' नामक एक नई सामाजिक सुरक्षा परियोजना का शुभारंभ करने जा रही है। इस परियोजना के अंतर्गत पहचान पत्र, भविष्य निधि (प्रोविडेंट फंड), साधारण एवं दुर्घटनाजनित मृत्यु के मामले आर्थिक सहायता, व्यवसाय के लिए भत्ता इत्यादि का सुअवसर होगा। विभिन्न नगरपालिकाओं में इसके लिए हॉकरों को जोड़ने का कार्य शुरु किया गया है।

माभै :

- पश्चिम बंगाल सरकार दिनांक ०१.०३.२०१६ से सूचना एवं संस्कृति विभाग में सूचीबद्ध (एक्रेडिएटेड) पत्रकारों के चिकित्साजनित एवं व्यक्तिगत दुर्घटना के बीमा के संबंध में सुविधा हेतु ''वेस्ट बंगाल हेल्थ स्कीम फॉर जर्नलिस्ट २०१६'' परियोजना को शुरू करने का निर्णय लिया है। हमारी सरकार ने इस परियोजना का नाम ''माभै'' दिया है।

इस परियोजना की विशिष्टता निम्न है :-

- ६५ वर्ष की उम्र तक सूचीबद्ध पत्रकार (यहां तक की सेवानिवृत हुए पत्रकार भी) के अलावा उनकी पत्नी/पति, पिता/माता, नाबालिक भाई/बहन, आश्रित, अविवाहिता/विधवा/विवाह विच्छेद बहन एवं संतान आदि इस परियोजना के अंतर्गत शामिल होंगे।
- सभी प्रकार की सरकारी अस्पताल, परीक्षा केंद्र के अलावा नगरपालिका/कॉरपोरेशन/अन्य स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा परिचालित स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल एवं सरकारी तालिका के अंतर्गत विभिन्न गैर सरकारी स्वास्थ्य सेवा प्रदानकारी संस्थाओं में चिकित्साजनित व्यय सरकार या सरकार की निर्दिष्ट संस्था वहन करेगी।
- सूचना एवं संस्कृति विभाग इस संबंध में सम्पूर्ण जांच करेगी एवं आनेवाली आदेश के माध्यम से इस परियोजना का विस्तारित विवरण शीघ्र देगी।

ठेका/अस्थायी/दिहाड़ी मजदूर की कार्य सुरक्षा :

राज्य सरकार ने ठेका/अस्थायी/दिहाड़ी मजदूरों की कार्य सुरक्षा को सुनिश्चित किया है एवं इस संबंध में कई निर्णय किये हैं :

- ६० वर्ष की उम्र तक उन्हें नौकरी से हटाया नहीं जाएगा।
- प्रति वर्ष ३ फीसदी दर से उनकी आय बढ़ानी होगी।
- ६० वर्ष की उम्र के पश्चात् उन्हें २ लाख रुपये का बेनिफीट प्रदान करना होगा।

- उन्हें स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत लाया गया है। इस बीमा परियोजना के तहत सामान्य बिमारी की चिकित्सा में डेढ़ लाख रुपये तक तथा महत्वपूर्ण बीमारी में पांच लाख रुपये तक चिकित्सा व्यय वहन किया जाएगा।
- नौकरी की अवधि तक निर्भरशील ग्रुप डी कर्मचारियों को अधिकतम बीस हजार रुपये एवं न्यूनतम दस हजार रुपये तथा ग्रुप सी के कर्मचारियों को अधिकतम २२,५०० रुपये एवं न्यूनतम ११,५०० रुपये प्रति माह वेतन निर्धारित किया गया है।
- इस संबंध में राज्य सरकार के अतिरिक्त ५०० रुपये खर्च होंगे। इसके अलावा अन्य सुविधाओं के संबंध में एक उच्चाधिकार समिति का गठन किया गया है। वे ३० अगस्त तक रिपोर्ट देंगे।

पितृत्व सह शिशु देखभाल अवकाश (Paternity-cum-Child Care Leave)

- हमारी सरकार ने इस बीच महिला कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश (मैटर्निटी लीव) १८० दिन एवं शिशु देखभाल अवकाश (चाइल्ड केयर लीव) ७३० दिन मंजूर किया है। हाल ही में राज्य सरकार सभी पुरुष कर्मचारियों के लिए ३० दिन पितृत्व सह शिशु देखभाल अवकाश मंजूर किया है।

बंगाल की माँ-माटी-मानुष की सहायता एवं शुभकामनाओं से आनेवाले दिनों में बंगाल और संगठित, अनुशासित एक नागरिक समाज को प्राप्त करेगा, जहां सौहार्द एवं सामंजस्य के मार्ग पर चलते हुए प्रशासन एवं विधि प्रणाली के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लोग जीने का सम्मान पायेंगे।

- कानून व्यवस्था की रक्षा के मामले में प्रशासन जिससे अच्छी तरह कार्य कर सकें, इसके लिए महत्वपूर्ण कदम उठाय गये हैं और उठाये जायेंगे।
- साधारण अपराध के अलावा ''साईबर क्राइम'' अब काफी महत्वपूर्ण हैं। इस ओर भी प्रशासन की विशेष नजर रहेगी।
- हम (तृणमूल दल) मानते हैं कि कानून कानून के ढंग से कार्य करेगा। (The law will take its own course)।
- प्रशासन पारदर्शिता एवं निरपेक्षता के साथ कार्य करे - माँ-माटी-मानुष की सरकार का यही उद्देश्य है।
- पुलिस कर्मचारियों के लिए मकान ('प्रत्याशा' एवं 'आकांक्षा' से शुरू) की संख्या और बढ़ाई जायेगी।
- पुलिस कर्मियों के परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य एवं शिक्षा की ओर विशेष नजर रखी जायेगी।
- कार्य के दौरान मृत कर्मचारी के परिवार के निकटतम सदस्य को नौकरी मिलेगी। सामाजिक उत्तरदायित्व के पालन के लिए प्रशासन ने इस बीच कांस्टेबलों के लिए १५ वर्षों तक कार्य करने के पश्चात अपने-अपने जिले (होम डिस्ट्रिक्ट) में पोस्टिंग का आदेश दिया है। यह सुविधा अन्य स्तर के पुलिस कर्मचारियों के लिए भी विस्तारित करने पर विचार किया जा रहा है।
- पुलिस बल के मैनपावर, इंस्फ्रास्ट्रक्चर एवं अन्य सुविधाओं की वृद्धि के लिए कदम उठाये जायेंगे। पुलिस प्रशासन के साथ जनसम्पर्क और घनिष्ठ एवं सुदृढ़ करने का प्रयास किया जाएगा।
- साम्प्रदायिक सद्भावना एवं अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को विशेष महत्व दिया जाएगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अन्य सम्प्रदाययुक्त सभी लोगों की सामाजिक सुरक्षा पर विशेष नजर दिया जाएगा।
- आमलोग सुरक्षित रहें एवं न्याय पायें तथा महिलाएं जल्द से जल्द न्याय पायें इस पर विशेष बल दिया जाएगा।
- माँ-बहन की सुरक्षा के लिए विशेष सेल तैयार किया जाएगा।

- साधारण पुलिस स्टेशन के साथ-साथ महिला पुलिस स्टेशन और ज्यादा से ज्यादा स्थापित किए जायेंगें।
- सिविक वालंटियर्स, एनवीएफ, होम गार्ड, विलेज पुलिस एवं डिस्ट्रिक्ट मैनेंजमेंट का जो लोग कार्य करते हैं उन्हें अधिक महत्व देकर मान बढ़ाया जाएगा।
- फास्ट ट्रैक कोर्ट एवं मानवाधिकार कोर्ट के उपर विशेष बल दिया जाएगा।
- कांस्टेबल की नौकरी में १० फीसदी सिविक वालंटियरों एवं होम गार्ड आवेदनकारियों में से चयन किया जाएगा।
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए आवासन, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी विभिन्न पैकेज चालू किए जाएंगे।
- वर्ज्य पदार्थों के निपटान, वर्ज्य पदार्थ के पुनर्व्यवहार एवं उससे उर्जा उत्पन्न करने की पहल की जाएगी।
- महिला पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ाई जायेगी।
- पहाड़-जंगल सहित पूरे बंगाल में कहीं भी कोई भेदभाव नहीं हैं, शांति चाहिये। शांति एवं एकता के वातावरण को बनाये रखने पर विशेष बल दिया जाएगा।
- नये पुलिस कमिशनरेट बनाये जायेंगे। इसके अलावा ६ नये जिलों (सुन्दरवन, कलिम्पोंग, बसीरहाट, बर्द्धमान-शिल्प, बर्द्धमान-ग्रामीण एवं झाड़ग्राम) तथा ३ नये महकमों (मिरिक, झालदा एवं मानबाजार) को गठित करने का निर्णय लिया गया है।
- प्रशासन को और अधिक तृणमूल स्तर पर ले जाया जायेगा।
- ब्लॉक स्तर तक जो प्रशासनिक बैठकें (१०५) की गई हैं उन्हें आनेवाले दिनों में और अधिक संख्या में किया जाएगा जिससे विकास और शीघ्र गति से लोगों तक पहुंच सकें।
- राज्य में शांति के शासक को और अधिक सुप्रतिष्ठित किया जाएगा।
- किसी प्रकार के दंगे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
- बंगाल दंगामुक्त बनेगा।

- जो लोग असामाजिक कार्यों में लगे हैं, पुलिस उनके खिलाफ कठोर कदम उठायेगी।
- आम लोगों के प्रति पुलिस का आचरण मानविक होगा।
- महिला सुरक्षा की ओर विशेष बल दिया जाएगा।
- प्रशासनिक स्तर पर पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व के साथ हम आमलोगों को सुशासन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे।

स्वास्थ्य

हमारा वादा था कि माँ-माटी-मानुष की इस सरकार का मुख्य दायित्व राज्य में सभी के लिए सुस्वास्थ्य की व्यवस्था करना है। कहां था, प्रसूति मृत्यु की दर को यथासंभव कम करूंगी। नवजात शिशुओं की मृत्यु की दर को भी कम करने की जी जान से कोशिश करूंगी। गरीब एवं ग्रामीण लोग बेहतरीन चिकित्सा पा सकें, इसके लिए सभी को उन्नत मान की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने का वादा था। हमने शपथ ली थीं कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अधिकांश चिकित्सा उपलब्ध होगी एवं महकमा स्तर पर इंटेंसिव केयर यूनिट की सुविधा दी जाएगी। हमारा लक्ष्य था विभिन्न स्तर पर अस्पतालों में आधुनिक उपकरणों की आपूर्ति करना एवं उन्हें परिचालित करने के लिए लोगों की नियुक्ति करना। हमने कहा था कि पांच वर्ष की भीतर हम स्वास्थ्य व्यवस्था को उन्नत बनायेंगे। प्रत्येक चिकित्सा कर्मी को अपने दायित्वों के प्रति सजग बनायेंगे।

हमारी प्रतिबद्धता थी - सभी के लिए स्वास्थ्य (Health for All) । हम आज गर्व के साथ कह सकते हैं कि सरकारी अस्पतालों में नि:शुल्क चिकित्सा व्यवस्था को शुरू कर हमने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है।

वादों को पूरा करने के अलावा काफी कार्य किया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधार हुआ है :

पिछले साढ़े चार वर्षों के दौरान स्वास्थ्य क्षेत्र के आधारभूत विकास में अकल्पनीय वृद्धि हुई है :

- अब राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में सभी के लिए अंतर्विभागीय (इंडोर) चिकित्सा नि:शुल्क उपलब्ध है। इसके साथ ही, राज्य के सरकारी अस्पतालों में भर्ती सभी लोगों को नि:शुल्क औषधि वितरित की जा रही है, जो कि एक अभिनव कदम है।

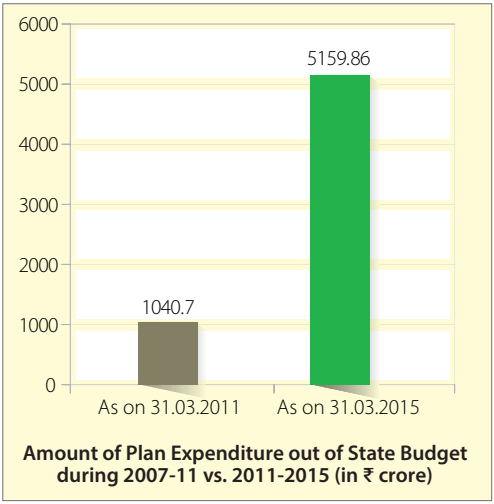

Amount of Plan Expenditure out of State Budget during 2007-11 vs. 2011-2015 (in ₹ crore)

- मात्र साढ़े चार वर्षों में १०९ सटीक मूल्य की औषधि दुकानों को खोला गया है, जहां विभिन्न औषधियों की कीमत पर ४८ प्रतिशत से ७७.२ प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है। अब तक इन दुकानों से करीब २ करोड़ लोग ५८५ करोड़ रुपये से अधिक की छूट पाकर लाभांवित हुए हैं। हमारी यह अभिनव पहल पूरे देश में मॉडल के रूप में चिह्नित हुई है।
- मई महीने के भीतर और ९ सटीक मूल्य की औषधि की दुकानें खोली जायेंगी।
- ७९ सटीक मूल्य के डायगोनस्टिक केंद्र को खोला गया है, जहां बाजार दर से ५० प्रतिशत से भी कम मूल्य (आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए पूर्ण रूप से

नि:शुल्क) पर एक्स-रे, डायलिसिस, सी.टी. स्कैन एवं एम.आर.आई. की जा रही है। मई महीने के भीतर और १४ सटीक मूल्य के डायगोनस्टिक सेंटर चालू किए जायेंगे।

- हमने विभिन्न जिलों एवं महकमो में ३६ सीसीयू (क्रिटिकल केयर यूनिट) एवं १७ एचडीयू (हाई डिपेंडेंसी यूनिट) स्थापित किया है। पश्चिम बंगाल एक मात्र राज्य है जहां महकमा स्तर पर सीसीयू/एचडीयू स्थापित करने के साथ इनमें सभी रोगियों की चिकित्सा सम्पूर्ण रूप से नि:शुल्क की जाती है। मई महीने तक और २ सीसीयू एवं ४ एचडीयू चालू हो जायेंगे।

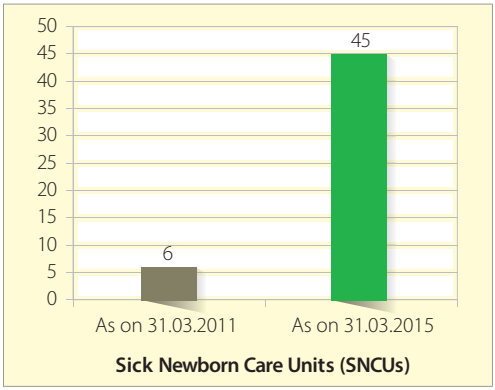

- हमनें इस बीच शिशु चिकित्सा में क्रांति लाकर ३०७ एसएनएसयू (सिक न्यू बॉर्न स्टैबिलाइजेशन यूनिट), ४९ एसएनसीयू (सिक न्यू बॉर्न केयर यूनिट) एवं १३ मेडिकल कॉलेजों में एनआईसीयू (नियोनटल इंटेंसिव केयर यूनिट) एवं ११ मेडिकल कॉलेजों में पीआईसीयू (पेडिएट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट) को चालू किया है।

- राज्य में ४१ मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल स्थापित किए गए हैं। ये अस्पताल छातना, ओंदा, बड़जोड़ा, विष्णुपुर, पुरुलिया, रघुनाथपुर, बालुरघाट, गंगारामपुर,

जलपाईगुड़ी, फालाकाटा, माल, इस्लामपुर, रायगंज, सिउड़ी, बोलपुर, रामपुरहाट, सालबनी, डेबरा, घाटाल, झाड़ग्राम, नयाग्राम, गोपीबल्लभपुर, नंदीग्राम, एगरा, पांसकुड़ा, सागरडीही, जंगीपुर, डोमकल, बारुईपुर, काकद्वीप, मेटियाबुरुज, डायमंड हार्बर, एम.आर. बांगुर अस्पताल, चांचल, बनगांव, बसीरहाट, श्रीरामपुर, आरामबाग, आसनसोल, कालना एवं उलुबेड़िया में निर्मित किए गए हैं।

- पश्चिम मिदनापुर के नयाग्राम, बांकुड़ा के बड़जोड़ा, ओंदा, छातना एवं मुर्शिदाबाद के सागरडीही एवं जंगीपुर में कुल ६ मल्टी-सुपर स्पेशलिटी अस्पताल इस बीच चालू हो गये हैं। हाल ही में और १५ सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बोलपुर, मेटियाब्रुज, झाड़ग्राम, सिउड़ी, रामपुरहाट, बालूरघाट, गंगारामपुर, डोमकल, रायगंज, घाटाल, काकद्वीप, विष्णुपुर, बारुईपुर, पांसकुड़ा, गोपीबल्लभपुर में चालू हुए हैं। मार्च महीने के भीतर कुल ३२ मल्टी सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल चालू हो जायेंगे। शेष इस वर्ष में चालू होंगे।

- राज्य में प्रतिष्ठानिक प्रसव (इंस्टिट्यूशनल डिलीवरी) की दर पिछले ४ वर्षों में ६८ फीसदी से बढ़कर ९० फीसदी तक पहुंच गई हैं। इस कारण, शिशु एवं मातृ मृत्यु दर में काफी कम आई हैं। ०-१ वर्ष के शिशु की मृत्यु की दर (आईएमआर) राज्य में ३१ से घटकर २७ तक पहुंच गई है।

- ९ एमसीएच हाब स्थापित हुए हैं। इनमें उलुबेड़िया एवं मुर्शिदाबाद अस्पताल का कार्य समाप्त हुआ है। कृष्णनगर एवं बांकुड़ा अस्पताल तथा कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में मई महीने तक कार्य समाप्त होगा।

- हमनें एस.एस.के.एम. अस्पताल में सरकारी क्षेत्र में पूर्वी भारत पहला पेडियाट्रिक कैथ लैब स्थापित किया है।

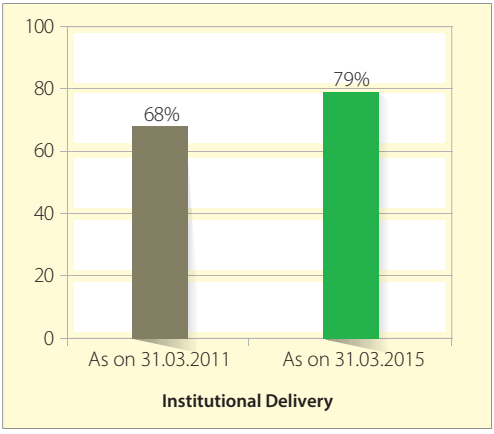

- कोलकाता में पूर्व भारत का पहला "कॉर्ड ब्लड बैंक" एवं "ह्यूमन मिल्क बैंक" - मधुर स्नेह हमने स्थापित किया है।
- ९ नये मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गये हैं - इन्हें कूचबिहार (२), रामपुरहाट, पुरुलिया, रायगंज, नदिया, डायमंड हार्बर, भांगड़ एवं कर्सियांग में स्थापित किया गया है।
- पिछले ४ वर्षों में अस्पतालों में २७ हजार से अधिक बेडों की वृद्धि हुई है। डॉक्टरी पढ़ने की सीटों की संख्या १३५५ से बढ़ाकर २९०० किया गया है। ३००० से अधिक नये डॉक्टरों एवं ३१०० नई नर्सों की नियुक्ति की गई हैं।

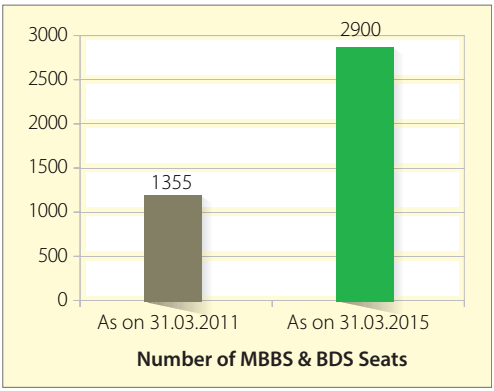

- "आयुष" (आयुर्वेद, योगासन एवं नैचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एवं होमियोपैथी) चिकित्सा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने जिले-जिले में पृथक रूप से स्थापित करने की पहल की है। प्रथम चरण में, बीरभूम, जलपाईगुड़ी, पश्चिम मिदनापुर, उत्तर एवं दक्षिण २४ परगना, दार्जिलिंग एवं नदिया जिलों में "आयुष" इसके पृथक आधारभूत ढांचे को तैयार किया जा रहा है। बाद के चरण में शेष जिलों में इस आधारभूत ढांचे को स्थापित किया जाएगा।

- गांवों में प्रत्येक घर में सरकारी स्वास्थ्य परिसेवा पहुंचाने लक्ष्य से कठोर परिश्रम कर हमारे गांवों की आशा (Accredited Social Health Activist) कठिन परिश्रम कर रही हैं। इन ASHA के परिश्रम को सम्मान देने एवं दूरदराज के क्षेत्र में पिछड़े लोगों तक सरकारी स्वास्थ्य परिसेवा पहुंचाने को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें साइकिल वितरित करने की कार्यसूची अपनाई गई है। पूरे राज्य में कुल ४५,२९९ ASHA सदस्याओं को साइकिल प्रदान की गयी।

आनेवाले दिनों में पश्चिम बंगाल के चिकित्सा व्यवस्था और उन्नत होगी। अन्य कई क्षेत्र में अनेकों नई सुविधाओं का सृजन होगा। हम विभिन्न प्रकार की नई पहल करेंगे। यहां उस तरह के कुछ कार्यों का उल्लेख कर रहे हैं। यहां यह ध्यान रखना जरूरी है कि इस तालिका के अलावा भी हम परिस्थितियों के अनुसार और भी अनेकों पहल करेंगे।

- स्वास्थ्य मनुष्य की अति मूल्यवान सम्पदा है। इसकी रक्षा करने का दायित्व एवं कर्तव्य हमारा है। हमारा लक्ष्य सभी के लिए स्वास्थ्य है।
- तृणमूल स्तर पर सरकारी स्वास्थ्य परिसेवा के प्रति लोगों का भरोसा पुनः बढ़ा है और आनेवाले दिनों में और बढ़ेगा।
- नये स्थापित सभी सुपर स्पेशियेलिटी अस्पतालों में उन्नत मान की परिसेवा को प्रदान करना सुनिश्चित किया जाएगा।
- सभी विशेषज्ञों विभागों वाले और मेडिकल कॉलेजों को स्थापित किया जाएगा। इससे मेडिकल की सीटों में वृद्धि होगी।
- कल्याणी में एम्स (AIMS) को स्थापित करने की पहल की गई है, जिसे तेजी से कार्यान्वित किया जा रहा है।

- वेब आधारित रिपोर्टिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इत्यादि युक्त एचएमआईएस की शक्ति वृद्धि।
- जंगलमहल, सुन्दरवन, चाय बागानों, वनबहुल एवं कोयला खदान क्षेत्रों में भ्रमणकारी मेडिकल यूनिट की व्यवस्था करना।
- राज्य के उपनगरों में स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए पीपीपी मॉडल का और उपयोग।
- जिला अस्पतालों में और विशेषज्ञों क्लिनिक स्थापित करना।
- सेक्स अनुपात को बरकरार करने के लिए ङ्घसेव द चाईल्ड गर्लफ परियोजना का और प्रचार करना।
- माँ एवं शिशु की स्वास्थ्य रक्षा हमारे सामने दो कठिन चुनौतियां हैं, जिनका हम दृढ़ता से मुकाबला करेंगे।
- शिशु मृत्यु दर, नवजात मृत्यु दर एवं मातृत्वकालीन मृत्यु दर को और कम करने का प्रयत्न किया जाएगा।
- राज्य स्तर एवं महकमा स्तर पर अस्पतालों में नई सुविधाओं जैसे आईसीयू, आईटीयू, बर्न यूनिट, ट्रॉमा केयर यूनिट एवं ब्लड बैंक इत्यादि को चालू करना।
- राज्य स्तर पर डायबिटिज, हाईपरटेंशन, कॉर्डियो-वैस्कुलर रोग, स्ट्रोक एवं कैंसर के उत्कर्ष केंद्रों को स्थापित करना।
- रोगी कल्याण समिति, स्वास्थ्य समिति एवं अन्य विकेंद्रीकरण संस्थाओं को क्षमता सम्पन्न करना।
- नर्सिंग एवं पैरामेडिकल शिक्षा के लिए स्कूल एवं कॉलेज स्थापित करना।
- सभी के लिए हेल्थ कार्ड।
- कम खर्च या बिना खर्च के उच्च मानक की स्वास्थ्य सेवा को उपलब्ध कराना हमारा मूल लक्ष्य है।
- राज्य के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित किये जायेंगे।
- कालाज्वर, लेप्रोसी, फाइलेरिया जैसी जानलेवा बीमारियों को जड़ से खत्म करने की कोशिश चल रही है और चलती रहेगी। डेंगू, मलेरिया समेत उसके जैसे जानलेवा रोगों के आक्रमण को रोकने के लिए आवश्यक व्यवस्था की जाएगी।

- जलवाही एवं पतंगवाही रोगों को कम पनपने दिया जाएगा।
- कोलकाता के अस्पतालों पर दबाव को कम करने के लिए जिला एवं ब्लॉक स्तर पर अस्पतालों को और सुदृढ़ किया जाएगा।
- अतिरिक्त दबाव कम करने के लिए और चिकित्सकों, नर्सों, स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी।
- स्वास्थ्य संबंधी कर्मियों आईसीडीएस एवं आशा सहित विभिन्न स्वास्थ्य कर्मियों के कार्यों की सुविधा को विशेष महत्व दिया जायगा।
- सभी के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था को और अधिक उन्नत एवं सुनिश्चित किया जाएगा।
- सरकारी एवं गैर सरकारी अस्पतालों में भ्रष्टाचार के शिकार लोगों के आरोपों के दर्ज करने एवं आरोपों की जांच कर उपयुक्त व्यवस्था करने के लिए एक उच्चाधिकार समिति का गठन किया जाएगा।
- मोबाइल फोन के माध्यम से पश्चिम बंगाल की समस्त ऐम्बुलेंस परिसेवा को एक छत के नीचे लाया जाएगा, जिससे किसी भी स्थान पर आवश्यकता के अनुसार कोई भी ऐम्बुलेंस पा सकें।

शिक्षा

तृणमूल सरकार का लक्ष्य था पश्चिम बंगाल में शिक्षा व्यवस्था के खोये हुए को पुनः प्राप्त करना। मैंने कहा था कि शिक्षा के राजनीतिकरण से रक्षा कर बंगाल में नवजागरण का नया ज्वार लायेंगे। हमारी योजना थी, विषय आधारित शिक्षकों की कमी को हम दूर करेंगे। उच्च शिक्षा में विभिन्न प्रकार के अनुसंधान करने का संकल्प लिया गया था। शपथ लिया था कि स्नातकों के रोजगार एवं पुराने ढंग से परिचालित व्यवस्था को उन्नत बनाकर शिक्षा क्षेत्र की नींव को मजबूत करेंगे। हमारा वादा था, बुनियादी आर्थिक घाटे को मिटाकर बंगाल में शिक्षा का आदर्श वातावरण तैयार करेंगे। निरपेक्ष, सभी के लिए सुलभ शिक्षा व्यवस्था को बनाये रखने के इस लक्ष्य के प्रति हम कितनी दूर पहुंचे हैं, उसे निम्नलिखित आंकड़ों के सापेक्ष में आप से विचार करने का अनुरोध करते हैं।

वादों को पूरा किया है :

- जिले-जिले में नया विश्वविद्यालय : वर्तमान के शासन में उच्च शिक्षा में सरकारी एवं गैर-सरकारी प्रयास से कुल १५ नये विद्यालय जोड़े गये हैं।

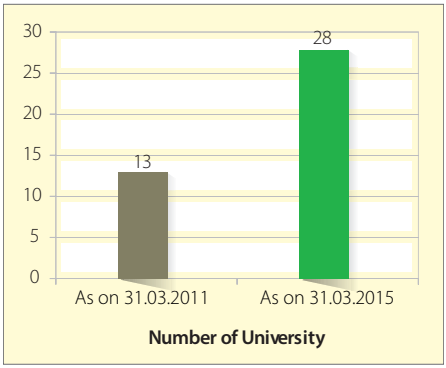

- वर्तमान सरकार के शासन में सरकारी पहल पर आसनसोल में काजी नजरूल विश्वविद्यालय, कूचबिहार पंचानन वर्मा विश्वविद्यालय, डायमंड हार्बर में पूर्वांचल का प्रथम महिला विश्वविद्यालय, बांकुड़ा विश्वविद्यालय, रायगंज विश्वविद्यालय एवं वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग, एजुकेशन प्लानिंग एंड एकाडेमिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना की गई है। संस्कृति भाषा के शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य में प्रथम संस्कृति विश्वविद्यालय संस्कृत कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है।

- गैर-सरकारी पहल पर सॉल्ट लेक में "टेक्नो इंडिया" विश्वविद्यालय, बोलपुर में "सीकॉम स्कील्स" विश्वविद्यालय, बेलघरिया में "एडामस" विश्वविद्यालय, खड़दह में "जे.आई.एस." विश्वविद्यालय, डायमंड हार्बर में "नेवटिया" विश्वविद्यालय, कोलकाता में एमआईटी यूनिवर्सिटी एवं यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेंजमेंट, उत्तर २४ परगना जिले में ब्रेनवेयर यूनिवर्सिटी जोड़े गये हैं।

- जिले-जिले में नया कॉलेज : आजादी के बाद जहां छत्तीस सरकारी कॉलेज स्थापित हुए थे वहीं हमारे साढ़े चार वर्ष के कार्यकाल में इस राज्य में ४६ नये कॉलेज स्थापित हुए हैं। इनमें ४२ कॉलेज चालू हो गये हैं।

- आजादी के बाद राज्य में सर्वोप्रथम महिलाओं के लिए सरकारी डिग्री कॉलेज की स्थापना हमने कोलकाता में अलीपुर हेस्टिंग हाउस में की हैं। इसका नाम

"सिस्टर निवेदिता कॉलेज" रखा गया है। इसके साथ ही करीब १४ करोड़ रुपये खर्च कर हमनें गवर्नमेंट गर्ल्स जनरल डिग्री कॉलेज स्थापित किया है।

- अगस्त २०१४ से राज्य में पहला हिंदी मीडियम कॉलेज बानारहाट में चालू हो गया है।

- राज्य में उच्च शिक्षा के इतिहास में सबसे बड़े विस्तार के फलस्वरूप पिछले साढ़े ४ वर्षों के करीब ३ लाख अतिरिक्त सीटों की वृद्धि के साथ-साथ राज्य में ग्रॉस नामांकन अनुपात वर्ष २०११ के १२.६ से बढ़कर वर्ष २०१४ में १७.५ तक पहुंच गया है। पिछले साढ़े ४ वर्षों में राज्य के स्कूलों एवं कॉलेजों में ५० हजार से अधिक रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति की गई है।

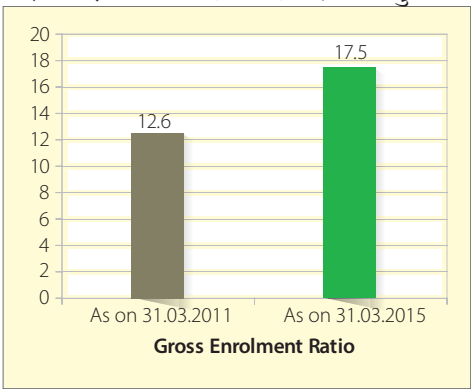

- उच्च शिक्षा में ओबीसी आरक्षण: साधारण श्रेणी के सीटों की संख्या में बिना कोई कमी किये (संस्थानों में सीटों की संख्या बढ़ाकर) उच्च शिक्षा में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए १७ फीसदी सीटों को आरक्षित किया गया है। इसके लिए राज्य को अतिरिक्त १,००० करोड़ रुपये व्यय करना पड़ा है। आरक्षण के परिणामस्वरूप पिछले वर्ष ५९,६१२ ओबीसी छात्र अंडर ग्रेज्युयेट एवं पोस्ट ग्रेज्युयेट कोर्स है भर्ती हुए हैं - जो पूरे राज्य में उच्च शिक्षा संस्थानों में भर्ती हुए कुल छात्रों का १०.६ फीसदी है।

- पिछले साढ़े चार वर्ष में राज्य में २५१० नये प्राथमिक एवं ३५४२ उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित किए गये हैं। १८१५ माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक स्तर में एवं ४६५ जूनियर हाई विद्यालयों को माध्यमिक स्तर में उन्नत किया गया है। राज्य में अभी ९९ बस्तियों के १ किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक विद्यालय एवं २ किलोमीटर दायरे में उच्च प्राथमिक विद्यालय है।

- तृणमूल सरकार चाहती है कि राज्य के प्रत्येक विद्यार्थी नियमित रूप से स्कूल जायें। इसे सुनिश्चित करने के लिए हमनें सभी को साइकिल प्रदान किया है। इस परियोजना का नाम हमनें "सबुज साथी" दिया है, क्योंकि परियोजना का अक्षरश: उद्देश्य हमारे समाज के सबसे हरे-भरे विद्यार्थियों तक विकास पहुंचना हैं। इसके अलावा साइकिल एक हरियाली, पर्यावरण हितैषी वाहन भी हैं। सम्पूर्ण राज्य में हम ४0 लाख साइकिल प्रदान करने की लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। इस बीच हमने २५ लाख साइकिल का वितरण कर दिया है, आनेवाले दिनों में और १५ लाख साइकिल वितरित करने का लक्ष्य है।

- विद्यालय शिक्षा में १५४ करोड़ रुपये खर्च कर प्रथम से लेकर चतुर्थ श्रेणी तक के सभी विद्यार्थियों हमने नि:शुल्क ब्लैक शू (काला जूता) प्रदान किया है। उन्हें अब खाली पैर स्कूल नहीं जाना पड़ेगा।
- इसके साथ ही विद्यार्थियों को नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक एवं दशमी कक्षा के लिए टेस्ट पेपर प्रदान किया गया है।
- प्रत्येक विद्यालय में लड़कों एवं लड़कियों के लिए पृथक शौचालय निर्मित किए गये हैं।
- मई २०११ के पहले राज्य में जहां मात्र ६५ पॉलिटेक्निक थे वहीं हमारे समय में राज्य में और ८१ नये पॉलिटेक्निक स्थापित हुए हैं अर्थात् शिक्षा सत्र २०१६ के प्रारम्भ में इस राज्य में पॉलिटेक्निक की संख्या १४६ हो गई है।
- मई २०११ के पहले राज्य में जहां मात्र ८० आई.टी.आई. थे, वहीं हमारे समय में राज्य में और १७० नये आई.टी.आई. तैयार हुए हैं अर्थात् शिक्षा सत्र २०१६ के प्रारम्भ में इस राज्य में आई.टी.आई. संख्या २५० हो गई है।
- मई २०११ के कुल जहां आई.टी.आई. एवं पॉलिटेक्निक में संयुक्त रूप से सीटों की सं. सम्पूर्ण राज्य में २५ हजार से कम थी, वह अब बढ़कर ७५ हजार से अधिक अर्थात् ३ गुणा बढ़ गई है।
- हमारे युवाओं के कौशल विकास (स्किल्ड डेवलपमेंट) के लिए राज्य सरकार ने एक विशाल कार्यसूची का शुभारम्भ किया है। इस कार्यसूची का नाम "उत्कर्ष बांग्ला" है। इस कार्यसूची की सफलता से एक असाधारण प्रतिभा संसाधन का निर्माण होगा, जो हमारे बंगाल को विकास के शीर्ष पर ले जाएगी। "उत्कर्ष बांग्ला" कार्यसूची का शुभारंभ होने से हमारी राज्य सरकार ने ८० आई.टी.आई. में पी.पी.पी. मॉडल पर पठन-पाठन का शुभारम्भ किया है, ५४ पॉलिटेक्निक में ई-लर्निंग की व्यवस्था को शुरू किया है।
- संस्थागत एवं परियोजना आधारित प्रशिक्षण कार्यसूची के अतिरिक्त राज्य के लोगों के लिए "उत्कर्ष बांग्ला" के माध्यम से अल्पावधि प्रशिक्षण (स्किल डेवलपमेंट) की व्यवस्था की जाएगी। इसका मूल लक्ष्य आत्मनिर्भरता को बढ़ाना एवं मजदूरी

आधारित आय को बढ़ाना है। इस परियोजना को मूर्त रूप देने के दायित्व "पश्चिम बंग सोसाइटी फॉर स्किल डेवलपमेंट" का होगा। राज्य सरकार के तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग तथा जिलास्तरीय अधिकारियों द्वारा आवश्यक सहायता की जाएगी।

- इस प्रयत्न के माध्यम से हम सम्पूर्ण राज्य में प्रत्येक वर्ष ३ लाख युवक-युवतियों को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। संस्थागत प्रशिक्षण के कार्यसूची के माध्यम से सम्पूर्ण राज्य में वर्ष में ३ लाख युवक-युवतियों को इस बीच तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा अर्थात् अब से प्रत्येक वर्ष कुल ६ लाख लोगों को हम प्रशिक्षण दे सकेंगे।
- रोजगार की परिधि को बढ़ाने एवं शिक्षा के अंत में रोजगार सुनिश्चित करने के लिए सिर्फ स्किल डेवलपमेंट ही नहीं हमनें प्लेसमेंट-लिंक्ड स्किल डेवलपमेंट की व्यवस्था शुरू की हैं। जैसे :
  - इलेक्ट्रॉनिक्स - सैमसंग के साथ
  - वस्त्र - रेमण्ड्स के साथ
  - रंग - बर्जर पेंट्स के साथ
  - वाहन - मारुति सुजुकी के साथ
  - रत्न एवं आभूषण - एसोचैम के साथ
  - उत्पादन - क्रेडाई के साथ एवं अन्य कई सेक्टर में।
- राज्य के युवक-युवतियों की दक्षता को बढ़ाने के लिए हमने जो पहल की है उसके फलस्वरूप तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में हमारे राज्य में एक के बाद एक दो बार अखिल

भारतीय दक्षता प्रतियोगिता (ऑल इंडिया स्किल कम्पिटिशन) में प्रथम स्थान हासिल किया है।

- पिछले साढ़े ४ वर्षों में हमारे राज्य में १५ लाख शिक्षार्थियों ने विभिन्न क्षेत्रों में दक्षता बढ़ाने का प्रशिक्षण लिया है। सिर्फ वर्ष २०१५ में इस तरह के साढ़े १० लाख विद्यार्थियों को "वेस्ट बंगाल स्टेट मिशन ऑन एम्प्लॉयमेंट" के माध्यम से रोजगार का अवसर मिला है।
- इसके साथ ही हमने राज्य स्किल डेवलपमेंट मिशन (West Bengal Skill Development Mission) एवं पश्चिम बंग सोसाइटी फॉर स्किल डेवलपमेंट (West Bengal Skill Development Mission) की स्थापना की है।
- कल्याणी में राज्य का पहला इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इंफॉरमेशन टेक्नोलॉजी (IIIT) स्थापित किया गया है। कल्याणी को हमनें एक नये एजुकेशन हब के रूप में तैयार किया है। यहां नया इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ एवं ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनाया जा रहा है।

आनेवाले वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में पश्चिम बंगाल काफी आगे जायेगा। विश्व दरबार में हमारी मेधा की ख्याति और बढ़ेगी। इसी लक्ष्य से निम्नलिखित कार्यों की योजना बनायी गयी है। हालांकि, हम वादा करते हैं कि इस तालिका के अलावा भी हम अनेकों कार्य करेंगे।

- बंगाल के सभ्यता एवं संस्कृति तथा सामंजस्य को प्रधानता देते हुए बंगाल के विद्वानों द्वारा लिखे गये जीवन दर्शनमूलक विभिन्न गंथों को विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा।

- रामकृष्ण मिशन के सहायता से संस्कृत बोर्ड शुरू किया जाएगा।
- स्कूल, कॉलेज एवं विश्वविद्यालय की संख्या और बढ़ायी जायेगी। योग्यता सम्पन्न निजी क्षेत्र को सुअवसर प्रदान किया जाएगा।
- कक्षा ९ से १२ तक के विद्यार्थियों को सभी विषयों की पाठ्य-पुस्तकों को नि:शुल्क प्रदान किया जाएगा।
- प्रथम से लेकर चतुर्थ कक्षा तक के विद्यार्थियों को जूता दिया गया है। वर्ष २०१६-१७ में कक्षा ५ से ८ तक विद्यार्थियों को जूता प्रदान करने का प्रयत्न किया जा रहा है।
- हमनें शिक्षा के क्षेत्र में काफी विस्तार किया है। आवश्यकतानुसार और विस्तार किया जाएगा एवं सभी स्थानों पर उच्चमान की शिक्षा को सुनिश्चित किया जायेगा।
- वर्तमान में निर्मित कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों के आधारभूत ढांचे को विकसित किया जाएगा। सरकारी कॉलेजों में विज्ञान विभागों में बुनियादी ढांचे को उन्नत बनाया जाएगा।
- नेशनल ऐसेसमेंट एंड ऐक्रेडियेशन काउंसिल एवं नेशनल बोर्ड ऑफ ऐक्रेडियेशन द्वारा बाध्यतामूलक रूप में उच्च शिक्षा केंद्र को स्वीकृत कराया जाएगा। उससे शिक्षा केंद्र का उत्कर्ष बढ़ेगा।
- निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर हमारे सभी कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में वाई-फाई कनेक्शन प्रदान किया जाएगा।
- प्रत्येक २ वर्षों में एक बार विद्यार्थियों को शीत वस्त्र प्रदान करने की व्यवस्था की जाएगी।
- अविकसित ब्लॉकों में ९वीं एवं १०वीं के विद्यार्थियों को मिड डे मील प्रदान किया जाएगा।
- विद्यालयों के शौचालय में पानी की व्यवस्था को उन्नत किया जाएगा।
- बंगाल के समस्त स्कूलों में चरणबद्ध तरीके से कम्प्यूटर प्रदान किया जाएगा।
- सभी स्कूलों में पेयजल परिशोधन यंत्र लगाया जाएगा।
- सभी पाठ्यपुस्तक डिजिटल रूप में इंटरनेट पर उपलब्ध होगी।

- सेंट जेवियर्स यूनिवर्सिटी बनायी जाएगी।
- प्रेसिडेंसी के द्वितीय कैम्पस को राजारहाट में चालू किया जाएगा।
- दार्जिलिंग में प्रेसिडेंसी का एक कैम्पस चालू होगा।
- दुर्गापुर एवं जलपाईगुड़ी में नेताजी सुभाष मुक्त विश्वविद्यालय चालू किया जाएगा।
- सभी निजी शिक्षा संस्थानों में पठन-पाठन एवं बुनियादी सुविधाओं के रखरखाव के लिए मॉनिटरिंग कमिटी स्थापित की जाएगी।
- शिक्षा क्षेत्र में और पारदर्शिता लाने के लिए ई-गवर्नेंस चालू किया जाएगा।
- और स्कूलों को प्राइमरी से माध्यमिक एवं माध्यमिक से उच्च माध्यमिक में उन्नत किया जाएगा।
- आईटीआई/पॉलिटेक्निक संस्थानों की संख्या बढ़ाई जाएगी। विभिन्न ब्लॉकों में यह पहल शुरू हो गई है। इसके अलावा तकनीकी शिक्षा एवं प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार वृद्धि हेतु मेगा इवेंट "उत्कर्ष बांग्ला" शुरू किया गया है, जिससे प्रत्येक वर्ष ६ लाख युवक-युवतियों को निश्चित नौकरी का सुअवसर मिलेगा।
- शेष सभी ब्लॉकों में आईटीआई स्थापित किए जायेंगे।
- और अंग्रेजी, हिंदी एवं आदिवासी मीडियम के मॉडल स्कूल स्थापित किए जायेंगे। महिलाओं के लिए आवश्यकतानुसार स्कूल, कॉलेजों की संख्या बढ़ायी जाएगी।

- चार प्रतियोगितामूलक परीक्षा के प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जायेंगे।
- प्राथमिक स्कूलों में ब्रतचारी तो थे ही, अब उच्च विद्यालयों में भी होंगे। इसके लिए शिक्षकों को उपयुक्त प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाएंगी।
- दार्जिलिंग में नेपाली कॉलेज शुरू होगा।
- विभिन्न कॉलेजों में चरणबद्ध तरीके से वाई-फाई सुविधा की जाएगी।
- निजी क्षेत्रों को नये कॉलेज खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- जिन सभी शिक्षकों के पास एम.फिल/पीएचडी के डिग्री है उन्हें अतिरिक्त वेतन वृद्धि प्रदान की जाएगी।
- विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी विद्या को पश्चिम बंगाल में अगली पंक्ति में लाने के लिए इन विषयों में सभी प्रकार के अनुसंधान के द्वार को खोला जाएगा।
- हिन्दी एवं उर्दू शिक्षा के प्रसार के लिए विभिन्न डिग्री कॉलेज शुरू होंगे।
- हिन्दी भाषी क्षेत्र में और हिन्दी मीडियम स्कूल एवं कॉलेज खोले जायेंगे।
- सहज सिलेबस बनाकर अल चिकी भाषा को चरणबद्ध तरीके से माध्यमिक स्तर तक उन्नत बनाए जायेगा।

उद्योग

वादा किया था, उद्योग में हरित क्रांति लाऊंगी। कहा था, निवेशकों के लिए विशेष व्यवस्था करूंगी, सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से उद्योगों की स्थापना के लिए उचित माहौल बनाऊंगी। केंद्र सरकारी एवं गैर-सरकारी उल्लेखनीय निवेश के लिए सभी प्रकार के कदम उठाना चाहा था। बंगाल में खोये हुए उद्योग के गौरव को वापस लाना हमारी कार्य योजना का एक विशेष अंश था। श्रमिकों के हितों की रक्षा करना एवं उद्योग स्थापित करने के लिए नवीन भूमि नीति का निर्धारण करना हमारा मूल उद्देश्य था। हमनें कहा था, जमीन के रिकॉर्ड को रखने के लिए ई-गवर्नेंस व्यवस्था रहेगी। वादा किया था कि सुविचारित, संतुलित, उपयुक्त अनुसंधान एवं समुचित सम्पर्क को प्रारम्भ करने का प्रयत्न करूंगी। कहा था, लौह-इस्पात उत्पादन, ऑटोमोबाइल एवं इंजीनियरिंग, परिवहन एवं पर्यटन उद्योग में आगे बढ़ेंगे। हमारा संकल्प था, चाय एवं जूट उद्योग के खोये हुए गौरव को वापस लाएंगे।

इन सभी वादों को पूरा करने में तृणमूल सरकार कितनी सफल हुई है, नीचे बता रही हूँ।

- वर्ष २०१५ में बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट (बीजीबीएस) का शुभारम्भ हुआ। वर्ष २०१५ एवं २०१६ में बीजीबीएस ने सफलता की एक असाधारण मिशाल पेश की है।

- वर्ष २०१५ में अत्यंत सफल बंगाल ग्लोबल समिट में २,४३,१०० करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव मिला है, जो आगामी ३ वर्षों में १ करोड़ लोगों के लिए रोजगार का सृजन करेगा।

- वर्तमान में उद्योग जगत में २ लाख २६ हजार करोड़ रुपये का निवेश मूर्त रूप लेने के मार्ग पर है। इसके साथ ही और ढाई लाख करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव आया है।

- वर्ष २०१०-११ तक बंद के कारण ९४ लाख श्रम दिवस नष्ट हुए थे, जो वर्ष २०१३-१४ में घटकर शून्य तक पहुंच गया।

- ऑनलाइन सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम को शुरू किया गया है। भारी उद्योग स्थापित करने के लिए जिन विभिन्न मंजूरियों की आवश्यकता होती है, उनके १४ तरह की मंजूरी को इसके तहत लाया गया है। इस प्रणाली से उद्योगों की स्थापना के लिए आवश्यक आवेदनों को जमा करने एवं उसके निष्पादन के साथ-साथ आवेदनों की जांच किस स्तर पर है, उसे इस व्यवस्था के माध्यम से जाना जा सकेगा। यह सब ऑनलाइन होगा।

इसके अंतर्गत निम्न व्यवस्थाएं की गई हैं :

- जमीन का म्यूटेशन एवं कंवर्सन
- ले-आउट प्लान का अनुमोदन
- कारखाना तैयार करने एवं उसे चालू करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण पर्षद की आवश्यक मंजूरी (Consent to Establish and Consent to Operate)
- अग्नि निरोधक प्रमाणपत्र (Fire License/Safety Certificate)
- भूगर्भ एवं भूपृष्ठ जल के उपयोग की अनुमति
- बिजली कनेक्शन की अनुमति
- वेस्ट बंगाल इंसेंटिव स्कीम का पंजीकरण

इसके अलावा अन्य कई व्यवस्थाएं :

- हमारा लक्ष्य उद्योगपतियों एवं निवेशकों के लिए औद्योगिकीकरण हेतु उपयुक्त वातावरण तैयार करना तथा सभी प्रकार की आवश्यक सहायता करना। यह नई ऑनलाइन व्यवस्था उसी नीति का प्रमुख हिस्सा है।
- इस उद्देश्य को लेकर हमनें सम्पूर्ण जानकारी से भरी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (Ease of Doing Business) पुस्तिका को प्रकाशित किया है।
- तृणमूल सरकार ने नई स्टार्ट-अप नीति, डिजाइन नीति एवं निर्यात नीति को चालू किया है।
- उद्योग हेतु कोर कमिटी एवं वाणिज्य प्रतिनिधियों को लेकर स्टियरिंग कमिटी गठित की गई है।

- दुर्गापुर के अंडाल में ग्रीनफील्ड काजी नजरूल इस्लाम एयरपोर्ट जनता की सेवा के लिए शुरू।
- कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के साथ मिलकर दक्षिण २४ परगना के सागरद्वीप में नये गहरे समुद्री बंदरगाह की परियोजना अपनाई गई है।
- आदिवासी एवं अनुसूचित जाति बहुल खदान क्षेत्र के सामग्रिक विकास एवं एक लाख से अधिक प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रोजगार के उद्देश्य से अनुमानित २०,000 करोड़ रुपये के निवेश से बीरभूम में देश के सबसे बड़े कोयला खदान देऊचा पाचामी देवानगंज हरिणशिंगा कोयला खदान परियोजना का शुभारम्भ किया गया है। इसकी संचित कोयला परिमाण २१0 करोड़ टन है। इससे निकाले गए कोयले का उपयोग ताप विद्युत केंद्रों में किया जाएगा।
- ऋषि बंकिम शिल्प उद्यान, सांकराइल फूड पार्क, जेम्स ऐंड ज्वेलरी पार्क, अंकुरहाटी, गोदापियासाल इंडस्ट्रियल पार्क, साहाचक इंडस्ट्रियल पार्क, बांकुड़ा में प्लास्टो स्टील पार्क, पुरुलिया में रघुनाथपुर स्टील ऐंड एलायेड इंडस्ट्रियल पार्क, बर्दवान के पानागढ़ में इंडस्ट्रियल पार्क, हावड़ा के उलुबेड़िया में इंडस्ट्रियल पार्क एवं खड़गपुर में विद्यासागर पार्क स्थापित होगा।
- जेएसडब्ल्यू सीमेंट के सालबनी सीमेंट कारखाना की स्थापना का कार्य शुरू हुआ है। इस कारखाने में खनिज सम्पदा को नष्ट ना कर एवं पर्यावरण के संतुलन बनाए रखते हुए विश्वस्तरीय सीमेंट तैयार किया जाएगा। वार्षिक २.४ मिलियन टन उत्पादन क्षमता सम्पन्न यह कारखाना आनेवाले दिनों में क्षेत्र के आर्थिक सामाजिक विकास एवं रोजगार के सृजन में विशेष भूमिका निभायेगी।

- राज्य में आईआईएससीओ की वार्षिक इस्पात उत्पादन क्षमता साढ़े ८ लाख टन से बढ़ाकर २९ लाख टन ले जाने के लिए इस बीच सेल ने १६ हजार करोड़ रुपये का निवेश किया है। इसके अलावा, सेल इस्पात उत्पादन को बढ़ाने के लिए और ४0 हजार करोड़ रुपये का नया निवेश करने जा रही है। इस मात्रा में किया गया निवेश पूरे देश में अन्यतम नजीर है।

- वृहद् एवं मझोले आकार के उद्योग के मामले में ऋण का परिमाण १ लाख ११ हजार करोड़ रुपये से बढ़कर १ लाख ९0 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

- लोडशेडिंग पश्चिम बंगाल में इतिहास बन गया है। उद्योग की मांग को पूरा करने के लिए पश्चिम बंगाल में विद्युत का अभाव नहीं है। वर्तमान में, पश्चिम बंगाल में विद्युत की कमी नहीं, बल्कि अधिकता है। पावर बैंकिंग के माध्यम से अब हम अन्य राज्यों में बिजली भेज रहे हैं। नई बिजली उत्पादन क्षमता को करीब ५000 मेगावाट बढ़ाने का कार्य हो रहा है। सागरदीघी एवं बैण्डेल के तापविद्युत केंद्र के साथ-साथ आज कटवा एवं रघुनाथपुर में नये केंद्र स्थापित हो रहे हैं।

- पश्चिम मिदनापुर के गोयालतोड़ में इंडस्ट्रियल पार्क, दक्षिण २४ परगना के बजबज में गार्मेंट पार्क, पूर्व मिदनापुर के हल्दिया में हल्दिया पार्क, नदिया में हरिणघाटा इंडस्ट्रियल पार्क प्रस्तावित है।

- सरकार से लेकर जनता सभी प्रकार के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सर्वांगींण स्वस्थ परिसेवा के लक्ष्य से पूरे राज्य में ई-डिस्ट्रिक्ट परिसेवा चालू हुई है।

- महत्वपूर्ण जनहितैषी परियोजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए सरकार के पास जमीन बेचने को इच्छुक लोगों की सुविधा के लिए सीधे जमीन खरीदने संबंधी नीति का शुभारम्भ।

- नई चाय पर्यटन नीति को तैयार किया गया है। चाय पर्यटन, चाय बागान में विविधीकरण लाना, स्थानीय निवासियों की नियुक्ति, चाय बागानों में जो स्थान उपयोग में नहीं आते हैं, उनका उपयोग कर स्थानीय लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था करना।
- उद्योगपति, उद्योग इकाई एवं उद्योग पार्कों द्वारा आवश्यक भूमि अधिग्रहण की सुविधा को विस्तारित करने के लिए पश्चिम बंगाल भूमि सुधार कानून, १९५५ की धारा १४ वाई में संशोधन।
- पूर्व मिदनापुर के नयाचक की ईको-टूरिज्म परियोजना एवं सौर विद्युत उत्पादन केंद्र की स्थापना के लिए राज्य सरकार कदम उठाएगी। इस प्रस्ताव में मत्यस्यजीवियों के लिए निवास एवं मछली पकड़ने के लिए उन्नत मान के उपकरणों की व्यवस्था की जा रही है।
- प्रौद्योगिकीजनित कारणों से हड़ताल के कारण हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा था। सरकार ने मजबूत कदम उठाया है, जिससे यह प्रतिष्ठान पुनः उठ खड़ा हुआ है।
- चर्मजनित सामग्रियों के लिए ४९.७६ लाख रुपये व्यय कर वर्ज्य पदार्थ नियंत्रण परियोजना एवं पम्पिंग स्टेशन की स्थापना की गई है।
- वर्ष २०१०-११ में राज्य में आईटी कम्पनियों की संख्या ५०० थी, जो अब ७९ फीसदी बढ़कर वर्तमान में ८९४ तक पहुंच गई है।
- आईटी उद्योग में वर्ष २०१०-११ में कुल निर्यात ८३३५ करोड़ रुपये का था, जो वर्ष २०१३-१४ में ६४ फीसदी बढ़कर १३,६८६ करोड़ तक पहुंच गया है।
- कल्याणी में राज्य में पहली बार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन ऐंड टेक्नोलॉजी की स्थापना हुई है।
- वर्ष २०१०-११ में आईटी सेक्टर में कर्मचारियों की संख्या ९०,००० थी, जो ६१ फीसदी बढ़कर वर्तमान में १,४५,००० है।
- आईटी क्षेत्र में नई पहल एवं नवजात कम्पनियों की सुविधा के लिए नैसकॉम के साथ मिलकर संयुक्त रूप से प्रारम्भिक गोदाम की स्थापना की गई है।
- ई-रेडीनेस में विशेष प्रयत्न के लिए राज्य को सम्माननीय डेटाकोयेस्ट पुरस्कार मिला है।

आनेवाले दिनों में पश्चिम बंगाल उद्योग के क्षेत्र में अग्रणी होगा। इस लक्ष्य को पाने के लिए लम्बा सफर तय करना होगा। जनता के विकासमुखी कार्यों को करने में तृणमूल सरकार कभी पीछे नहीं रहती है, इस बार भी नहीं रहेगी। कुछ कार्य, जिन्हें करूंगी ही, उसके बारे में नीचे बता रही हूँ। यह तालिका और बड़ी होगी इसमें कोई संदेह नहीं है।

- पानागढ़, विद्यासागर, हरिणघाटा एवं गोयालतोड़ में इंडस्ट्रियल पार्कों के बुनियादी ढांचे को और उन्नत बनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सुविधायुक्त और कई ऐसे नये पार्कों को तैयार कर निवेश को आकर्षित किया जाएगा। इसके अलावा बुनियादी विकास के उद्देश्य से निजी इंडस्ट्रियल पार्कों को स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कोरिडोर का कार्य इस बीच शुरू हो गया है तथा रघुनाथपुर अंचल को आनेवाले दिनों के इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में चिन्हित किया गया है। कोरिडोर तैयार करने का कार्य सम्पूर्ण किया जाएगा तथा कोरिडोर से सटे क्षेत्र में और इंडस्ट्रियल क्लस्टर का निर्माण सम्भव है या नहीं जांच की जाएगी।
- रसूलपुर एवं भोर सागर बंदरगाह निर्माण कर बंदरगाह निर्माण के संबंध में विशेष रूप से नजर रखी जाएगी। ये बंदरगाह पूर्वी भारत से बाहर एवं बाहर से पूर्वी भारत में नौवाहित माल की आपूर्ति करने की व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाएगा। ये बंदरगाह कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के परिपूरक के रूप में कार्य करेंगे। तटवर्ती क्षेत्रों को विकसित किया जाएगा।

- भारी-भरकम राशि के इंडस्ट्रियल फंड को तैयार कर उद्योग के बुनियादी निर्माण के कार्य को सहज करने की व्यवस्था की जाएगी। इस मामले में भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित नेशनल इंडस्ट्रियल इंवेस्टमेंट फंड की सहायता मांगी जा सकती है। इस कार्य में निजी भागीदारों को उत्साहित किया जाएगा। इसके परिणामस्वरूप, इंडस्ट्रियल पार्क क्षेत्रों में सड़क मार्ग, विद्युत, जलापूर्ति इत्यादि की बुनियादी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा।
- प्राकृतिक गैस का पर्याप्त संग्रह इस राज्य में होने पर गैस-चालित उद्योग निर्माण की व्यवस्था की जाएगी। कोलकाता, उसके आस-पास के अंचल, उपनगरों एवं पड़ोसी जिलों में सिटी गैस डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम तैयार किया जाएगा। सीएनजी चालित जन परिवहन की व्यवस्था शुरू की जाएगी।
- आईटी या उस तरह के मेधा संसाधनजनित उद्योग के प्रसार के लिए हम सर्वोच्च प्रयास करेंगे तथा इसके लिए विशेष सुविधा प्रदान करने के लिए आग्रह के साथ विचार करेंगे।

लघु उद्योग

लघु उद्योग के मामले में हमारी योजना विशेष नीति अपनाने का प्रयास करने की थी। लघु एवं मझोले उद्योग में निवेशों के लिए सहज ऋण प्रदान करने की व्यवस्था, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, कुटीर शिल्प से जुड़े श्रमिकों एवं शिल्पियों व बुनकरों के लिए सचित्र परिचय पत्र प्रारम्भ करना, लघु एवं कुटीर उद्योग के विकास के लिए क्लस्टर गठन इत्यादि कार्य को जोरदार तरीके से करने की भावना थी कहा था कि लघु उद्योग से जुड़े लोगों को वाध्यतामूलक ढंग से प्रोविडेंट फंड एवं स्वास्थ्य बीमा के तहत लाया जाएगा।

हम जो कहते हैं, वह करते हैं। तृणमूल सरकार अपनी बात पर कितनी खरी उतरी है, उस पर स्वयं विचार करें।

- एमएसएमई एवं टेक्सटाइल पॉलिसी २०१३-१८ : वर्ष २०१३ में चालू हुई इस पॉलिसी का उद्देश्य एक बिजनेस इको सिस्टम तैयार करना है जहां अति सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्योग बांछित गुणवत्ता एवं सटीक मूल्य के साथ आयें।
- अति सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्योग के क्षेत्र में सर्वाधिक ऋण प्रदान वृद्धि में देश में सर्वश्रेष्ठ।
- पिछले चार वर्षों में कुल ९१ हजार करोड़ रुपये ऋण प्रदान किए गये हैं। यहां उल्लेखनीय है कि वर्ष २००७-११ के दौरान ऋण प्रदान करने का परिमाण १६,७६४ करोड़ रुपये था।
- इन चार वर्षों में ५०,४०० से अधिक एमएसएमई यूनिट खोले गये हैं, जहां ४,५६,००० से अधिक रोजगार का सृजन हुआ है।
- पिछले चार वर्षों में ३२० क्लस्टर बनाये गये हैं, जहां उसके पहले के चार वर्षों में सिर्फ ४९ क्लस्टर थे।

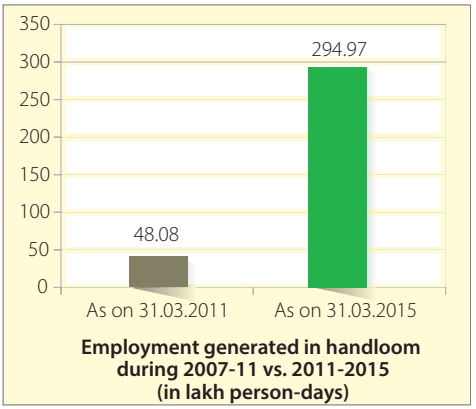

Employment generated in handloom during 2007-11 vs. 2011-2015 (in lakh person-days)

- अति सूक्ष्म, छोटे एवं मझोले उद्योगपतियों के मूलधन की रक्षा के लिए प्राथमिक रूप से २०० करोड़ रुपये के एमएसएमई वेंचर कैपिटल फंड का गठन किया गया है।
- राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बंगाल के पारंपरिक देशी सामग्रियों के प्रदर्शन एवं प्रचार के उद्देश्य से विश्व बांगला ब्रांड चालू हुआ है।
- कोलकाता एयरपोर्ट पर डोमेस्टिक एवं इंटरनेशनल दोनों टर्मिनलों में एक-एक तथा दक्षिणापण, राजारहाट, बागडोगरा एयरपोर्ट एवं नई दिल्ली में विश्व बांग्ला शोरूम खोला गया है। शीघ्र ही एक शोरूम एस्प्लानेड में खोला जाएगा।
- फिनांस क्लिनिक (एफसी) : उद्योगपति, बैंक एवं सरकार - इन तीन सूत्रों को एक स्थान पर लाने की एक महत्वपूर्ण पहल के तहत पिछले एक वर्ष में २८०० से अधिक उद्योगपतियों ने सुविधा एवं परामर्श हासिल किया है।

- टेक्नोलॉजी फेसिलिटेशन सेंटर (टीएफसी) : अति सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्योगों के मामले में आधुनिक प्रौद्योगिकी के संबंध में आंकड़ों को जाने के लिए यादवपुर विश्वविद्यालय के सीडीसीआरआई कैम्पस में एक सिंगल विंडो परिसेवा शुरू की गई है। टीएफसी की परिसेवा www.msmetfc.in साइट पर प्राप्त होगी। अभी तक करीब २,४०० उद्योगपतियों को प्रौद्योगिकी के संबंध में समाधान प्रदान किया गया है।
- यूनिक क्लियरेंस सेंटर (यूसीसी): हावड़ा, जलपाईगुड़ी, बर्द्धमान, पुरुलिया, हुगली एवं बांकुड़ा जिले में स्थित म्यूटेशन की तेजी से ट्रैकिंग एवं उद्योग के लिए जमीन परिवर्तन के उद्देश्य से की गई कोशिश से पिछले डेढ़ वर्ष में इस यूसीसी में १००० एकड़ से अधिक जमीन का म्यूटेशन एवं परिवर्तन सम्भव हुआ है।
- एमएसएमई इंवेस्ट पोर्टल: वर्ष २०१५ में आईआईएम कोलकाता के साथ मिलकर स्थापित किया गया यह पोर्टल उद्योगपतियों, निवेशकों एवं पेशागत विशेषज्ञों को जोड़े रखता है।
- रूरल क्राफ्ट हब : वर्ष २०१४ में यूनेस्को के साथ मिलकर स्थापित इस परियोजना के अंतर्गत ९ जिलों के २६ ग्रामों के १० तरह के शिल्पों के उद्देश्य से शिल्पियों को आत्मनिर्भर उद्योगपति के रूप में स्थापित करने के लिए इन ग्रामों को कारूक्षेत्र क्षेत्र के रूप में विकसित किया गया है। इन ग्रामों को पर्यटन केंद्र के रूप में भी तैयार करने के लिए बंगाल का रूरल क्राफ्ट हब बनाया जा रहा है। गत् २८ जुलाई

२०१५ को युनेस्को के मुख्य कार्यालय द्वारा चयन कर पेरिस में उनकी कारुकला प्रदर्शन को विरल सम्मान दिया गया है।

- राज्य सरकार के आह्वान के प्रत्युत्तर में केंद्र सरकार का वस्त्र मंत्रालय नदिया के शांतिपुर में ङ्गइंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजीफ स्थापित करने के लिए तैयार हुआ है। यह देश की पहली पंक्ति के तकनीकी शिक्षा प्रतिष्ठानों में अन्यतम होगा।

- उद्योगपति तैयार करने के लिए नए बिजनेस रियलिटी शो "एगिए बांगला" को बेहद सार्थक तरीके से आयोजित किया गया।

- लघु एवं मझोले उद्योग में निवेश करनेवालों के लिए ५ लाख रुपये तक सहज ऋण प्रदान करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ मिलकर एसएमई क्रेडिट कार्ड।

- सिनर्जी एमएसएमई : एक अनन्य सेवा प्रदान करनेवाला इवेंट है, जहां एक ही छत के नीचे अति सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्योगों से जुड़े सभी समाधानों को उद्योगपति प्राप्त करेंगे। ३५,५०० से अधिक एमएसएमई उद्योगपति को राज्यस्तर पर यह सुविधा मिली है। इस बीच हावड़ा, मालदा एवं सिलीगुड़ी में ३ सिनर्जी इवेंट हुए हैं।

- "सर्विस विद अ स्माइल" (एसडब्ल्यूएएस) नामक मोबाइल ऐप्प लघु उद्योग के क्षेत्र में उठते उद्योगपतिगण सीधे अपने निवेश एवं कार्य के संबंध में आवश्यक तथ्य का आदान-प्रदान, शिकायत दर्ज कराने एवं परामर्श को लेकर चर्चा कर सकेंगे।

- अति सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्योगपति की सुविधा के लिए एमएसएमई फैसिलेशन सेंटर (एमएफसी) एवं सिंगल एप्लीकेशन गेटवे (एसएजी) गठित की गई है।

- कांडारी (स्टेट लीडरशिप प्रोग्राम) : इस परियोजना के तहत आगामी ५ वर्षों में ११ सूक्ष्म उद्योगों (जैसे - जरी, अगरबत्ती, मछली का चारा, जूट संबंधी सामग्री, कार्पेट, वस्त्र, ढलाई, धातु शिल्प, पैकेट बंद प्रसंस्कृत खाद्य, रत्न व आभूषण तथा चर्म) के कारबार में बाजार की भागीदारी में ५ फीसदी वृद्धि करेंगे। इससे ४,१२,६२४ करोड़ रुपये का व्यवसाय होगा एवं ६१ लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा।

- शिल्पकारों एवं बुनकरों को सामाजिक सम्मान एवं सुविधा सुनिश्चित करने के लिए ५.६९ लाख "आर्टिसन आई.डी. कार्ड" एवं ५.३० लाख "वीभर आई. डी. कार्ड" प्रदान किया गया है।

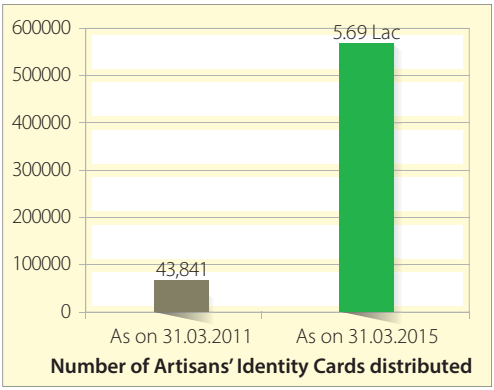

- रेडिमेड पोशाक, होजियरी सामग्री इत्यादि के उद्योगों के सुविधा एवं प्रचार के उद्देश्य से ९१५९ करोड़ रुपये के डेवलपमेंट कॉस्ट एवं २६,१०० करोड़ रुपये निवेश से इंटिग्रेटेड टेक्सटाइल डेवलपमेंट परियोजना चालू की गई है, जहां ६,०१,१०० लोगों को रोजगार मिला है।

- राज्य सरकार ने लघु एवं मझोले उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए झाड़ग्राम, विष्णुपुर, अलीपुरदुआर एवं पुरुलिया में ग्रामीण हाट का आयोजन किया। एक-एक हाट के पीछे करीब ३ करोड़ रुपये का व्यय हुआ।

जो किया है, सिर्फ उसी से संतुष्ट रहने की मानसिकता माँ-माटी-मानुष सरकार की नहीं है। लोगों के साथ मिलकर और काफी कुछ करना है। उसे पूरे मन से पूरा करेंगे। भविष्य की उस कार्य परियोजना के एक छोटे अंश को यहां लिखा गया है।

- आनेवाले पांच वर्षों में सभी सेक्टरों में काफी आर्थिक लाभ होगा।
- हाल ही में चालू स्टार्ट-अप पॉलिसी की सहायता से कई स्टार्ट अप कम्पनियों को सहायता प्रदान किया जाएगा।
- टेक्सप्रो : इस परियोजना के अंतर्गत तीन वर्ष के भीतर पीपीपी मॉडल पर गठित कई टेक्सटाइल पार्क एवं गार्मेन्ट हब स्थापित होंगें। इस परियोजना में कई करोड़ रुपये निवेश किया जाएगा तथा कई लाख लोगों को रोजगार मिलेगा।
- सरकारी स्वीकृति प्राप्त इंडस्ट्रियल हब: स्कीम ऑफ एप्रूव्ड इंडस्ट्रियल पार्क के अधीन अनेकों इंडस्ट्रियल हब स्थापित होंगे। इसमें कई हजार एकड़ में उद्योग स्थापित करने के लिए निर्दिष्ट जमीन का उपयोग होगा।

- आभूषण उद्योग, चर्म उद्योग, फाउंड्री एवं प्रोसेस्ड व पैकेज्ड खाद्य के लिए विशेष इंडस्ट्रियल पार्क (शिल्प तीर्थ) स्थापित किए जाएंगे।

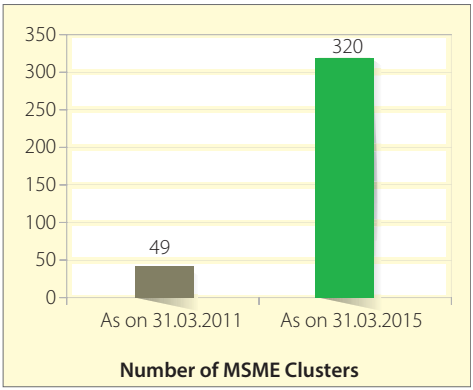

- सरकार बनाने के समय राज्य में ४९ क्लस्टर थे। पिछड़े साढ़े चार वर्ष में हमनें ३२० क्लस्टर का निर्माण किया है। आनेवाले पांच वर्षों में और कई नये क्लस्टर तैयार होंगे, जिससे कई लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इन सभी क्लस्टरों के सृजन में जो क्षेत्र भाग लेंगे, उनमें कार्पेट, जरी, जूट सामग्री एवं अगरबत्ती शामिल हैं।
- तांती साथी : अनेकों तांत यंत्र विहीन तांतियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें तांतयंत्र दिया जाएगा। इसमें करीब कई सौ करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।
- अनेकों शिल्पियों एवं कारीगरों को क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा।

- शांतिनिकेत में स्थापित विश्व सूक्ष्म बाजार में कई करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।
- मालदा के रेशम पार्क में कई करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।
- रूरल क्राफ्ट ऐंड कल्चर हब : यूनेस्को के सहयोग से कई करोड़ रुपये मूल्य की इस परियोजना के फलस्वरूप कई हजार लोक शिल्पियों की आय बढ़ेगी।
- देश एवं विदेश में नये विश्व बांग्ला शोरूम स्थापित होंगे।
- बानारहाट में यूको-टूरिज्म पार्क में कई हजार करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।
- गोदापियाशाल, विद्यासागर, सालबनी, साहाचक, रघुनाथपुर, हल्दिया एवं बरजोड़ा में सभी इंडस्ट्रियल हब का निर्माण कार्य समाप्त होगा।
- एमएसएमई वेंचर कैपिटल फण्डिंग प्रोसेस को और शक्तिशाली बनाया जाएगा।

महिला एवं शिशु कल्याण

हमनें तय किया कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा एवं महिला व शिशु सुरक्षा का विशेष ध्यान रखेंगे। हमारा उद्देश्य बाल विवाह, महिलाओं की तस्करी एवं शिशुओं की तस्करी जैसे अभिशाप को जड़ से खत्म करना था। हमनें समझा था कि शिशुओं के लिए पौष्टिक भोजन कितना जरूरी है।

समस्याओं के समाधान के प्रति तत्पर होना एवं परिस्थिति के अनुसार कदम उठाना तृणमूल सरकार की विशेषता है। इस मामले में कोई भटकाव नहीं हुआ है, उसे इसे पढ़कर समझ सकेंगे।

- कन्या शिशुओं के सामग्रिक विकास, उन्हें विद्यालयमुखी करने एवं उनके बाल विवाह को रोकने के लिए शुरू की गई अभूतपूर्व "कन्याश्री" परियोजना युनाइटेड नेशन्स, यूनिसेफ एवं इंग्लैंड के डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (डीएफआईडी द्वारा प्रशंसा प्राप्त है। इस परियोजना में अब तक ३३ लाख से अधिक कन्या शिशुओं को सूचीबद्ध किया गया है। १४ अगस्त को "कन्याश्री दिवस" के रूप में घोषित किया गया है।

- राज्य के २० जिलों में १,१४,०९६ आंगनबाड़ी केंद्र चालू हुए हैं। इनमें ६ महीने से ६ वर्ष उम्र तक के ६६.७३ लाख शिशु एवं १३.३६ लाख माताएं सेवा प्राप्त कर रही हैं।
- कुपोषण को दूर करने के लिए कुपोषित शिशुओं को रेडी टू ईट खाद्य प्रदान किया जा रहा है।
- राज्य के शिशु कुपोषण की दर वर्ष २०१०-११ में ३० थी, जो वर्तमान में घटकर १८.३७ पहुंच गई है।
- हमनें समाज के विभिन्न स्तर पर अवहेलित लोगों को विकास के मूल स्रोत में लाने के लिए कई कल्याणकारी परियोजनाओं का शुभारम्भ किया है। इनमें उल्लेखनीय है।
  - यौन कर्मी एवं तरस्करी का शिकार हुई महिलाओं के पुनर्वासन के लिए "मुक्तिर आलो" परियोजना।
  - काफी कम लम्बाईवाले लोगों को स्वावलम्बी बनाने के लिए "लिटिल स्टार"परियोजना।
  - एवं विपरीतलिंगियों के विकास के लिए "वेस्ट बंगाल ट्रांसजेंडर डेवलपमेंट बोर्ड" का गठन।
- स्टेट प्लान ऑफ एक्शन फॉर चिल्ड्रेन: वर्ष २०१४ के दिसम्बर महीने में राज्य सरकार ने यूनिसेफ की सहायता से २०१४ से २०१८ तक के लिए स्टेट प्लान ऑफ

एक्शन फॉर चिल्ड्रेन को प्रकाशित किया था। राज्य के शिशुओं के सर्वांगीण विकास परियोजना की नियमित जांच करना मूल लक्ष्य है। इसके साथ ही मालदा एवं पुरुलिया के लिए डिस्ट्रिक्ट प्लान ऑफ एक्शन फॉर चिल्ड्रेन तैयार किया गया है।

- शिशु आलय : शिशुओं के शारीरिक एवं मानसिक विकास में महत्वपूर्ण उनके जीवन के कुछ प्रारम्भिक वर्ष होतो हैं। शिशु विकास की इस धारणा को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त अर्ली चाइल्डहूड केयर एंड एजुकेशन (ईसीसीई) प्रदान करने के उद्देश्य से ङ्गशिशु आलयफ परियोजना चालू की गई है। वर्तमान में राज्य में एक हजार आईसीडीएस सेंटर को इस परियोजना के तहत लाया गया है। आनेवाले समय में राज्य के सभी आईसीडीएस सेंटर इसके तहत लाये जायेंगे।
- स्वावलम्बन : स्वावलम्बन गरीब, असहाय महिलाओं को वृत्तिमूलक प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की योजना है। पिछले साढ़े चार वर्षों में ४00 परियोजनाओं के माध्यम से १६ हजार से अधिक महिलाओं को इसके तहत लाया गया है। वर्तमान में यौनकर्मी एवं उनकी संतानों के पुनर्वासन के लिए एक विशेष स्वावलम्बन योजना चालू की गई है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि माँ-माटी-मानुष की सरकार माताओं एवं शिशुओं के बारे में हमेशा सोचती रहती है। बंगाल की महिलाओं एवं शिशुओं का सुख, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा भविष्य में बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। इसके लिए जो करूंगी, उसका सामान्य उदाहरण दे रही हूँ।

- कन्याश्री प्लस का शुभारम्भ होगा। इस परियोजना के माध्यम से कन्याश्री के तहत आनेवाली बालिकाओं के लिए उच्च शिक्षा एवं नौकरी की सुविधा प्रदान की जाएगी। परियोजना को और विस्तारित एवं प्रसारित किया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा लड़कियाँ यह सुअवसर पायें, उसके लिए पारिवारिक आय बढ़ायी जायेगी।

- महिलाओं के लिए एक राज्यव्यापी विशेष हेल्पलाइन नम्बर को चालू किया जाएगा।
- वूमन एम्प्लॉयमेंट बैंक तैयार किया जाएगा।
- महिला सशक्तिकरण एवं महिला रोजगार का ध्यान रखा जाएगा।
- शिशु एवं महिलाओं की तस्करी रोकने के लिए विशेष योजना बनायी गई है। आनेवाले दिनों में इस योजना को और मजबूत किया जाएगा।
- शिशुओं एवं उनकी माताओं के लिए पौष्टिक भोजन की व्यवस्था की जाएगी एवं उसके लिए राज्यस्तर पर एक मिशन प्रारम्भ किया जाएगा। इसमें सभी नोडल विभागों एवं यूनिसेफ की भूमिका होगी।
- असहाय महिलाओं को पेंशन की सुविधा दी जाएगी।
- आंगनबाड़ी कर्मियों के लिए सरकारी आवासन प्रशिक्षण केंद्र शुरू किए जाएंगे।
- आंगनबाड़ी कर्मियों को साइकिल प्रदान किया जाएगा।
- ईंट-भट्ठा एवं छींटमहल अंचल में आईसीडीएस स्थापित किया जाएगा।
- वूमन इम्पावरमेंट सेंटर को और शक्तिशाली बनाया जाएगा।
- ब्लॉक-ब्लॉक में आंगनबाड़ी केंद्र के भवन निर्मित किए गए हैं तथा और भी किए जायेंगे।

ग्रामीण विकास

हमनें गांवों के लोगों को सहज एवं सुविधाजनक जीवन प्रदान करने का आश्वासन दिया था। हमारे कार्यों की सूची में पंचायत पद्धति की सांगठनिक क्षमता बढ़ाना, गरीबी रेखा के नीचे के लोगों की आर्थिक सहायता प्रदान करना एवं सम्पर्क को बढ़ाना शामिल था। हमनें तय किया था कि जलापूर्ति व्यवस्था को उन्नत बनाएंगे एवं विभिन्न जल परियोजना को गठित करेंगे। गांवों के लोगों के लिए सुचारू शौचालय बनाना हमारी योजना के अंतर्गत था। हमनें तय किया था कि गांवों के लोगों को उपयुक्त कार्य करने की सुविधा प्रदान करेंगे।

ग्राम बांग्ला के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए तृणमूल सरकार ने इन वादों का पूरा पालन किया है।

- १०० दिन का कार्य : वर्ष २०१५-१६ में विगत वर्षों के कार्यों के आंकड़ों के आधार पर १०० दिन के कार्य के साथ अन्य विभागों के कार्य के समन्वय के माध्यम से आजीविका को विकसित करने के लिए पश्चिम बंगाल ने पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ स्थान हासिल किया है तथा केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय से पुरस्कार प्राप्त किया है। इसके साथ ही उत्तर २४ परगना जिले को सौ दिन के कार्य में असाधारण उपलब्धता हासिल करने के लिए पुरस्कृत किया गया है।

- वित्तीय वर्ष २०१४-१५ में हमने ४०१० करोड़ रुपये खर्च कर देश के प्रथम तथा साढ़े १६ लाख से अधिक श्रमदिवस का सृजन कर देश में द्वितीय स्थान हासिल किया है।

- पिछले साढ़े ४ वर्ष में राज्य में एक सौ दिन के कार्य में हमनें करीब १७,५८९ करोड़ों रुपये खर्च कर ८४.५१ करोड़ श्रमदिवसों का सृजन किया है। आनेवाले वर्ष के मई महीने के भीतर हम और ५००० करोड़ रुपये इस परियोजना में खर्च करनेवाले हैं।

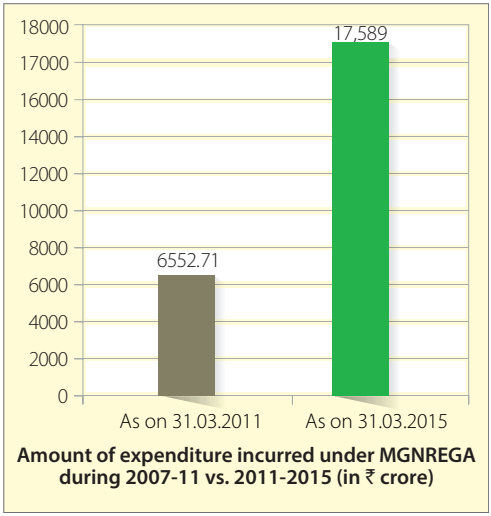

Amount of expenditure incurred under MGNREGA during 2007-11 vs. 2011-2015 (in ₹ crore)

- मिशन निर्मल बांग्ला : पिछले ढाई वर्ष में राज्य में २६ लाख से अधिक परिवारों के लिए शौचालय निर्मित हुए हैं। हमारे राज्य में वित्तीय वर्ष २०१४-१५ में "निर्मल बांग्ला" सैनिटेशन योजना के तहत करीब ८.५ लाख शौचालयों का निर्माण कर भारत सरकार से "देश में अव्वल" होने का ताज प्राप्त किया है। इस वर्ष दिसम्बर महीने तक ११ लाख से अधिक परिवारों में शौचालयों का निर्माण कर हम प्रथम स्थान पर हैं। आगामी मई महीने के भीतर और साढ़े ७ लाख से अधिक परिवारों में शौचालय निर्मित हुए हैं।

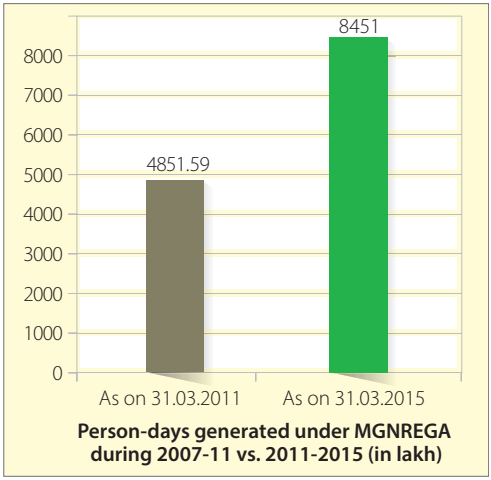

Person-days generated under MGNREGA during 2007-11 vs. 2011-2015 (in lakh)

- नदिया ने देश का पहला खुले में शौच विहीन जिला होने का पुरस्कार अर्जित किया है। पूरे देश में पारिवारिक शौचालय के निर्माण के क्षेत्र में अग्रणी ४ जिलों में से ३ हैं नदिया, उत्तर २४ परगना एवं हुगली - ये तीनों पश्चिम बंगाल में हैं।

- इंदिरा आवासन योजना के तहत वर्ष २०१५-१६ में पश्चिम बंगाल आवास निर्माण को मंजूरी प्रदान करने एवं निर्माण के लक्ष्य को पूरा करने में पूरे देश में पहले स्थान पर है।

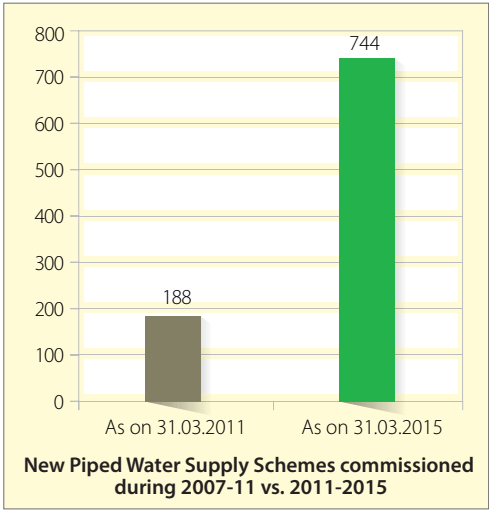

New Piped Water Supply Schemes commissioned during 2007-11 vs. 2011-2015

- पिछले साढ़े ४ वर्षों में दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में ७४४ नलवाहित जलापूर्ति परियोजना एवं करीब २१ हजार ट्यूबवेल स्थापित किए गये हैं, जिससे १ करोड़ ७० लाख लोग परिसेवा प्राप्त कर रहे हैं। वर्ष २०१६ के मई महीने के भीतर यह परिसेवा २ करोड़ लोगों तक पहुंच जाएगी।

- आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्र में ९१ फीसदी लोगों को शुद्ध पेय जल की आपूर्ति की जा रही है। आगामी मई महीने के भीतर ९७ फीसदी लोगों को शुद्ध पेयजल प्रदान किया जाएगा।
- पुरुलिया जिले में करीब १२०० करोड़ रुपये खर्च कर राज्य की अन्यतम बृहद पेयजल आपूर्ति परियोजना ङ्गजाईकोफ का कार्य शुरू किया गया है। इससे पुरुलिया जिले के ९ ब्लॉकों के १५ लाख लोग लाभान्वित होंगे।
- बांकुड़ा जिले में राज्य की एक बृहद नलवाहित पेयजल आपूर्ति परियोजना (११०० करोड़ रुपये) को हाथ में लिया गया है।
- न्यू टाउन एवं उससे सटे क्षेत्र के लिए हमनें एक १०० एमजीडी (मिलियन्स ऑफ गैलन्स पर डे) क्षमता सम्पन्न सरफेस वाटर आधारित जल परियोजना को शुरू किया है। हुगली नदी से पानी लाकर उसे शोधित कर इस परियोजना के प्रथम चरण में न्यूटाउन, सॉल्टलेक एवं नवदिगंत क्षेत्र में २० एमजीडी पेयजल की प्रत्येक दिन आपूर्ति की जायेगी। इस परियोजना में करीब ७२७ करोड़ रुपये व्यय होगा। इस

परियोजना के मूर्त रूप लेने से प्राथमिक चरण में करीब साढ़े चार लोग एवं भविष्य में करीब १५ लाख लोग लाभान्वित होंगे।

- पूरे राज्य में करीब २ लाख ७६ हजार एकड़ भूमि पर सिंचाई व्यवस्था प्रदान की गई हैं। वर्ष २०१६ के मई महीने तक और अतिरिक्त ६२,000 एकड़ भूमि को सिंचाई के अंतर्गत लाया जाएगा।
- पूरे राज्य में इन साढ़े चार वर्षों में २०१३ किलोमीटर बांध के विकास का कार्य समाप्त हुआ है। इनमें सुन्दरवन के आयला प्रभावित क्षेत्र में ५0 किलोमीटर बांध हैं। इसके साथ ही और २२५ किलोमीटर बांध के निर्माण का कार्य चल रहा है।
- "जल धरो, जल भरो" परियोजना के तहत पूरे राज्य में ५0,000 जलाशयों के निर्माण के लक्ष्य के संबंध में १ लाख ४0 हजार से अधिक निर्माण कार्य सम्पन्न हुए हैं।
- जंगलमहल क्षेत्र की मूल समस्या है भूमि की जल अवशोषण क्षमता में कमी एवं जमीन के असमान ढाल के कारण बारिश का पानी वह जाता है। इस समस्या के समाधान के लिए हम क्षेत्र में जल जमा रखने के लिए "जलतीर्थ" परियोजना के

तहत चेक डैम एवं जल संरक्षण टैंक तैयार करने में लगे हैं। पश्चिम मिदनापुर, पुरुलिया, बांकुड़ा एवं बीरभूम जिला में करीब ३२ हजार हेक्टर भूमि के लिए ५०० करोड़ रुपये खर्च कर ८३८ इस तरह की परियोजनाओं के मूर्त रूप प्रदान करने के कार्य को हमनें हाथ में लिया है, जिसके माध्यम से ४२४ परियोजनाओं का कार्य शुरू हो गया है।

- करीब ६५० करोड़ रुपये के व्यय से केलेघाई-कपालेश्वरी-बागाई खाल के पूर्व मिदनापुर के हिस्से में सफाई का कार्य सम्पन्न हुआ है। पश्चिम मिदनापुर जिले में इस बीच २१६ करोड़ रुपये के व्यय से नदी के ७५ किलोमीटर खनन एवं १५८ किलोमीटर सिंचाई नाले के खनन कार्य सम्पन्न हुआ है। शेष कार्य को शीघ्र समाप्त किया जाएगा। इस परियोजना में पूर्व मिदनापुर के मयना, भगवानपुर-१ एवं पटाशपुर-१ ब्लॉक के साथ पश्चिम मिदनापुर जिला के ११ ब्लॉकों के करीब ४ लाख लोग लाभान्वित होंगे।

- पांसकुड़ा-१ एवं २ ब्लॉक सहित पूर्व एवं पश्चिम मिदनापुर जिले में करीब १२ ब्लॉकों में बाढ़ नियंत्रण के लिए करीब २००० करोड़ रुपये के "घाटाल मास्टर प्लान" को मंजूरी दी गई है। इसके मूर्त रूप लेने से इस विशाल क्षेत्र में करीब १७ लाख लोग प्रतिवर्ष बाढ़ की समस्या से मुक्ति पायेंगे।

- पूरे राज्य में ११७ नये पुलों का निर्माण किया गया है। गंगासागर में तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए काकद्वीप-लॉट ८ में नई जेटी निर्माण किया गया है। इसके साथ ही ५० करोड़ रुपये के व्यय से पश्चिम मिदनापुर के जंगलमहल क्षेत्र में लालगढ़ ब्लॉक में आमकला ब्रिज के निर्माण का कार्य सम्पन्न हुआ है।

- ग्रामीण सड़क योजना के तहत ८००० किलोमीटर से अधिक सड़क का निर्माण हो गया है। इसके साथ ही और करीब २३०० किमी. सड़क का निर्माण अगले मई महीने तक सम्पन्न हो जाएगा।

बंगाल के गांवों के लोगों के चेहरे पर जो मुस्कान ला सकी हूँ, वह आनेवाले दिनों में मिट न जायें, उससे सुनिश्चित करने के लिए तृणमूल सरकार सदैव तत्पर रहेंगी। हमारा कार्य रूकेगा नहीं। क्या करूंगी, उसके कुछ सामान्य उदाहरण निम्न हैं :

गांव हमारे गर्व हैं। गांवों को अपने पैरों पर खड़ा करना एवं गांवों का सर्वांगीण विकास करना हमारा प्रथम लक्ष्य हैं। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए निर्दिष्ट योजना बनायी गई हैं तथा आनेवाले दिनों में और कार्य किये जायेंगे।

- ग्राम पंचायत, पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों के कार्यों में पारदर्शिता लाने एवं ग्रामों में जनसम्पर्क को और बढ़ाने के लिए निर्दिष्ट योजना बनाई जायेंगी।
- १00 दिन कार्य को महत्व दिया जायेगा तथा यह परियोजना समय पर राशि प्राप्त करें, उसकी व्यवस्था की जाएगी।
- मिशन निर्मल बांग्ला परियोजना को और आगे ले जाया जायेगा। इसके माध्यम से लाखों घरों में शौचालय का निर्माण किया जाएगा। जिन स्थानों पर जन समावेश होता है वहां कई हजार शौचालय निर्मित होंगे। ग्रामांचलों को वास्तव में कचरामुक्त स्थान के रूप में स्थापित किया जाएगा।
- हाउस फॉर ऑल परियोजना पर बल दिया जाएगा।
- अनेकों रास्तों के तैयार करने की सफलता पर बल दिया जाएगा।
- विश्व बैंक के सहयोग से आईएसजीपी प्रोग्राम के माध्यम से ग्राम पंचायतों में कई हजार सदस्यों एवं कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। ग्रामीण पंचायतों की सम्पदा

को बढ़ाया जाएगा। जियो-टैंगिंग पद्धति से मोबाइल फोन के माध्यम से पंचायतों के सभी कार्यकलापों को सूचीबद्ध किया जाएगा।

- सभी जल संरक्षण एवं कुआँ खनन के कार्य को समाप्त किया जाएगा तथा निर्धारित संख्या को और बढ़ाया जायेगा।
- ग्राम विकास परियोजना एवं कृषि विकास परियोजना के अच्छे परिणाम के उद्देश्य से उन्हें समकेंद्रित किया जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग इस समकेंद्रीकरण का केंद्र बिन्दु होगा।
- बृहद पाइप लाइन से जलापूर्ति परियोजना को पूरा किया जाएगा।
- सभी विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी में पेयजल आपूर्ति की जाएगी।
- बांकुड़ा, पुरुलिया एवं अन्य जल संकटवाले क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति परियोजना को सम्पूर्ण रूप से सुनिश्चित किया जाएगा।

शहरी विकास

सड़क सम्पर्क व्यवस्था की उन्नति, फ्लाईओवर पुलों इत्यादि के निर्माण हेतु संरचनात्मक काम करने का निश्चय हमने किया था। सोचा था कि नयी टाउनशिप बनाने की आवश्यकता है। शहर के लोग बेहतर जलापूर्ति की सुविधा पायें, उसकी ओर हमारी नजरें थीं। नगर परिवहन व्यवस्था में उन्नति की बात हमारे ध्यान में थी। सीपीएम के समय बिजली आपूर्ति की बड़ी खराब अवस्था थी - हमने निश्चय किया था इस इतिहास को बदल देने का। जनता की सेवा हेतु ई-गवर्नेंस स्थापित करने की योजना शुरू-शुरू में ही बनायी थी।

तृणमूल सरकार सही परियोजना हाथ में लेने में जितनी पारंगत है, उसे मूर्त्त रूप देने में उतनी ही सक्षम है। वादा करके उसे निभाने की विरासत के क्षेत्र में भी विचलन नहीं हुई।

- विधाननगर Municipal Corporation तथा हरिनघाटा, बुनियादपुर एवं डोमकल में नई Municipality गठित हुई।
- आसनसोल तथा हावड़ा Municipal Corporation का पुनर्गठन हुआ।
- अण्डाल में Golden City Industrial Township और कोलकाता लेदर कंप्लेक्स क्षेत्र में Sector VI Industrial Township का गठन हुआ।
- विगत साढ़े चार वर्षों में परियोजना खाते में Municipality-यों को ६७०० करोड़ रुपये प्रदान किए गए।
- पिछले साढ़े चार वर्षों के दौरान पौर संबंधी तथा शहरी विकास मंत्रालय ने बहुत सारी परियोजनाओं को मूर्त्त रूप दिया है। इनमें विशेष उल्लेखनीय हैं - कोलकाता ई.एम.बाईपास से जुड़े इलाके में "माँ" ओवर ब्रिज का निर्माण, फूलबाड़ी Land Customs Station का निर्माण, धापा से जुड़े इलाके में जयहिन्द जल परियोजना, गार्डेन रीच जल परियोजना, बाली, भाटपाड़ा और दमदम पौरसभा की Surface Water Supply परियोजना, बारानगर पौरसभा का Water Treatment Plant, गीतांजलि स्टेडियम एवं नजरूल मंच का कायाकल्प आदि।

- नगर सुन्दरीकरण के उद्देश्य से न्युटाउन में Eco Tourism Park-प्रकृति तीर्थ, बर्द्धमान में Mandela Park तथा डुमुरजला में Eco Park का निर्माण हमने किया है।
- एक ही साथ हमने ४-लेन वाले कमालगाजी फ्लाईओवर पुल का निर्माण कार्य समाप्त किया है। यह फ्लाईओवर ई.एम. बाईपास को कमालगाजी जंक्शन से जोड़ता है। १00 करोड़ की लागत से KMDA (Kolkata Metropolitan Development Authority) ने अढ़ाई वर्ष से भी कम समय में इस परियोजना को पूरा किया है।
- इसी दौरान गंगासागर - बकखाली, फुरफुरा शरीफ, तारापीठ-रामपुरहाट, पाथरचापरी एवं बक्रेश्वर Development Authority का गठन हुआ।
- पूरे राज्य में हमने ६ अलग-अलग Theme के ऊपर ६ Greenfield City का निर्माण किया है। बारुईपुर में उत्तम, शान्तिनिकेतन में गीतवितान, आसनसोल में अग्निवीणा, कल्याणी में समृद्धि सिटी एवं हावड़ा में स्पोर्ट्स सिटी के साथ-साथ सिलीगुड़ी में तिस्ता सिटी का निर्माण हमने किया है।
- राज्य परिवहन में नई गति आई है। दुर्गापुर में अण्डाल विमानपत्तन ने देश के सर्वप्रथम निजी उद्योग से निर्मित Greenfield Airport के रूप में अपनी पहचान

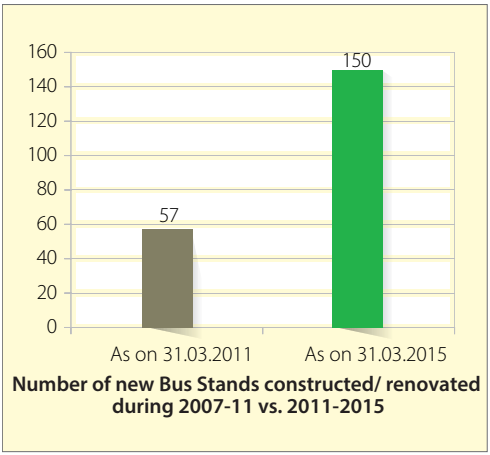

Number of new Bus Stands constructed/ renovated during 2007-11 vs. 2011-2015

बनाई है। दुर्गापुर से कोलकाता होते हुए नई दिल्ली तक उड़ान चालू हो गई है। कोलकाता से अण्डाल होते हुए कूचबिहार तक उड़ान चालू हुई है।

- यात्रियों की सुविधा के लिए : कोलकाता-मालदा, कोलकाता-बालुरघाट, कोलकाता-गंगासागर, कोलकाता-दीघा हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हो गयी है।
- AC बस सहित १५०० नई स्टेट बसें चालू हुई हैं। और २५० नई बसें खरीदी जा रही हैं। १५,००० No Refusal Taxi सड़क पर उतर गयी हैं। ४००० नई निजी बसों के परमिट प्रदान किए गए हैं।
- राज्य में कुल १६ अदद आई.टी. पार्क का निर्माण हुआ है, जिनमें से ८ का काम पूरा हो गया है।
- "लोडशेडिंग" आज पश्चिम बंगाल में इतिहास की बात हो गयी है। "सभी के घर में रोशनी" कार्यक्रम के अन्तर्गत मार्च, २०१६ के भीतर राज्य के हर परिवार में बिजली पहुँचाने का लक्ष्य पूरा होगा। वर्तमान में, उत्तर दीनाजपुर, जलपाईगुड़ी, अलीपुरदुआर, दक्षिण दीनाजपुर, मालदा, पूर्व एवं पश्चिम मिदनापुर के ७ जिलों में यह काम समाप्त हो चुका है। बाकी जिलों में मार्च, २०१६ तक यह काम पूरा करने हेतु काम तीव्र गति से चल रहा है।

- पश्चिम बंगाल में अभी बिजली की कमी नहीं है, बल्कि Power Banking के जरिए दूसरे राज्यों को हम अभी बिजली भेज रहे हैं। पिछले साढ़े चार वर्षों के दौरान हमारे राज्य में नई बिजली उत्पादन क्षमता लगभग ५000 मेगावाट स्थापित हुई है।
- बैण्डेल ताप विद्युत केन्द्र की ५ नं. इकाई के पुनर्नवीकरण एवं आधुनिकीकरण का काम पूरा हो गया है।
- मुर्शिदाबाद जिले में WBPDCL ६000 करोड़ रुपये से सागरदीघी ताप विद्युत केन्द्र की दो नई इकाइयाँ - ३ एवं ४ स्थापित करने का काम हाथ में लिया गया है। विगत १५ दिसम्बर को सागरदीघी ताप विद्युत केन्द्र की ३ नम्बर इकाई औपचारिक रूप से चालू हो गयी है। WBPDCL की यह इकाई ५00 मेगावाट ताप बिजली उत्पन्न करने वाली है।

बंगाल के नगर सारी दुनिया में एक दिन सम्मानित होंगे, यह तृणमूल सरकार का विश्वास है। परन्तु उसके लिए जरूरत है - कड़ी मेहनत, भरपूर जिम्मेदारी का पालन। बहुत कुछ करने का संकल्प है, जिनमें से कुछेक परियोजनाओं का खुलासा यहाँ किया गया है।

- दिल्ली के विज्ञान भवन में आधुनिक विश्व बांग्ला कंवेन्शन सेण्टर का निर्माण हो रहा है। उसके साथ एक बहुत बड़ा होटल भी है। इस सेण्टर में हजारों लोगों के बैठने की व्यवस्था है।

- इको पार्क में सोलर डोम का निर्माण हो रहा है।
- इको पार्क के करीब हेलीपोर्ट का निर्माण हो रहा है।
- हेलीपोर्ट के निकट ही इण्डोर स्टेडियम बनने जा रहा है।
- शहर के कई प्रमुख स्थानों पर कोलकाता द्वार का निर्माण किया जाएगा।
- इण्टरनेशनल, इण्टरस्टेट एवं इण्टरसिटी बस टर्मिनलस सहित कई कार्यक्रम हाथ में लिए जाएँगे।
- इको पार्क में आईफेल टावर सहित सात आश्चर्यों की प्रतिकृति।
- NKD के लिए ९ मंजिला विशिष्ट प्रशासनिक भवन का निर्माण किया जाएगा।
- WiFi Connection दुर्गापुर, आसनसोल, बर्द्धमान, सिलीगुड़ी, मालदा, उत्तर २४ परगना, दमदम, बैरकपुर, बोलपुर, कृष्णनगर, चन्दननगर, चुँचुड़ा इत्यादि स्थानों पर बढ़ाया जाएगा।
- जयगाँव में दूसरे इण्डो-भूटान गेट का निर्माण किया जाएगा।
- उल्टाडांगा से गड़िया तक बस रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम चालू किया जाएगा।
- प्रगति मैदान की तरह ही मिलन मेला में exhibition-cum-mela ground तथा Convention centre बनाया जाएगा।

- झिंझिरा बाजार से बाटानगर तक बजबज ट्रंक रोड के ऊपर फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा।

- दक्षिणेश्वर मन्दिर इलाके में पैदल यात्री तथा ट्रैफिक की भीड़ को नियंत्रित किया जाएगा। Sky walk बनाया जा रहा है। बन जाने पर आवागमन में सहूलियत होगी।

- और अधिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेण्ट का कार्य शुरू किया जाएगा।

- बायो-गैस बिजली के उत्पादन हेतु सॉलिड वेस्ट का इस्तेमाल किया जाएगा

- House for All के अन्तर्गत गरीब एवं आम लोगों के आवास के विषय पर महत्वपूर्ण ढंग से विचार किया जाएगा।

- सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काफी काम किया जाएगा। सेक्टर V की तरह सेक्टर VI का निर्माण कार्य चल रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी भवन का निर्माण हो जाने पर इस सेक्टर की और अधिक उन्नति अवश्यंभावी है।

- सूचना प्रौद्योगिकी में विशेष सुविधा और छूट देने के उद्देश्य से विभिन्न स्कीम चालू की जाएँगी।
- कई छोटे शहर एवं उपनगरी बनाई जाएगी, जिससे अनेक रोजगार उत्पन्न हों। यह निश्चित करने के लिए ढांचागत सुविधाओं पर अधिक बल दिया जाएगा।

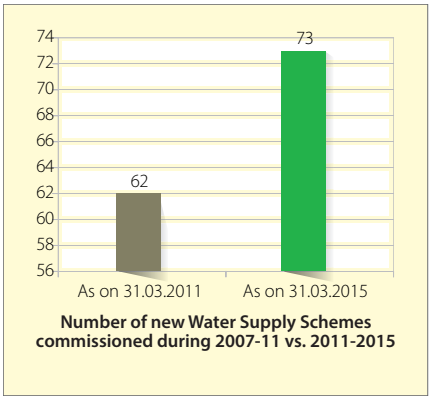

Number of new Water Supply Schemes commissioned during 2007-11 vs. 2011-2015

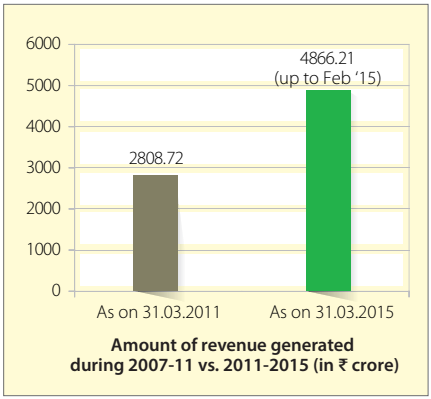

Amount of revenue generated during 2007-11 vs. 2011-2015 (in ₹ crore)

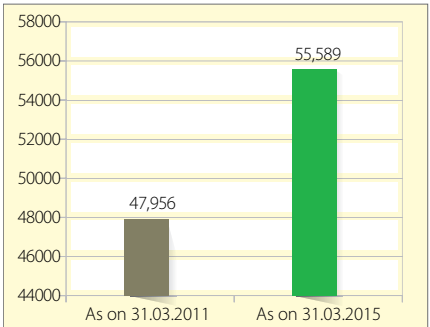

Number of houses constructed for Urban Poor under BSUP (Basic Services to the Urban Poor)during 2007-11 vs. 2011-2015

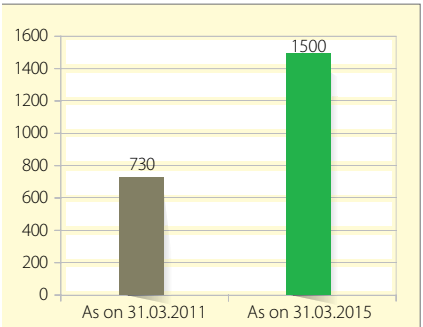

Number of new Bus routes introduced during 2007-11 vs. 2011-2015

संस्कृति, खेल-कूद व युवाकल्याण

दुनिया भर में बंगाल की संस्कृति अपना श्रेष्ठ स्थान पुनःअर्जित कर सके उसके लिए सभी तरह की कार्रवाई करने का प्रयास करने का हमने निश्चय किया था। रवीन्द्र-नजरूल की विचार धारा को पूरे विश्व में पहुँचाने का निर्णय लिया था। सिनेमा एवं नाटक के क्षेत्र में बहुत सारे विकासमूलक काम करने का निश्चय हमने किया था। नाट्य-कलाकारों को यथा-योग्य आर्थिक सहायता करने एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के चलचित्र उत्सव के आयोजन का निर्णय हमने उसी समय लिया था। असहाय लोक कलाकारों के लिए यथा-उपयुक्त आमदनी के स्रोत की व्यवस्था करने का भी निश्चय हमारा था। खेल-कूद में बंगाल पुनः आगे बढ़े, उसका दायित्व भी वहन करने का वादा किया था। आर्थिक दृष्टि से पिछड़े परिवार से आए प्रतिभावान खिलाड़ियों के लिए विशेष पैकेज की व्यवस्था की जाएगी, यह भी हमने बताया था।

भारत के बीच बंगाल को सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक स्थान पर प्रतिष्ठित करने के लक्ष्य की दिशा में ठोस कदम के साथ तृणमूल सरकार अग्रसर हो रही है।

खेल-कूद के क्षेत्र में भी पुराने गौरव के दिन लौटाने की तमन्ना थी। जो मिला है, उसकी तालिका बहुत छोटी नहीं है।

- लोक संस्कृति के पुनरुज्जीवन और क्रियान्वयन प्रसार के लक्ष्य की दिशा में "लोकप्रसार परिकल्पना" से ६० हजार लोक कलाकारों का आर्थिक उपार्जन सुनिश्चित हुआ है।
- बंगाल के विभिन्न लोक कलाकारों को पुनर्जीवित करने की दिशा में यह एक अनोखी परियोजना है। इस परियोजना के अन्तर्गत लोक कलाकारों को हर महीने ₹१००० की सम्मानित राशि मिलती है, जो सीधे उनके बैंक खाते में चली जाती है।

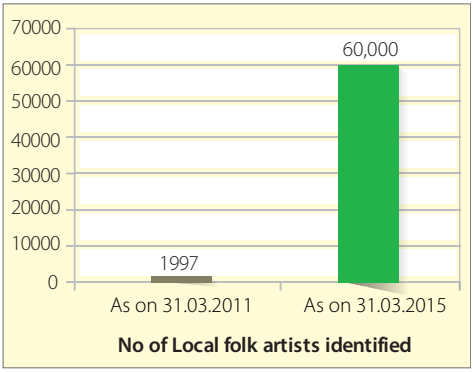

- ये लोक कलाकार अपनी कला प्रदर्शन के माध्यम से विभिन्न परियोजनाओं जैसे-कन्याश्री, युवश्री, शिक्षाश्री इत्यादि के प्रचार में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। इन परियोजनाओं ने बंगाल के लोक कलाकारों के बीच व्यापक उत्साह का संचार किया है।
- ७७,००० से भी अधिक लोक कलाकारों और आदिवासी कलाकारों ने सरकार की विभिन्न परियोजनाओं एवं उद्योग के संबंध में तथ्य प्रचार के लिए प्रायः २७००० प्रचारमूलक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया।
- वर्ष २००७ से २०११ के बीच १९९७ लोगों को स्थानीय लोक कलाकार के रूप में चिह्नित किया गया था। दूसरी ओर वर्ष २०११ से २०१५ के बीच चिह्नित किए गए लोक कलाकारों की संख्या ६०,००० के ऊपर थी, जो कि और बढ़ती जा रही है।
- नाट्य गोष्ठी तथा जात्रा कलाकारों को आर्थिक सहायता प्रदान : अभी तक ३०० नाट्य दल को ₹५०,००० की दर से आर्थिक सहायता मिली है।

- अपने-अपने क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल करने वालों को सम्मानित करने के लिए विभिन्न पुरस्कार चालू किए गए हैं।
- सिनेमा एवं टेलीविजन के कलाकारों एवं उनके परिवार के सदस्यों के लिए" ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस" चालू किया गया है।
- रिकार्ड समय के भीतर टालीगंज में टेक्निशियन्स स्टूडिओ का कायाकल्प एवं पुनर्निर्माण किया गया है।
- वर्ष २०१२ में छोटे पर्दे के धारावाहिक कलाकारों, यंत्रवादकों एवं इस उद्योग के सर्वांगीण विकास के लिए "पश्चिमबंग टेलि. अकादमी" बनाई गयी। इसके पृष्ठपोषण हेतु विभिन्न प्रयास किए गए हैं जैसे - टेलीविजन के कर्मचारियों के लिए ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस, टेली सम्मान प्रदान आदि।
- वर्ष २०११ में पश्चिमबंग काजी नजरूल इस्लाम अकादमी की स्थापना की गई, जिसका मूल उद्देश्य है - काजी नजरूल इस्लाम की बहुमुखी कार्यावली में अनुसंधान और विचारों एवं भावनाओं का प्रचार-प्रसार करना। नजरूलगीति को आधार बनाकर नियमित कार्यशालाओं एवं कार्यक्रमों का आयोजन। इसके साथ ही उनकी जन्म तथा पुण्यतिथि का पालन।
- वर्ष २०१२ में राज्य के आदिवासियों की आर्थिक-सामाजिक उन्नति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण हेतु बिरसा मुण्डा अकादमी की स्थापना की गयी। इसके प्रयास से सांस्कृतिक कार्यक्रम सारे सकम एवं मुण्डारी भाषा में विभिन्न आडिओ-सीडी बनाए गए हैं।
- राज्य के हिन्दी भाषी लोगों की सांस्कृतिक प्रगति के लिए २०१२ में पश्चिमवंग हिन्दी अकादमी का पुनर्गठन किया गया। एक समिति भी गठित की गयीं जो इसके विभिन्न कार्यकलापों की देखभाल करती है। विस्तृत परियोजना के लिए कई बैठकें भी आयोजित की गयीं। हिन्दी अकादमी का एक ग्रंथागार भी तैयार किया गया है, जो एक धरोहर है। ग्रंथागार में हैं - अमूल्य पुस्तकें एवं अनुसंधान दस्तावेज।
- वर्ष २०११ में राजवंशी भाषा की उन्नति, प्रचार-प्रसार तथा संरक्षण हेतु राजवंशी भाषा अकादमी की स्थापना की गयी। कूचबिहार में पुनर्गठित विक्टर महल में इसका कार्यालय है। संगोष्ठियाँ, सभाएँ, सम्मान कार्यक्रम आदि का आयोजन नियमित रूप से किया जा रहा है।

- पुरस्कार व सम्मान प्रदान : राज्य सरकार की ओर से बंगविभूषण व बंगभूषण पुरस्कार, संगीत महासम्मान, संगीत सम्मान, महानायक सम्मान, टेली पुरस्कार, कलाकार महासम्मान एवं शन्तिगोपाल व तपन कुमार पुरस्कार आदि प्रदान किए जाते हैं।
- सूचना व संस्कृति मंत्रालय नियमित रूप से बंगला, उर्दू, हिन्दी, संथाली व अंग्रेजी में "पश्चिमबंग" का प्रकाशन कर रहा है। कई विशेष अंक जैसे - "उन्नयनेर पथे मानुषेर साथ" होप टू रीयलिटी, लेट बंगाल शो द वे, पथ देखाबे पश्चिमबंग आदि का प्रकाशन इस दौरान किया गया।
- बसुमति पत्रिका को पुनर्जीवित किया गया। साहित्यिक पत्रिका ङ्गङ्घमासिक बसुमतिफ्फ का प्रकाशन नियमित रूप से हो रहा है।
- पुराने हाथ से लिखे तथा टाइप किए गए कार्ड के बदले संवाददाताओं के लिए लाया गया है - आधुनिक लेमिनेटेड प्लास्टिक कार्ड। २०१३ से उनके लिए सम्पर्क हेतु तीव्र व कार्यशील माध्यम के हिसाब से ई-मेल व एसएमएस पद्धति की शुरुआत की गयी है।
- सूचना व संस्कृति मंत्रालय से एक्रेडिटेशन कार्ड प्राप्त समस्त संवाददाताओं को परिवहन मंत्रालय के अधीन राज्य परिवहन संस्था द्वारा संचालित राज्य में समस्त बस व ट्रामों में निःशुल्क आवागमन सुविधा देना हमने सुनिश्चित किया है।
- जिलों के संवाददाताओं को प्रदान किए गए प्रेस कार्डों के पुनर्नवीकरण करने के लिए सूचना अधिकारी जिला सूचना व संस्कृति अधिकारी के पास क्षमता हस्तांतरित की गयी है।
- कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय चलचित्र उत्सव आज स्वाभाविक अर्थ में अंतर्राष्ट्रीय हो गया है। समूचे देश को देखते हुए, कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय चलचित्र उत्सव का पुरस्कार मूल्य सबसे अधिक है। कोलकाता चलचित्र उत्सव के प्रति जन साधारण के मन में आग्रह तथा उत्सव में सहभागिता दिन-प्रति दिन उत्तरोत्तर बढ़ी है।
- वर्ष २०१४ एवं २०१६ में गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेकर इस मंत्रालय द्वारा टैबलो (झांकी) राज्य के लिए सर्वोत्तम झांकी का पुरस्कार जीता है।
- विशिष्ट व्यक्तियों की जन्म व पुण्य तिथि की यादगार में नियमित रूप से स्मरण व श्रद्धांजलि-ज्ञापन किए जाते हैं। अभी तक इसप्रकार के १७५ कार्यक्रम आयोजित किए गए।

- बड़े पर्दे व छोटे पर्दे के २१, ००० से भी अधिक कर्मचारियों को ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस परियोजना तथा ग्रुप परसनल एक्सीडेण्ट इंश्योरेंस के दायरे में लाया गया। इनका मूल्य प्रति परिवार क्रमशः १.५ लाख तथा १.० लाख रूपये है।

- बाउल संस्कृति के विकास के लिए बाउल गान तथा बाउल कलाकारों के सर्वांगीण विकास का लक्ष्य रखकर हमने वीरभूमि के केन्दुली में जयदेव केन्दुली बाउल अकादमी की स्थापना की गयी।

- स्टेडियम, स्वीमिंग पूल इत्यादि के विकास के लिए ₹१०० करोड़ से अधिक का प्रावधान किया गया है।

- जो-जो काम पूरे हो चुके हैं, वे हैं - झाड़ग्राम स्टेडियम, शालबनी स्टेडियम, लेवंग गोरखा स्टेडियम, सिलीगुड़ी में कंचनजंघा स्टेडियम में फ्लड लाईट की व्यवस्था, विवेकानन्द युवभारती क्रीड़ांगन में नई फ्लड लाईट की व्यवस्था, पुरुलिया स्पोर्ट्स होस्टल, मिदनापुर स्वीमिंग क्लब, सुभाष सरोवर स्वीमिंग पूल एवं ईस्ट बंगाल, मोहनबागान, मोहम्डन स्पोर्टिंग क्लबों के मैदानों की उन्नति। शेष कार्य शीघ्र ही समाप्त किए जाएंगे।

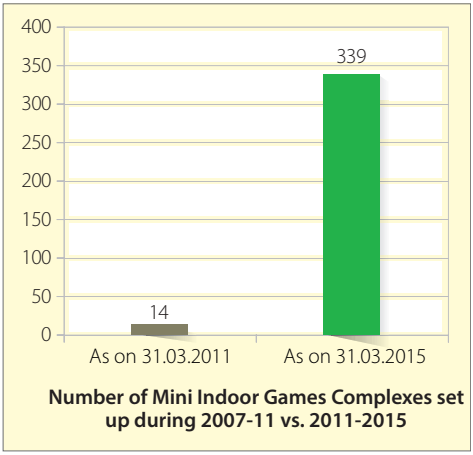

Number of Mini Indoor Games Complexes set up during 2007-11 vs. 2011-2015

- कोलकाता में सभी प्रकार के स्टेडियम की सुविधा जैसे - नेताजी इण्डोर स्टेडियम, रविन्द्र सरोवर स्टेडियम, विवेकानन्द युवभारती क्रीड़ांगन, सुभाष सरोवर स्वीमिंग पूल एवं किशोर भारती स्टेडियम के आधुनिकीकरण एवं उन्नति का दायित्व लिया गया है। खासकर विवेकानन्द युवभारती क्रीड़ांगन के कायाकल्प व उन्नति के लिए २५,००० प्लास्टिक बकेट सीट, शौचागार एवं नाले में सुधार, दो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के ड्रेसिंग रूम, जिमनेसियम को पुनः सुसज्जित करने का काम किया गया है। १७ वर्ष से कम उम्र के फीफा विश्व कप की आवश्यकतानुसार कृत्रिम घास के

स्थान पर प्राकृतिक घास की पिच तथा दो इसीप्रकार के अनुशीलन के लिए स्थान प्रदान किए गए हैं। दौड़ हेतु सिंथेटिक ट्रैक के बदले नए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक ट्रैक बनाया गया है।

- खेलों के लिए चार प्रकार के पुरस्कार दिए जा रहे हैं : १) आजीवन उपलब्धि के लिए ५ लाख रुपये का नकद पुरस्कार एवं एक स्मारक (२) क्रीड़ागुरु पुरस्कार : एक लाख रुपये नकद तथा एक स्मारक (३) बंगाल का गौरव पुरस्कार : एक लाख रुपये नकद तथा एक स्मारक (४) खेल सम्मान पुरस्कार : ५०,००० रुपये नकद पुरस्कार एवं स्मारक। ये सभी पुरस्कार २०१३ से हर वर्ष दिए जाते हैं।

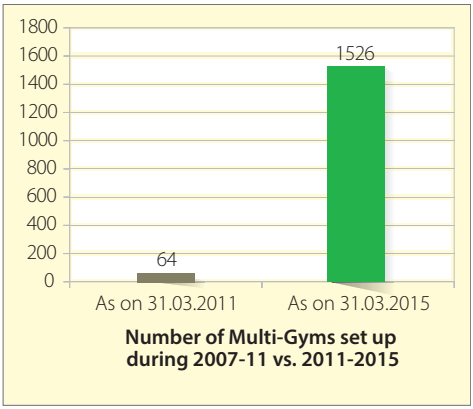

- जिला क्रीड़ा परिषद एवं महकमा क्रीड़ा परिषद का पुनर्गठन किया गया है तथा खेल-कूद की उन्नति के लिए जिला एवं महकमा स्तर पर रुपये का बजट प्रावधान किया जाता है।
- राज्य के बजट में परियोजना व्यय २००७-११ वर्ष में ₹१०३.९७ करोड़ से बढ़ाकर २०११-१५ वर्ष में ₹३४९.४३ करोड़ किया गया।
- ग्रामीण क्षेत्रों में खेल-कूद के प्रसार हेतु पूरे राज्य में ८३७४ क्लबों को खेल मंत्रालय द्वारा २८३ करोड़ रुपये खेल-कूद के सामानों की खरीद तथा ढांचागत सुविधाओं के विकास के लिए प्रदान किए गए।
- नई प्रतिभाओं की खोज के लिए सुन्दरवन में "सुन्दरवन कप", जंगलमहल में "जंगलमहल कप", उत्तरबंग में दार्जिलिंग-डूअर्स-तराई क्रीड़ा प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है।
- ९० करोड़ रुपये के व्यय से २३ अदद नये युव होस्टल बनाए गए हैं। ४८ करोड़ रुपये के खर्च से २० नए युव होस्टल की मरम्मत की गई है।

- १९५० मल्टीजिम तथा ४७५ मिनी इण्डोर गेम कंप्लेक्स के निर्माण में क्रमशः ₹४३ करोड़ एवं ₹५८ करोड़ खर्च किए गए।
- एवरेस्ट के विजयी सफल पर्वतारोहियों की उपलब्धि को स्वीकृति प्रदान करने के लिए हमने "Tenzing Norgay - Radhanath Sikdar Award" पुरस्कार एवं महिला पर्वतारोहियों के लिए "Chhanda Gayen Bravery Award" चालू किया है।

और भी बहुत कुछ करना बाकी है। आनेवाले दिनों में अंसख्य कामों के माध्यम से पश्चिम बंगाल की संस्कृति एवं खेल-कूद में स्वर्णिम युग वापस लाएँगे। कुछ का उल्लेख यहाँ किया गया है।

- लोक प्रसार कलाकारों एवं कला को और बढ़ावा दिया जाएगा।
- योग्य व्यक्ति को योग्य सम्मान व स्वीकृति से नवाजा जाएगा, जो इस दौरान चालू हो गया है।
- टॉलीऊड से लेकर टेलीऊड, यात्रा, नाटक, साहित्य व संस्कृति, संगीत, काव्य, लोक संस्कृति से शुरू करके कारु कला, चारु कला तक सर्वत्र सरकार ने विशेष कार्रवाई की है। आने वाले दिनों में इस क्षेत्र में और प्रयास किए जाएँगे।

- चारुकला, कारु कला एवं लोक कलाओं को और अधिक प्रकाश में लाने के लिए सरकारी कार्यक्रमों में इनके प्रदर्शन का समावेश किया जाएगा।
- मसलिन, सिल्क, ताँत आदि लुप्तप्राय उद्योगों का पुनरुद्धार किया जाएगा। पाट उद्योग, काँथा उद्योग, हापू गान, जारी गान, सारी गान इत्यादि लोक कलाओं को प्रसार के दायरे में लाया जाएगा।
- नाटक एवं अन्य मंच कलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विद्यालय एवं रेपर्टरी का निर्माण किया जाएगा।
- क्रीड़ा क्षेत्र में Talent Search Scheme तैयार की जाएगी। जिलों-जिलों में बांग्ला युव केन्द्र व ब्लॉक तक उसके प्रसार का प्रयास किया जाएगा।
- १७ वर्ष से कम आयु वाले खिलाड़ियों के लिए फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन २०१७ में किया जाएगा। इसके लिए विवेकानन्द युव भारती क्रीड़ांगन की उन्नति का साधन पैदा किया जा रहा है।
- दिसम्बर, २०१६ में इण्टरनेशनल प्रीमियर टेनिस लीग का आयोजन होगा। अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद का कार्यक्रम बंगाल में और ज्यादा हो, इसके लिए सरकार और प्रयत्नशील रहेगी।
- जहाँ स्टेडियम नहीं है, परन्तु होना जरूरी है, वहाँ स्टेडियम निर्माण के विषय पर विशेष महत्व देते हुए विचार किया जाएगा।

- अगले पाँच वर्षों में निम्न स्थानों पर स्टेडियम व क्रीड़ा हेतु ढांचागत सुविधाएँ तैयार की जाएँगी : बोलपुर, भातार, मेमारी, बुनियादपुर, अण्डा, इस्लामपुर, आमता, शान्तिपुर, राणाघाट एवं खातरा। इसके अलावा, अन्य जिलों में एकाधिक स्थानों पर आवश्यकतानुसार स्टेडियम बनाए जाएँगे।
- राजारहाट स्टेडियम कंप्लेक्स, उलुबेड़िया एवं दुमुरजला स्टेडियम तथा ईस्टबंगाल, मोहनबंगाल व मोहम्डन स्पोर्टिंग क्लबों के साथ Super leage club के आधुनिकीकरण, विकास एवं मरम्मत के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- धनधान्य, उत्तीर्ण स्टेडियम - अलीपुर में काम प्रगति पर है। इसप्रकार कोलकाता को दो स्टेडियम और मिल जाएँगे।
- रवीन्द्र सरोवर स्टेडियम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक उन्नत बनाया जाएगा।
- किशोर भारती स्टेडियम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक उन्नत बनाया जाएगा।
- हाबरा के बानीपुर में एक स्पोर्ट्स स्कूल निर्मित किया जाएगा।
- क्रीड़ा क्षेत्र में प्रसिद्ध व्यक्तियों को खेल सम्मान, बंगाल गौरव, क्रीड़ा गुरु इत्यादि सम्मान से नवाजा जाएगा।
- महिलाओं के खेल-कूद की दिशा में और ध्यान दिया जाएगा।
- विभिन्न एनजीओ के सहयोग से विकलांगों के लिए खेल-कूद का आयोजन किया जाएगा। विकलांग संस्थाएँ खेल-कूद को और आगे ले जा सकें, इसके लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- पूरे राज्य में अवस्थित स्टेडियमों का कायाकल्प और सौंदर्यीकरण किया जाएगा।
- युव होस्टल की उन्नति व गठन समाप्त किया जाएगा। और अधिक नए होस्टल बनाए जाएँगे और Consession दिए जाएँगे।
- समस्त माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय, कॉलेज एवं विश्वविद्यालयों में खेलकूद के विकास के लिए और आर्थिक सहायता दी जाएगी तथा खेलकूद व व्यायाम के क्षेत्र में स्कूल-स्कूल में ब्रतचारी को वापस लाकर उसके प्रचार-प्रसार के माध्यम से शारीरिक गठन के ऊपर विशेष जोर दिया जाएगा।
- समस्त ग्राम एवं शहर को और प्रोत्साहन देने के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या और बढ़ायी जाएगी।

- बंगाल के खेलकूद और उसके मनोन्नयन के लिए विशेष सहायता दी जाएगी।
- असहाय कलाकारों एवं क्रीड़ा विशेषज्ञों को सहायता प्रदान की जाएगी।
- प्रतिभावान कलाकारों तथा खिलाड़ियों के रोजगार की ओर ध्यान दिया जा रहा है और दिया जाएगा।
- क्रीड़ा क्षेत्र में विशिष्ट लोगों को उचित काम के अवसर बनाए जाएँगे।
- विभिन्न सांस्कृतिक कला कुशली तथा प्रेस मीडिया के साथ जुड़े व्यक्तियों के लिए Insurance चालू किया गया है और किया जाएगा।
- युव कल्याण, क्रीड़ा एवं संस्कृति को लेकर एक उत्कर्ष केन्द्र का निर्माण किया जाएगा।

कृषि, भूमि-सुधार, बागवानी, मत्स्य पालन तथा प्राणी संसाधन विकास

उन्नत तरीके की कृषि प्रक्रिया के आधार पर उत्पादन में बढ़ोत्तरी करने की योजना हमने बनाई थी। हमने कहा था कि धान उत्पादन में हम पंजाब व कर्नाटक के समकक्ष बनेंगे, उन्नत तकनोलॉजी का प्रयोग करके उत्पादन बढ़ाएँगे तथा कृषकों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलवाएँगे। जिले-जिले में कोल्ड स्टोरेज एवं सिंचाई व्यवस्था ढाँचे का विकास करना हमारा लक्ष्य था। मुर्गी पालन एवं मांस, अण्डे व दूध इत्यादि के विषय में थकज द्वारा लागू नियमों के अनुसार रखरखाव एवं बरबादी रोकने की व्यवस्था करना हमारा अभिप्राय था। कृषक भत्ता, मछुआरों की सुरक्षा में वृद्धि, बीजों के स्तर में सुधार तथा भूमि बैंक का गठन हमारी कार्यसूची के अन्तर्गत थे।

हमारे राजनैतिक दर्शन का केन्द्र माटी है। बंगाल की मिट्टी में सोना पैदा करने के प्रति तृणमूल कृतसंकल्प थी। शुरू से ही पश्चिम बंगाल में कृषि की नींव मजबूत थी। आइए देखते हैं - साढ़े चार वर्ष में हमारे कृषि कार्य का लेखा जोखा।

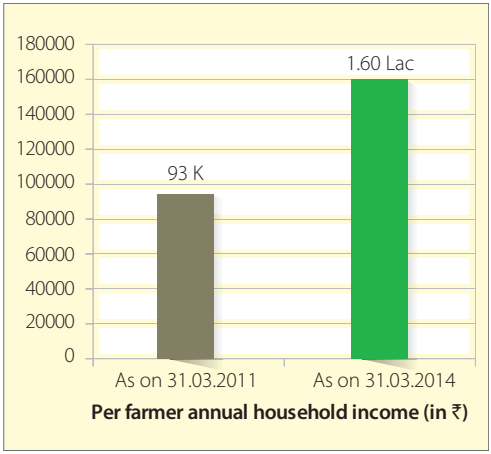

- अनाज के सर्वश्रेष्ठ उत्पादन हेतु हमारे राज्य को इस वर्ष के साथ-साथ लगातार चार वर्षों तक भारत सरकार के "कृषि कर्मण" पुरस्कार से नवाजा गया है। २०११-१२ के दौरान दलहन तथा २०१२-१३ के दौरान खाद्य अनाज के उत्पादन में सफलता के उपरान्त २०१३-१४ के दौरान भी खाद्य अनाज के उत्पादन में अतुलनीय सफलता के लिए लगातार ये पुरस्कार हमें प्राप्त हुए हैं। वर्ष २०१०-११ में उत्पादन जहाँ मात्र १४८ लाख टन था, २०१४-१५ में बढ़कर लगभग १७४ लाख टन हो गया।

- इसके साथ-साथ, किसानों की पारिवारिक आय में भी काफी बढ़ोत्तरी हुई है। वर्ष २०१०-११ में जहाँ प्रति परिवार वार्षिक आय थी मात्र ९३ हजार रुपये, वह वित्त वर्ष २०१४-१५ में बढ़कर १ लाख ६० हजार रुपये हो गयी है।

- हमने सिर्फ़ साढ़े चार वर्षों में लगभग ६९ लाख कृषक परिवारों को "किसान क्रेडिट कार्ड" प्रदान किए हैं।
- राज्य में १७६ कृषक बाजार स्थापित किए जा रहे हैं। इनमें से १२१ से भी अधिक कृषक बाजारों का काम पूरा हो चुका है।
- हमारी फसल हमारा गोला तथा हमारी फसल हमारी गाड़ी योजना से क्रमशः १७,000 एवं २२,000 परिवारों को लाभ मिला है।
- वर्द्धमान जिले में स्थापित "माटी तीर्थ-कृषि कथा" United Nation के Food & Agricultural Organisation (FAO) द्वारा सराही गयी है।
- कृषि, मत्स्यपालन, पशुपालन और सहयोगी क्षेत्रों के लिए विचारों के आदान-प्रदान तथा चर्चा के लिए स्थायी संरचना के रूप में हमने वर्द्धमान जिले में "माटी-तीर्थ" की स्थापना की है। माटी उत्सव प्रांगण में भी स्थायी संरचना के रूप में हमने "माटी-तीर्थ" की स्थापना की है, जहाँ हमने इस बार माटी उत्सव का पालन किया था।
- वैज्ञानिक तरीके से आधुनिक कृषि शिक्षा के प्रचार के लिए हमारी सरकार ने एक ठोस कदम के ज़रिए बर्दवान जिले के साधनपुर में एक नए कृषि महाविद्यालय की स्थापना की है।

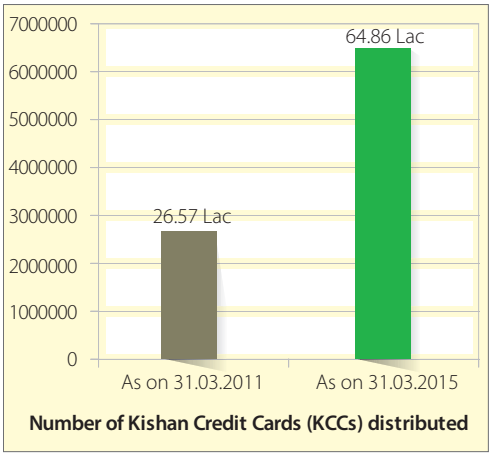

• पूरे देश में सर्वप्रथम पश्चिम बंगाल सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक अभिनव योजना - माटी की बात - चालू की है। इस योजना के अन्तर्गत कृषि विकास एवं ग्रामोन्नयन की दृष्टि से आधुनिकतम प्रौद्योगिकी की सहायता से बंगाल के किसान भाइयों के द्वार पर वैज्ञानिक प्रथा से खेती-किसानी की विभिन्न सूचनाएँ, सरकारी परियोजनाओं की जानकारी, कृषि विस्तार संबंधी वीडिओ, शिक्षामूलक दस्तावेज, चित्र इत्यादि पहुँच जाते हैं।

- गाँव के किसानों को उन्नत कृषि तकनीक उपलब्ध कराने की दृष्टि से वर्तमान राज्य सरकार स्वनिर्भर सामूहिक खेती उन्नयन समितियों को "कस्टम हायरिंग सेण्टर" बनाने के लिए २४ लाख रुपये तक का अनुदान दिया है। इन केन्द्रों से कृषक अपनी आवश्यकतानुसार सुलभ मूल्य पर कृषि औजार किराये पर ले सकते हैं।
- गत चार वर्षों में हमने "निज गृह निज भूमिम" योजना के अधीन पट्टा, कृषि-पट्टा और वन-पट्टा कुल मिलाकर ३ लाख से भी अधिक पट्टा प्रदान किये हैं। पूर्ववर्ती सरकार के आखिरी चार वर्षों में यह संख्या सिर्फ़ १ लाख १० हजार थी।
- इस बीच हमने जमीन आवंटन नीति एवं जमीन क्रय सम्बंधी नीति निर्धारित की है।
- उद्योग, वाणिज्य एवं विकास कार्यों के लिए हमारे राज्य में है भूमि बैंक (Land Bank) एवं भूमि बैंक का नक्शा (Map)।
- यह पहला मौका है जब उद्योग लगाने के उद्देश्य से जमीन का म्यूटेशन करने की समय सीमा निर्धारित हुई है २१ दिन, जबकि कनवर्शन करने की समय सीमा निर्धारित हुई है ३० दिन।
- हमारे खाद्य प्रसंस्करण एवं बागवानी मंत्रालय ने पिछले साढ़े चार वर्ष में पूरे राज्य में २९ अदद कोल्ड् स्टोरेज, ५६ बाजारों का निर्माण किया है। प्रायः डेढ़ लाख वर्ग किमी. के क्षेत्र में पॉली हाउस (Poly House) तथा अढाई लाख वर्ग किमी. क्षेत्र

में शेड नेट (Shade Net) का निर्माण किया गया है। साथ ही साथ १३७ ट्रैक्टर तथा ८२८ Power tiller वितरित किए गए हैं।

- मत्स्यपालन के क्षेत्र में हमारी ८१० बड़ी-बड़ी झीलों में मछली पालन का काम शुरू हुआ है। २३ करोड़ रुपये के खर्च से मछलियों के उन्नत खाद्य की आपूर्ति की गयी है। १.३८ लाख मछुआरों को Biometric Card प्रदान किए गए हैं।
- हिल्सा मछली की आपूर्ति बढ़ाने के लिए सुल्तानपुर में Hilsa Conservation and Research Centre की स्थापना की गई है।
- हमारे प्राणी संसाधन विकास मंत्रालय ने गत साढ़े चार वर्ष में एक लाख से भी अधिक बकरों, अढ़ाई करोड़ हंसों व चूजों का वितरण विभिन्न स्वनिर्भर दलों के मध्य किया गया है। इसके अलावा बेकार युवक, युवतियों को रोजगार की दृष्टि से प्रायः ३ हजार Bengal Dairy Kiosk की स्थापना जिलों-जिलों में की गयी है।

कृषि बंगाल का गौरव है। यह गौरव आने वाले दिनों में भी बरकरार रहेगा। और भी बहुत कुछ करेंगे, जो हमारे स्वर्णिम बंगाल का भविष्य सुजला सुफला रखेगा। जिन कामों को करने का संकल्प हमने लिया है, वह इस पुस्तक के पन्नों में दर्ज है।

- आगामी पाँच वर्षों में हमारा मूल लक्ष्य है - कृषि क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में विकास करके किसानों की आमदनी में प्रायः दो गुनी वृद्धि करना। इसके लिए तरह-तरह की नीतियाँ बनाकर आर्थिक दृष्टि से कृषि क्षेत्र में आकर्षण बढ़ाकर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगितात्मक परिस्थिति उत्पन्न करना।
- मौसम संबंधी किसी प्रकार की प्रतिकूल स्थिति के लिए तैयार रहेंगे।
- योजना एवं कार्यक्रम से बाहर निकलकर योजनाबद्ध तरीके से एण्ड-टू-एण्ड परियोजना शुरू की जाएगी।

- कृषि क्षेत्र से जुड़े तमाम विभागों की कार्यसूचियों को राज्य स्तरीय एक को-आर्डिनेशन सेल द्वारा केन्द्रित किया जाएगा। इस सेल में पशुपालन, मछली, खाद्य प्रसंस्करण, सिंचाई आदि जैसे विभागों से आए अनभिज्ञ सदस्यगण योजना एवं देखरेख के माध्यम से एक दूसरे से मिलेंगे।
- को-ऑपरेटिव क्रेडिट, मार्केटिंग एवं प्रोसेसिंग संस्थानों का सशक्तिकरण किया जाएगा।
- नेशनल एग्रिकल्चर इंश्योरेंस स्कीम के रूपान्तरण के माध्यम से समस्त फसलों का बीमा करने की सुविधा प्रदान की जाएगी।
- डिजिटल मिडियम से "माटी की बात" का विकास किया जाएगा।
- इन सीटू जल संरक्षण तथा भूगर्भ जल के विवेकपूर्ण प्रयोग की ओर ध्यान दिया जाएगा।
- सीड विलेज परियोजना एवं सटीर्फिकेशन का विस्तार किया जाएगा।
- और अधिक कृषक बाजार की स्थापना की जाएगी। कृषक बाजारों सहित अन्य बाजारों के क्षेत्रों का विकास किया जाएगा।
- ई-ट्रेडिंग के माध्यम से राष्ट्रीय कृषि बाजारों में प्रवेश किया जाएगा।
- कोल्ड स्टोरेजों का रखरखाव किया जाएगा तथा चरणबद्ध तरीके से विनियंत्रित किया जाएगा।
- स्व-नियुक्ति के लिए कृषक परिवार की दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से खास प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- पश्चिम बंगाल एग्रो मार्केटिंग कॉर्पोरेशन के द्वारा विभिन्न प्रकार के महकदार चावल की श्रेष्ठता संबंधी प्रचार चलाया जाएगा। अन्य कृषियोग्य पण्यों के विपणन हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएँगे।
- सुफल बांगला परियोजना : कोलकाता सहित दूसरे जिलों में मदर डेयरी, लाइवस्टॉक

डेवलपमेण्ट कॉर्पोरेशन एवं फिशरीज विभाग के सहयोग से विपणन केन्द्र का गठन किया जाएगा।

- आवश्यक सूचनाओं से कृषकों को अवगत कराने के लिए किसान पोर्टल सर्विस चालू की जाएगी।
- निजी विनियोग के माध्यम से इण्टीग्रेटेड फिशरीज जोन का सृजन किया जाएगा।
- आम, केला, अमरूद, लीची, अनन्नास सहित अन्य फलों एवं सब्जियों की पैदावार क्रमशः बढ़ायी जाएगी।
- फिशरी इस्टेट का विकास किया जाएगा। हिल्सा मछली पालन पर यथोचित महत्व दिया जाएगा। घरहीन मछुआरों तथा किसानों के लिए जमीन का पट्टे एवं मकान की व्यवस्था की जाएगी।
- सुन्दरवन एवं दीघा को विशेष फिशरी जोन के रूप में विकसित किया जाएगा। आनेवाले दिनों में पश्चिम बंगाल मछली उत्पादन में स्वावलंबी बन सके, इसके लिए बड़े मछली-पालन के लिए ढांचागत सुविधाएँ तैयार की जाएँगी।

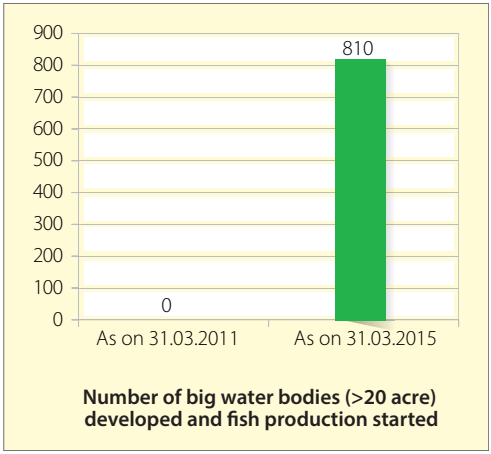

Number of big water bodies (>20 acre) developed and fish production started

- मछली पालन में दक्षता बढ़ाने के ऊपर विशेष जोर दिया जाएगा।
- मछली पालन में निजी विनियोग हेतु व्यापारियों को बढ़ावा दिया जाएगा।
- ग्राम स्तर तक पशुचिकित्सा का आधुनिकीकरण किया जाएगा।
- ८0% पोल्ट्री एवं पशु संसाधन के टीकाकरण की व्यवस्था की जाएगी। मुर्गी के साथ-साथ हंस के पोल्ट्री व्यवसाय पर बल दिया जाएगा। इससे रोजगार एवं स्वावलंबन का अवसर बढ़ेगा।
- पशुपालन में शिक्षित करके लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था की जाएगी।
- दूध के उत्पादन की मात्रा में वृद्धि की जाएगी।
- कृषि उत्पादन को लक्ष्य बनाकर उन्नति के आधार पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में परिवर्तन लाया जाएगा।

- गाय आदि पशुओं के लिए स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किए जाएँगे।
- उत्तर बंगाल में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।
- उच्च माध्यमिक स्तर पर कृषि को ऐच्छिक विषय के रूप में शामिल किया जाएगा।
- अकाल प्रवर क्षेत्र में ली गयी सिंचाई परियोजना को पूरा किया जाएगा।
- कृषकों को ऋण एवं आर्थिक सुरक्षा देने हेतु किसान क्रेडिट कार्ड देने का लक्ष्य १००% पूरा किया जाएगा।
- फसल बीमा के ऊपर जोर दिया जाएगा।
- तेज सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली आपूर्ति की जाएगी।
- इस बीच हम लोगों ने बहुत सारे सिंचाई रहित जमीन को सिंचाई के दायरे में ला दिया है। शेष सिंचाई रहित जमीन को भी इस दायरे में लाया जाएगा।
- कृषक बाजार, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज इत्यादि बनाकर उचित मूल्य पर धान व आलू इत्यादि के विपणन में सहायता की जाएगी। इस क्षेत्र में कृषकों की प्राप्य रकम उनके बैंक खातों में सीधे अंतरित की जाएगी।
- "कृषि चर्चा की बैठकों", मोबाइल तथा बिजली के माध्यम से लोगों को और करीब लाकर बहुफसली बीज बोने एवं मछली, प्याज आदि की उन्नत फसल के बारे में नियमित प्रशिक्षण दिए जाएँगे।
- स्थायी "माटीतीर्थ" संरचना का प्रयोग कर नई बहुफसली खेती, मछली पालन, बागवानी आदि विषय में प्रशिक्षण एवं ग्रीन फार्मिंग आदि के संबंध में विचार-विमर्श की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही साथ, कृषि विद्यालय के छात्र अपने हाथ-कलम से कार्य करके कृषि-विकास कर सकें, उस विषय पर भी ध्यान दिया जाएगा।
- जिलों-जिलों में कृषि भवन का निर्माण किया जाएगा।

अल्पसंख्यकों का विकास

अल्पसंख्यकों की उन्नति की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा, यह थी हमारी प्रतीज्ञा। उनकी उन्नति के लिए खास तहबिल का गठन, रोजगार की प्रधानता तथा विशेष मंत्रालय का गठन हमारा उद्देश्य था। निश्चय किया था - अलीगढ़ विश्वविद्यालय की तरह का शिक्षा प्रतिष्ठान निर्मित करने का। उनके लिए सीट संरक्षण पर महत्व दिया जाएगा। हमारी योजना थी आवश्यक मदरसा का निर्माण और अल्पसंख्यकों के लिए विशेष कमीशन की स्थापना। इसमें से कई हासिल करने में हम सफल हुए हैं। प्रस्तुत है किए गए कार्यों का संक्षिप्त लेखा-जोखा।

वादे पूरे किए गए:

- अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति एवं ऋण : विगत साढ़े चार वर्षों में, राज्य में १ करोड़ ५ लाख से भी अधिक अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्राओं के लिए १९२१ करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति तथा लगभग ४ लाख युवक-युवतियों को स्वरोजगार के लिए ७00 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण प्रदान कर हमारा राज्य पूरे देश भर में प्रथम स्थान पर है।
- अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के क्षेत्र में वित्त वर्ष २0१0-११ के बजट में ४७२ करोड़ रुपये के प्रावधान के मुकाबले वर्तमान सरकार के वित्त वर्ष २0१५-१६ में प्रायः ५ गुना अधिक यानी २३८३ करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

- राज्य के बजट में अल्पसंख्यक की उन्नति के लिए वर्ष २००७-११ में ₹४३२ करोड़ का प्रावधान किया गया था, जबकि २०११-१५ में इसे बढ़ाकर २८२७ करोड़ रुपये किया गया है।
- १५१ अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉक में Multi Sector Devolopment Program (MSDP) चालू किया गया है। हमारे राज्य में उसके क्रियान्वयन हेतु प्रायः २१५४.२७ करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो पूरे भारत में सबसे अधिक है।
- हमने OBC तालिका में और भी नए-नए समुदाय को शामिल किया है। राज्य के मुस्लिम संप्रदाय के ९७% लोगों को OBC के दायरे में लाया गया है। इससे शिक्षा एवं सरकारी नौकरियों में आरक्षण एवं अन्य सुविधाएँ सुनिश्चित की गयी हैं।
- इसके अलावा नए कानून लागू करके उच्च शिक्षा संस्थाओं में दाखिले के क्षेत्र में १७% सीट OBC के लिए आरक्षित की गयी है। इसके क्रियान्वयन से साधारण श्रेणी की संख्या में किसी प्रकार की कमी नहीं की गई है और इसमें १००० करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च होंगे। इसके फलस्परूप अल्पसंख्यक समुदाय के उच्च शिक्षा प्राप्ति के अवसर में निःसंदेह वृद्धि होगी। आरक्षण के परिणामस्वरूप पिछले वर्ष ५९,६१२ ओबीसी के छात्रों को Under Graduate तथा Post Graduate कोर्स में दाखिला मिला है, जो पूरे राज्य में उच्च शिक्षा संस्थान में कुल प्रवेश का १०.६% है।
- आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि इस वर्ष अल्पसंख्यक समुदाय के २९१ व्यक्ति डॉक्टरी में, २५ व्यक्ति WBCS में तथा ९ व्यक्ति WBJS (Judicial Service)- में सफल हुए हैं।
- न्यू टाउन में लगभग २० एकड़ क्षेत्र में प्रायः २५७ करोड़ रुपये खर्च करके नवनिर्मित आलिया विश्वविद्यालय के भवन में पठन-पाठन का कार्य शुरू हो चुका है। इसके साथ ही ७५ करोड़ रुपये के व्यय से आलिया विश्वविद्यालय के पार्कसर्कस कैम्पस का कार्य समाप्त हुआ है।
- रखरखाव भत्ता : अल्पसंख्यक विषयक तथा मदरसा शिक्षा विभाग के अधीनस्थ मदरसा स्कूल से संलग्न छात्रावासों में रहने वाले छात्र-छात्राओं को प्रति वर्ष प्रति १० (दस) महीने के लिए मासिक रु.१००० रुपये की दर से रखरखाव भत्ता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।
- न्यू टाउन में ५ एकड़ जमीन पर तृतीय हज भवन मदीना-तूल-हुज्जाज का निर्माण प्रायः १०० करोड़ रुपये खर्च करके किया गया है।

- वाक्फ बोर्ड के माध्यम से प्रायः ६५,000 इमाम पोलिओ दूरीकरण, साम्प्रदायिक सद्भाव की रक्षा सहित विभिन्न समाज सेवामूलक काम में हमारी मदद कर रहे हैं।
- जबरन दखल किए गए कलुषित होने से कब्रस्थान की रक्षा करने के उद्देश्य से २000 सार्वजनिक कब्रगाहों के चारो ओर चहारदीवारी बनाई गयी है, जिसके लिए ₹१५0 करोड़ का अनुमोदन किया गया है।
- मदरसे में कंप्यूटर प्रशिक्षण (साइबर ग्राम) : राज्य के सभी मदरसों के प्रत्येक छात्र-छात्रा (६ठीं श्रेणी और उसके ऊपर) के लिए कंप्यूटर का प्राथमिक ज्ञान व इण्टरनेट के प्रयोग का प्रशिक्षण चालू किया गया है। मदरसा के छात्र-छात्राओं की क्षमता-वृद्धि की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत में पश्चिम बंगाल ही एक मात्र ऐसा राज्य है, जहाँ इस प्रकार का प्रयास किया गया है।
- छात्रावास निर्माण : हमारी सरकार ने इस दौरान ३८२ नए छात्रावास (छात्र-१९0 व छात्रा-१९२) निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके फलस्वरूप कुल मिलाकर प्रायः २२ हजार शिक्षार्थी लाभान्वित होंगे, जिनमें अधिकांश छात्राएँ हैं। ८७ छात्रावास चालू हो गए हैं। मार्च, २०१६ के मध्य तक २४0 छात्रावासों को सक्रिय किया जाएगा।
- पेशेवर प्रशिक्षण : वर्ष २०११ के मई महीने के बाद से अल्पसंख्यक युवक-युवतियों के लिए नानाप्रकार के पेशेवर प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। अल्पसंख्यक समुदाय के प्रायः ६0 हजार युवक-युवतियों ने विभिन्न विषयों में प्रशिक्षण लिये हैं। अभीतक पेशेवर प्रशिक्षण प्राप्त कुल २१,३९१ शिक्षार्थियों की नियुक्ति की गयी है।
- पॉलीटेक्निक एवं आईटीआई : अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं की कारीगरी में दक्षता वृद्धि के लिए अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉकों में से ८ पॉलीटेक्निक कॉलेजों (७ नए और १ अपग्रेडेशन) तथा ३९ आईटीआई के निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

- कर्मतीर्थ (मार्केटिंग हब) : अल्पसंख्यकों को स्वरोजगार के माध्यम से कुछ वास्तुओं को तैयार करके उनके विपणन हेतु १३२ मार्केटिंग हब तैयार किये जा रहे हैं। इसके फलस्वरूप प्रायः २१,००० युवक-युवतियाँ लभान्वित होंगे। इस क्षेत्र में रु.१३६ करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रसंगवश उल्लेखनीय है कि पूरे राज्य में ५०० मार्केटिंग हब तैयार किए जा रहे हैं। मार्च, २०१६ में ७८ मार्केटिंग हबों को सक्रिय किया जाएगा।

- अल्पसंख्यक भवन निर्माण : अल्पसंख्यकों की उन्नति के लिए किये गए समस्त कार्यों को एक छत के नीचे लाने के लिए कोलकाता सहित प्रत्येक जिले में एक-एक यानी कुल २० अल्पसंख्यक भवन का निर्माण किया जा रहा है, जिनमें से १७ अबतक चालू हो चुके हैं। अल्पसंख्यकों की उन्नति संबंधी कार्यों की देख-रेख के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति जिला स्तर पर की जाएगी।

- उर्दू भाषा का प्रचार-प्रसार : संबद्ध कानून में संशोधन करके उर्दू भाषा को सरकारी भाषाओं की तालिका में शामिल किया गया है। जिन इलाकों में १०% से अधिक उर्दू भाषी लोग रहते हैं, उन क्षेत्रों में उर्दू भाषा को सरकारी भाषा के रूप में मान्यता दी जा रही है। बर्द्धमान जिले में आसनसोल तथा उत्तर दीनाजपुर जिले में इस्लामपुर जैसे उर्दूभाषी अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र में उर्दू भाषा के प्रसार के उद्देश्य से पश्चिम बंगाल उर्दू अकादमी की शाखा के रूप में दो उर्दू सांस्कृतिक केन्द्र के निर्माण की योजना बनाई गई है।

- आवासन : अल्पसंख्यक समुदाय की आवासन समस्या के समाधान हेतु इस बीच एमएसडीपी, बीआरजीएफ, गीतांजली एवं असहाय महिलाओं के आवासन हेतु आवासन परियोजना के माध्यम से प्रायः ८२ हजार से भी अधिक गृह निर्माण के लिए रु.१०५८ करोड़ खर्च किए गए हैं। पिछली सरकार के कार्यकाल में सिर्फ ४१ हजार आवासनों का निर्माण किया गया था।

बंगाल में अल्पसंख्यक भाई-बहनों के लिए भविष्य में भी हम अपने कर्तव्य पालन से पीछे नहीं हटेंगे। उनकी सुख-सुविधा सुनिश्चित करने के लिए काफी परीश्रम करेंगे। कुछ काम, जो हम करेंगे ही, उनका उल्लेख यहाँ किया जा रहा है। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि इस तालिका में ही हमारी भावी परियोजनाएँ सीमित नहीं हैं।

- अल्पसंख्यक लोगों के जीवन की तथा धार्मिक सुरक्षा सुनिश्चित करना भी हमारा काम है।
- अल्पसंख्यक समुदाय के असंख्य छात्र-छात्राओं को छात्र-वृत्ति दी जाएगी।
- मदरसों में नवम श्रेणी से बारहवीं श्रेणी तक की समस्त छात्राओं को साइकिल प्रदान की जाएगी।
- अल्पसंख्यक बहुल जिलों एवं महकमों में अंग्रेजी माध्यम के मदरसों का निर्माण किया जाएगा एवं जिनका निर्माण शुरू हो गया है, उन्हें पूरा किया जाएगा।
- वर्ष २०२० तक सरकारी सहायताप्राप्त समस्त मदरसों के छात्र-छात्राओं को प्राथमिक कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- नए मदरसा भवन, होस्टल, अतिरिक्त श्रेणी कक्ष, पेय जल व्यवस्था, शौचागार एवं लेबोरेटरी बनाए जाएँगे।
- कुछेक सरकारी सहायताप्राप्त मदरसों को उत्कर्ष केन्द्र के रूप में परिवर्तित किया जाएगा।

- इसके अलावा, काफी मदरसों के विज्ञान विभाग को उच्च माध्यमिक स्तर तक उन्नत किया जाएगा एवं उनमें आधुनिक परीक्षणशाला की सुविधा रहेगी।
- निर्दिष्ट स्कूलों एवं मदरसों में वर्ष २०२० तक कई सौ होस्टल निर्मित किए जाएँगे।
- जिला सदर दफ्तर एवं नए विश्वविद्यालयों में अल्पसंख्यक छात्रावास बनाए जाएँगे। इससे अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को और अधिक उच्च शिक्षा ग्रहण करने का अवसर प्राप्त होगा।
- अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में नए उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं स्नातक स्तर के कॉलेजों में नए-नए विभाग बनाए जाएँगे।
- उत्तर बंगाल में अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में आलिया विश्वविद्यालय के नए कैम्पस की स्थापना की जाएगी।
- अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र में आलिया विश्वविद्यालय के अधीन कई एक सरकारी कॉलेज स्थापित किए जाएँगे।
- आलिया विश्वविद्यालय के अधीन मेडिकल कॉलेज की स्थापना की योजना है।
- दिल्ली के आईएएस कोचिंग सेण्टर में अध्ययनरत अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को आर्थिक सहायता करने के लिए एक विशेष योजना हाथ में ली गयी है, जिससे कई सौ छात्र-छात्राएँ लाभान्वित होंगे।
- बस्ती क्षेत्र में रहने वाले आर्थिक दृष्टि से पिछड़े छात्र-छात्राओं के लिए विशेष प्रशिक्षण व्यवस्था की जाएगी। नामी प्रतिष्ठानों द्वारा सांध्यकालीन कार्यक्रम शुरू करके छात्र-छात्राओं के मानसिक विकास में मदद की जाएगी।
- डब्ल्युबीसीएस तथा अन्य रोजगार से जुड़ी प्रतियोगितामूलक परीक्षाओं के लिए बहुत-सारे विशेष प्रशिक्षण कोर्स चालू किए जाएँगे।
- अगले पाँच वर्षों में लाखों लोगों को स्वावलंबी करने के उद्देश्य से ऋण दिए जाएँगे। युवक-युवतियों को विशेष प्रशिक्षण देकर विभिन्न विषयों में उनकी दक्षता बढ़ायी जाएगी।
- अगले पाँच वर्षों में युवक-युवतियों को विशेष प्रशिक्षण देकर विभिन्न विषयों में उनकी दक्षता बढ़ायी जाएगी।

- बहुत-से कर्मतीर्थ का निर्माण शुरू किया जाएगा। अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए और कई सौ कर्मतीर्थों का गठन किया जाएगा।
- अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉकों में बेसलाइन सर्वर द्वारा संरचनागत विचलन चिह्नित किए जाएँगे तथा उनके निवारण हेतु संरचना का निर्माण किया जाएगा।
- "सबके लिए आवासन" के अधीन अल्पसंख्यकों के लिए असंख्य आवासन परियोजनाएँ हाथ में ली जाएँगी।
- केआईटी, केएमडीए, डब्ल्युबी हिडको आदि सरकारी संस्थाओं द्वारा प्रदत्त जमीन पर अल्पसंख्यकों के लिए विशेष आवासन बनाए जाएँगे।
- कम ब्याज पर काफी मात्रा में ऋण दिए जाएँगे।
- ओबीसी तालिका में ९७% मुस्लिम शामिल हो जाने से उनके रोजगार के अवसर काफी बढ़ जाएँगे।
- आसनसोल व इस्लामपुर की तरह हावड़ा, हुगली एवं उत्तर २४ परगना में उर्दू अकादमी की शाखा स्थापित की जाएगी।
- प्रतियोगिता मूलक परीक्षाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाएँगे।
- जिन सब स्थानों में अल्पसंख्यकों की संख्या १०% से ऊपर है, उन सब स्थानों में अल्पसंख्यकों की भाषाओं को विशेष महत्व दिया जाएगा।

- जिन स्थानों पर उर्दू को सरकारी भाषा के रूप में चिह्नित किया गया है, उन इलाकों में विभिन्न कामों की सुविधा के लिए उर्दूभाषा सहकारियों के कैडर गठित किए जाएँगे, जिस प्रकार से वित्त विभाग के पर्सनल असिस्टेंट के लिए विशेष गोष्ठी है।
- सीमालंघन रोकने के उद्देश्य से किसी भी वाक्फ़ सम्पत्ति का रखरखाव किया जाएगा।
- कब्रस्तान की चहार-दीवारी बनाने के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी।

जंगलमहल, पहाड़ एवं चाय बागान

बंगाल का जंगलमहल उग्र राजनैतिक चर्चा का केन्द्र था। पहाड़ों में भी शान्ति नहीं थी। चाय बागानों में श्रमिकों एवं मालिकों के बीच रोजाना अशान्ति थी। कुल मिलाकर इन तीन भौगोलिक क्षेत्रों में बंगाल की मिट्टी रक्त से लाल हो गयी थी। हम लोगों ने प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक सभी स्तरों पर अथक प्रयास से शान्ति लौटाई है, इन सभी उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में।

किए गए वादों की रक्षा हेतु तृणमूल सरकार की कार्रवाइयों के कुछ ब्यौरे नीचे दिए गए हैं।

- वर्तमान सरकार के शासनकाल में जंगलमहल में शान्ति स्थापित हुई है। पिछले साढ़े चार वर्षों में जंगलमहल में उन्नयन के काम को एक अलग पहचान मिली है। हमारे राज्य के कुल २४ ब्लाकों के लोग (पश्चिम मिदनापुर में ११, पुरुलिया में ९ और बांकुड़ा में ४) जंगलमहल इलाके में शामिल हैं। २०१५ से बीरभूम जिले के १० ब्लॉक भी इसके दायरे में आ गए हैं।
- केन्द्र सरकार द्वारा वित्त वर्ष २०१५-१६ से Integrated Action Plan (IAP) योजना बन्द कर देने के बाद जंगलमहल के विकास हेतु हमारी सरकार की Jangalmahal

Action Plan (JAP) योजना हाथ में ली गयी तथा विकास के खाते में ₹११० करोड़ का प्रावधान किया गया था।

- इस क्षेत्र के लोगों के लिए सरकारी काम में सुविधा एवं प्रशासनिक कार्य निष्पादन की वृद्धि की दृष्टि से पश्चिमी मिदनापुर जिले के झाड़ग्राम को एक अलग जिला तथा पुरुलिया जिले के झालदा एवं मानबाजार को २ अलग महकमा बनाने का निर्णय लिया गया।
- बांकुड़ा जिले के बड़जोड़ा, ओन्दा, छातना और विष्णुपुर एवं पश्चिम मिदनापुर जिले के नयाग्राम, झाड़ग्राम व गोपीबल्लभपुर में कुल ७ मल्टी सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल का निर्माण किया गया है। इसके अलावा पुरुलिया जिले के हातुयाड़ा व रघुनाथपुर एवं पश्चिम मिदनापुर जिले के शालबनी, डेबरा और घाटाल में और ५ मल्टी सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है।
- हमारी सरकार जंगलमहल के प्रत्येक परिवार को ₹२ प्रति किलो की दर से हर महीने ३५ किलोग्राम खाद्यान्न की आपूर्ति कर रही है।
- केन्दु पत्ते चुनकर जीवन निर्वाह करने वाले लोगों की सामाजिक सुरक्षा के लिए एक नई योजना (West Bengal Kendu Leaves Collectors' Social Security Scheme, 2015) का श्रीगणेश किया गया है।

- इस सामाजिक सुरक्षा योजना के अन्दर ६0 वर्ष की आयु पूरी करने पर उपभोक्ता अधिकतम डेढ़ लाख रुपये तक की आर्थिक सुरक्षा पायेंगे। साथ ही साथ दुर्घटनाजनित मृत्यु होने पर उसके परिवार को एकबारगी डेढ़ लाख रुपये और स्वाभाविक मृत्यु होने पर पचास हजार रुपये मिलेंगे। स्थायी अक्षमता के लिए २५ हजार रुपये, मातृत्व कालीन सहायता के रूप में ६ हजार रुपये और बीमारी के मामले में वार्षिक २५ हाजार रुपये, परिवार के सदस्य की मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार बाबत ३ हजार रुपये आर्थिक सहायता की व्यवस्था भी इस योजना के अन्तर्गत है। इस सामाजिक सुरक्षा योजना ने केन्दु पत्ते चुनकर जीविका चलाने वाले जंगलमहल के दरिद्र परिवारों के लिए सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा का एक नया क्षितिज खोल दिया है।

- जंगलमहल क्षेत्र की मूल समस्या है - भौगोलिक कारणों से मिट्टी में जलधारण क्षमता की कमी एवं ऊँची-नीची जमीन के कारण बारिस का पानी बह जाता है। इस समस्या के समाधान हेतु हम इस इलाके में पानी को संजोकर रखने हेतु जलतीर्थ परियोजना में चेक डैम और जल संरक्षण टैंक बनाने में सक्रिय हुए हैं। पश्चिम मिदनापुर, पुरुलिया, बांकुड़ा व वीरभूम जिले की कुल ३२ हजार हेक्टेयर जमीन के लिए ₹५00 करोड़ के व्यय से ८३८ ऐसी परियोजनाओं के क्रियान्वयन का कार्य हमने हाथ में लिया है, जिनमें से ४२४ परियोजना का काम शुरू हो चुका है।

- पुरुलिया जिले में राज्य का अन्यतम वृहद् पेय जल की आपूर्ति हेतु जाइका परियोजना (लगभग १२०० करोड़ रुपये) का काम शुरू हो चुका है। इसके फलस्वरूप पुरुलिया जिले के ९ ब्लॉकों के १५ लाख लोग लाभान्वित होंगे।
- बांकुड़ा जिले में राज्य की पाइप द्वारा अनोखी पेय जल आपूर्ति परियोजना (₹११०० करोड़) हाथ में ली गयी है। इसके माध्यम से, दुर्गापुर में दामोदर नदी, मुकुटमणिपुर में कंसावती जलाधार एवं जिले की दूसरी छोटी-छोटी नदियाँ जैसे शिलावती, द्वारकेश्वर आदि से जल लेकर साफ करके आपूर्ति की जाएगी। इस परियोजना में दो चरण होंगे एवं २०५२ मौजों के १८ लाख से भी अधिक लोग इससे लाभान्वित होंगे।
- पूर्व व पश्चिम मिदनापुर जिले के कुल १२ ब्लॉकों में बाढ़ नियंत्रण हेतु लगभग-२ हजार करोड़ रुपये से "घाटाल मास्टर प्लान" अनुमोदित की गयी है। पूरा हो जाने पर इस विस्तृत क्षेत्र में प्रायः १७ लाख लोग प्रतिवर्ष बाढ़ की समस्या से छुटकारा पायेंगे।
- लगभग ६५० करोड़ रुपये के खर्च से केलेघाई - कपालेश्वरी - बागाई नहरों का पूर्व मिदनापुर अंश के कायाकल्प का काम पूरा हो गया है। पश्चिम मिदनापुर जिले में २१६ करोड़ रुपये के व्यय से ७५ किमी. खनन एवं १५८ किमी. नहरें खोदने का काम पूरा हो गया है। शेष कार्य भी शीघ्र समाप्त होगा। इस परियोजना के अन्तर्गत पूर्व मिदनापुर जिले के मयना, भगवानपुर-१ और पटाशपुर-१ ब्लॉकों के साथ पश्चिम मिदनापुर जिले के ११ ब्लॉक के लगभग ४ लाख लोग लाभान्वित होंगे।

- खेल-कूद के क्षेत्र में उपयुक्त प्रतिभा की निरंतर खोज तथा जंगलमहल के युवा संप्रदाय को मूल स्रोत में लौटाने की दृष्टि से "जंगलमहल कपफ आदि खेल-कूद प्रतियोगिता का नियमित आयोजन किया जाता है।
- साढ़े चार वर्ष में हमने जंगलमहल के प्रायः ३३,000 युवक-युवतियों को पुलिस के विभिन्न पदों पर नियुक्त किया है। इनमें से होमगार्ड में नियुक्त हुए हैं - ११९३ व्यक्ति, NVF में ४०३७ व्यक्ति, जूनियर कंसटेबल मे ४८०९ व्यक्ति, S.T. Constable में ६७८ व्यक्ति, Village Police Volunteer के रूप में ६५0 व्यक्ति, Civic Police Volunteer के रूप में २0,१९८ व्यक्ति, महिला कंस्टेबल ३८0 व्यक्ति, SPO के रूप में ८९५ व्यक्ति।
- नई सरकार के शासनकाल में पहाड़ में भी शान्ति स्थापित हुई है। पहाड़ के भाई-बहन भी आज सरकार की उन्नति में शामिल है। इस बीच, पहाड़ की उन्नति के लिए हमलोगों ने एकगुच्छ परिकल्पनाएँ हाथ में ली हैं। इसके लिए गोरखा टैरीटोरियल ऐडमिनिस्ट्रेशन बनाया गया है। राज्य सरकार के पैसों से उन्नति का कार्य चल रहा है।
- पहाड़ की उन्नति के लिए हमारी सरकार ने विगत तीन वर्षों में परियोजना के खाते में जीटीए को ₹१0१८ करोड़ का प्रावधान किया है। ब्लॉक, महकमा और जिला सदर के साथ ग्रामों के यातायात सम्पर्ककारी सड़क निर्माण, मरम्मत, ग्रामीण विद्युतीकरण, कम्युनिटी हॉल का विकास, नदी के किनारों, झरनों का संरक्षण का काम, ग्राम व शहरी क्षेत्रों के जल की समस्या के समाधान सहित पहाड़ों पर पर्यटन विकास के लिए सरकार ने सभी तरह के कदम उठाए हैं।
- इलाके के जनसाधारण की माँग तथा प्रशासनिक सुविधा के लिए कलिंपांग महकमा को नया जिला तथा मिरिक को नया महकमा बनाने का निर्णय लिया गया।
- हमने Clean Dargeeling Green Darjeeling कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। यह केवल कार्यक्रम ही नहीं बल्कि यह हमारा अंगीकार है। दार्जिलिंग के झरने की अग्रगति को हम लौटा देंगे तथा पर्वत को हरे-भरे वन से ढक देंगे। इसका मूल लक्ष्य है -
  - समग्र दार्जिलिंग जिले में एक निर्मल, सुन्दर, सजीव परिवेश का सृजन।
  - मिट्टी संरक्षण, वृक्षारोपण के माध्यम से पहाड़ को हरे-भरे वृक्षों से ढक देना (Green Cover)।
  - इलाके के साथ-साथ इलाके के लोगों को जीविकोपार्जन का अवसर प्रदान करना।
  - जल संरक्षण एवं बारिश के जल को संचित करके पर्वतीय इलाके के लोगों की जल-समस्या का समाधान।

- दार्जिलिंग जिले की सबसे बड़ी समस्या थी शुद्ध पेय जल का अभाव। खासकर जनवरी महीने से मई तक जल की समस्या विकट होती है। जल की आपूर्ति के लिए यह शहर एक झील के ऊपर पूरी तरह से निर्भर है। २६ स्रोतों का जल इस झील में इकट्ठा होता है, परन्तु उस जल से पूरे साल तक जल की माँग पूरी नहीं हो सकती। दार्जिलिंग की जल-समस्या भी अब समाधान के मार्ग पर है। इस बीच, जन स्वास्थ्य और कारीगरी मंत्रालय के प्रयास से दार्जिलिंग व आस-पास के क्षेत्रों में शुद्ध पानीय जल आपूर्ति के लिए ₹५५ करोड़ से बालासन जल परियोजना को मूर्त्त रूप दिया गया है। बालासन नदी से जल लेकर व शुद्ध करके रोजाना प्रायः २० लाख गैलेन पेय जल की आपूर्ति की जाती है और उस क्षेत्र के लगभग डेढ़ लाख निवासियों एवं पर्यटकों की पेय जल की माँग पूरी की जाती है।
- दार्जिलिंग जिले के प्रत्येक ब्लॉक में हमलोग ठोस एवं तरल वर्ज्य (Solid And liquid waste Management) के निष्कासन की व्यवस्था की है।
- प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालयों में बरसात के पानी को संचित करने की एक उपयुक्त संरचना जनस्वास्थ्य एवं कारीगरी मंत्रालय तैयार करेगा। मकान के छत के ऊपर बरसात का पानी इकट्ठा करने के लिए भी ढांचागत सुविधाएँ तैयार की जाएँगी।
- हमारी सरकार ने लेप्चा, तमांग, शेरपा, भूटिया, मंगर, लिम्बू, राई जनजातियों की उन्नति के उद्देश्य से पृथक-पृथक बोर्ड का गठन किया है। उनके निवास स्थान निर्माण, शिक्षा, सांस्कृतिक पुनर्जीवन व सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न परियोजनाओं को मूर्त्त रूप दिया जा रहा है।
- तराई-डुअर्स क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से "तराई-डुअर्स टास्कफोर्स" का गठन किया गया है।
- लेप्चा संस्कृति और उसकी विरासत को पर्यटकों तक पहुँचाने के लिए हमने डेढ़ करोड़ रुपये खर्च करके दो "Cultural Tourism Centre" का गठन किया है। एक सुकियापोखरी ब्लॉक में और दूसरा कलिम्पोंग-१ ब्लॉक में तैयार हो रहा है।
- पहाड़ के सभी लोगों के मध्य जन वितरण प्रणाली के माध्यम से ₹२ प्रति किग्रा. दर से ३५ किग्रा. अनाज वितरित किए जा रहे हैं।
- पहाड़ में ४ जल बिजली परियोजनाएँ बन रही हैं - तीस्ता नदी के ऊपर ३ अदद और रन्मम नदी के ऊपर १ जल बिजली उत्पादन परियोजना आ रही है। इसमें कुल निवेश हुआ है ₹३,३०० करोड़।

- नई प्रतिभा की खोज के लिए दार्जिलिंग-डुअर्स-तराई क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
- राज्य के प्रायः २८० चाय बागानों में १२ लाख से भी अधिक लोग रहते हैं। वर्तमान सरकार इन सभी क्षेत्रों में आवासन, पेय जल की आपूर्ति, राशन, चिकित्सा और स्वास्थ्य व्यवस्था आदि सेवाएँ प्रदान कर रही है।
- खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम में चाय बागान के प्रत्येक परिवार को ₹२ प्रति किलो की दर से महीने में ३५ किग्रा. अनाज हमारी सरकार दे रही है।
- इसके अलावा, प्रति व्यक्ति को महीने में ७०० मिली. केरोसिन की आपूर्ति की जाती है।
- समस्त योग्य श्रमिकों को Financial Assistance to the workers in locked out Industrial Units (FAWLOI) के अन्तर्गत शामिल किया गया है।
- इसके दायरे में प्रायः डेढ़ हजार श्रमिक हर महीने १५०० रुपये की दर से भत्ता पा रहे हैं। इस योजना में नीतिगत बदलाव के माध्यम से पहले के एक वर्ष के बदले अब चाय बागान बन्द होने के तीन महीने के समय तक यह सुविधा प्रदान की जाती है।
- चाय बागान से निकटवर्ती अस्पताल में जाने के लिए निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा प्रदान की जाती है।
- चाय बागानों में चलती-फिरती मेडिकल यूनिट के जरिए सप्ताह में तीन दिन उन्नत स्तर का परीक्षाण एवं चिकित्सा प्रदान की जाती है।

- चाय बागानों के कुपोषण के शिकार शिशुओं की चिकित्सा पोषण पुनर्वासन केन्द्रों (Nutrition Rehabilitation Centre) के जरिए करायी जाती है।
- चाय बागानों के अशक्त एवं बेसहारा व्यक्तियों को "सहाय" योजना के मार्फत तैयार भोजन की आपूर्ति की जाती है।

हमारा काम है बंगाल के लोगों की उन्नति, चाहे भौगोलिक स्थिति जो भी हो। जो-जो काम हमने किए हैं, वहीं तक सीमित रहने पर उन्नति का चक्र एक दिन थम जाएगा, यह हम जानते हैं। इस महत् यज्ञ में हम सभी को शामिल होना होगा। जंगलमहल, पहाड़ तथा चाय बागान की शान्ति और उन्नति को

और अधिक सुदृढ़ और चिरस्थायी करने के लिए आने वाले दिनों में और बहुत से काम करने होंगे, उसकी एक रूपरेखा नीचे दी गयी है।

- जंगलमहल में शान्ति, सुरक्षा तथा आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा को बरकरार रखना होगा।
- जंगलमहल की उन्नति के लिए माँ-माटी-मानुष की सरकार सदैव तत्पर है।
- सर्वांगीण उन्नति तथा पर्यटन के प्रचार-प्रसार के माध्यम से जंगलमहल को अग्रसर करना होगा।
- आर्थिक-सामाजिक परिस्थितियों की ओर नजर रखकर अनुसूचित जाति, आदिवासी एवं ओबीसी की सम्पूर्ण सहायता की जाएगी।
- पहाड़ भी हम लोगों का प्रिय स्थान है। हमने बार-बार सिर्फ़ इसलिए दौड़ लगाई है कि पहाड़ और जंगलमहल प्रसन्न, शान्त और सुरक्षित रहे।
- पर्यटन संबंधी कार्यों का प्रचार-प्रसार होगा।
- पहाड़ में सर्वांगीण उन्नति का चित्र बरकरार रहे, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा।
- पहाड़ में अनेक Welfare Board का गठन किया गया है सभी माई-बहनों की सहूलियत के लिए। पहाड़ में उन्नति की धारा बरकरार रहेगी इस संबंध में अगर और कोई आगे आता है, तो उसकी सहायता की जाएगी।
- तराई, डुअर्स व आदिवासी, अनुसूचित जाति, चाय बागान के श्रमिकों और पहाड़ी भाई-बहनों सभी की उन्नति का विशेष ध्यान रखा जाएगा।
- चाय बागानों की उन्नति के लिए हम हमेशा ही प्रयत्नशील हैं। पेंशन, खाद्य

आपूर्ति, स्वास्थ्य, शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए हम कृतसंकल्प हैं। श्रमिकों की मजदूरी तथा बकाया पैसे समय पर दिए जाँय, उस तरफ भी हमारी दृष्टि रहेगी।

- चाय उद्योग के पुनर्जीवन के लिए हमारा दल बचनबद्ध है।
- सभी संप्रदाय के लोगों को साथ लेकर सद्‌भाव व भाईचारा बनाए रखना ही हमारा स्थायी लक्ष्य है।

पिछड़े वर्ग का कल्याण व आदिवासियों का विकास

पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा प्राप्ति के क्षेत्र में नानाप्रकार की सुविधाओं की जरूरत को हमने चार वर्ष पहले ही महसूस किया था। जाति प्रमाणपत्र हासिल करने की प्रक्रिया को तेज करने की आवश्यकता है, इसको समझने में भी देरी नहीं हुई थी। जंगल महल के लोगों के जीवन-यापन में सर्वांगीण उन्नति का साधन हमने अपनाया था। अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्र-छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में छात्रवृत्ति की व्यवस्था करने का संकल्प हमने लिया था। इसके साथ ही उनके लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण की व्यवस्था करने की हमारी इच्छा थी।

तृणमूल सरकार एक निश्चित लक्ष्य के साथ आगे बढ़ी है। हम कहाँ तक सफल हुए हैं, यह निम्नलिखित तथ्यों से ही स्पष्ट हो जाएगा।

- हमारी सरकार ने आदिवासी उन्नयन की दिशा में एक अलग Tribal Development Department का गठन किया है।
- 'शिक्षाश्री' पांचवी से आठवीं कक्षाओं के SC व ST छात्र-छात्राओं को स्कॉलरशिप प्रदान करने की दिशा में राज्य सरकार ने "शिक्षाश्री" योजना चालू की है। अभीतक १३.४ लाख SC तथा प्रायः २.४ लाख ST छात्र-छात्राएँ इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं।

अगली मई तक और भी साढ़े ९ लाख छात्र-छात्राएँ इसमें शामिल होंगे।

- विगत साढ़े चार वर्षों में प्रायः ४२ लाख SC/ST/OBC प्रमाणपत्र प्रदान किए गए हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है।

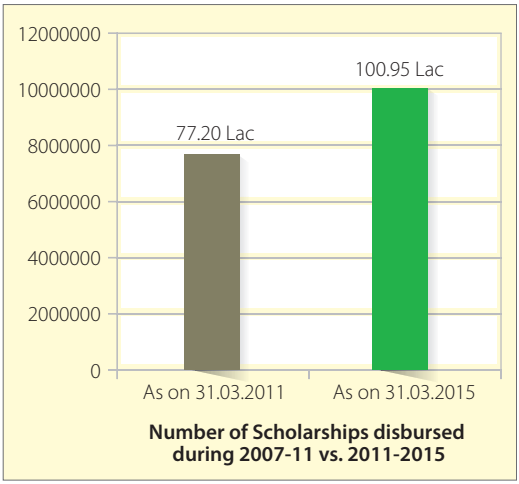

Number of Scholarships disbursed during 2007-11 vs. 2011-2015

- हमारी सरकार ने लेप्चा, तमांग, शेरपा, भूटिया, मंगर, खाम्बू-राई एवं लिम्बू जनजाति की उन्नति के लिए एक अलग बोर्ड का गठन किया है। साथ ही उनेक आवास निर्माण, शिक्षा, सांस्कृतिक पुनर्जीवन व सर्वांगीण उन्नति के लिए विभिन्न योजनाओं को मूर्त्त रूप दिया जा रहा है।

इसके अलावा पहाड़ एवं मैदानी इलाकों के लोगों के विकास के लिए तराई-डुआर्स टास्क फोर्स का गठन भी हुआ है।

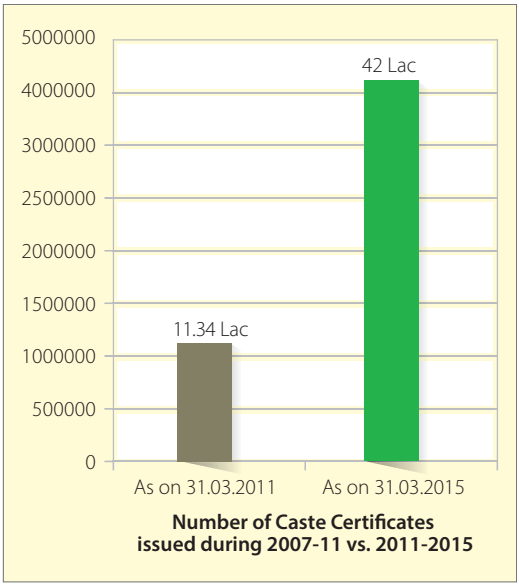

Number of Caste Certificates issued during 2007-11 vs. 2011-2015

- हमारी सरकार जंगलमहल के प्रत्येक आदिवासी परिवार को ₹.२ प्रति किलो की दर से खाद्यान्न की आपूर्ति कर रही है।
- केन्दु पत्ते चुनकर जीवन-यापन करने वाले लोगों की सामाजिक सुरक्षा के लिए एक नई योजना (West Bengal Kendu Leaves Collectors' Social Security Scheme, २०१५) चालू की गयी है।

- हमारी सरकार ने SC और ST छात्रों व छात्राओं की पेशवर व कारीगरी शिक्षा की सुविधा को ध्यान में रख-कर देश में अध्ययन करने वालों के लिए आसान शर्तों पर अधिकतम १० लाख रुपये और विदेशों में शिक्षा ग्रहण करने वालों के लिए अधिकतम २० लाख रुपये ऋण देने की व्यवस्था की है, जो कि पूरे देश के लिए मॉडल है।

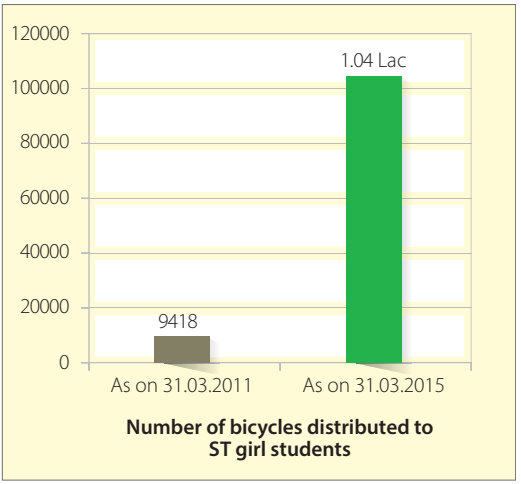

- हमारे राष्ट्रीय जीवन में बाबा साहब अम्बेडकर का अतुलनीय योगदान रहा है। उनकी १२५वीं जयंती को स्मरण करके हमने ३० दिसम्बर को पूरे राज्य भर में अम्बेडकर दिवस का पालन किया है। राज्य के State Institute of Panchayat & Rural Development का नाम बदल कर हमने नया नाम Dr. B.R. Ambedkar State Institute of Panchayat & Rural Development दिया है। जलपाईगुड़ी के नागराकाटा में एवं उत्तर २४ परगना के बागदा में हमने २ अदद अम्बेडकर विद्यालय का निर्माण किया है।

पिछड़े लोगों को अग्रसर करना ही हमारी सरकार का लक्ष्य है। सिर्फ़ उपर्युक्त कार्यों के जरिए यह लक्ष्य पुरा करना संभव नहीं है। इसलिए और भी काम करेंगे। इन सभी लोगों के जीवन स्तर को और बेहतर बनाने के लिए और अधिक उन्नति करेंगे। क्या करेंगे, उनमें से कुछ का उल्लेख नीचे किया जा रहा है।

- पिछड़ी श्रेणी के कल्याण के क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं की स्वच्छता, दृष्टि-आकर्षण तथा उनकी समझदारी में वृद्धि की जाएगी।
- विभिन्न स्कीमों एवं योजनाओं का प्रचार-प्रसार और अदिक हो तथा वे निर्दिष्ट लोगों तक पहुँचें, इसकी तरफ ध्यान दिया जाएगा।
- योग्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के दायरे में आए, उसके लिए व्यवस्था की जाएगी।
- विशेष नियुक्ति अभियान के जरिए सरकारी विभागों में आरक्षण के माध्यम से नियुक्त कर्मचारियों की संख्या में कमी की समस्या का समाधान किया जाएगा।
- पिछड़े वर्ष के समस्त योग्य छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी एवं विभिन्न प्रशिक्षण एवं रोजगार का अवसर प्रदान किया जाएगा।
- प्रांतिक जाति व श्रेणी के लोग जाति प्रमाणपत्र लेकर रोजगार प्राप्त कर सकें, उसके लिए एक विशेष अभियान चलाया जाएगा।
- और अधिक छात्रावास, पुस्तकालय तथा कंप्यूटर प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी।
- सभी लोगों की सामाजिक सुरक्षा तथा महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा के ऊपर और ध्यान दिया जाएगा।
- प्रांतिक लोगों को जाति प्रमाणपत्र एवं वृत्ति दी जाएगी।
- विशेष प्रशिक्षण के माध्यम से पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे परिणाम की संभावना बढ़ायी जाएगी।
- खेल-कूद में पिछड़े वर्ग के लोगों को और अधिक अवसर प्रदान किए जाएँगे।
- शेष महकमा के लिए जाति प्रमाणपत्र के ऑनलाइन आवेदन फॉर्म सहज उपलब्ध कराये जाएँगे।
- अम्बेडकर सेण्टर ऑफ एक्सिलेंस पिछड़े लोगों के सुविधार्थ मल्टी डायमेंशनल प्रोग्राम के जरिए आपसी सहयोगिता का जो काम कर रहा है, उसका प्रचार-प्रसार विभिन्न जिलों में किया जाएगा।
- निरंतर दक्षता वृद्धि की विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से पिछड़ी श्रेणी के युवक-युवतियों को नौकरी पाने का मार्ग प्रशस्त किया जाएगा।

आवासन

निवास स्थान मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता है और अधिकार भी। हमने लोगों को वह अधिकार दिया है। हम महसूस करते हैं कि सिर के ऊपर छत और दोनों टाइम का भोजन पाने का अधिकार सबका है। इसीलिए सरकार चलाने के पहले दिन से ही परीश्रम करने वाले साधारण लोगों के आश्रय के बारे में हमारी नजर पड़ी है।

वादे पूरे किए:

- आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए चालू की गयी "गीतांजलि" परियोजना के अन्तर्गत विगत साढ़े चार वर्षों में १.७९ लाख परिवार लाभान्वित हुए हैं। अगले मई महीने तक और २० हजार परिवार इस सुविधा का लाभ पाने जा रहे हैं।
- यात्रियों की सुविधा के लिए "पथ साथी" परियोजना में सड़क के किनारे ६९ ढाँचे बनाए जा चुके हैं।

- "आकांक्षा" परियोजना के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों के लिए ५0 हजार आवास का निर्माण किया जा रहा है। इसे पूरा करने के लिए सरकार ने मुफ्त जमीन की व्यवस्था की है।
- "प्रत्याशा" योजना के अन्तर्गत पुलिस कर्मचारियों के लिए मालिकाना आधार पर वासस्थान बनाए जा रहे हैं। इसे मूर्त्त रूप देने के लिए राज्य सरकार ने मुफ्त जमीन की व्यवस्था की है।

जनसंख्या के काफी दबाव के बावजूद लोगों को आश्रय प्रदान करने के प्रयास में कुछकाम किए गए हैं। अगले पाँच वर्षों में और क्या-क्या करने की इच्छा है, उसे नीचे दिया जा रहा है।

- अगले पाँच वर्षों में राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए ५0,000 फ्लैट/मकान का निर्माण किया जाएगा।
- रोगियों के कारण जिन लोगों को अस्पताल में रुकना आवश्यक होता है, उनके लिए २५ अदद "रात्रिकालीन प्रतीक्षालय (Night shelter) का निर्माण किया जाएगा।
- पथचारियों के चलने की सुविधा के लिए अगले ५ वर्षों में विभिन्न सुविधायुक्त सेवाएँ प्रदान करने के लिए १00 "पथ साथी" का निर्माण किया जाएगा।
- सीमित आर्थिक क्षमता वाले लोगों के लिए कई rental housing बनाए जाएँगे।

लोक निर्माण एवं परिवहन

सभ्यता की सर्वश्रेष्ठ सीढ़ी है सड़क। इसीलिए विकास कार्य शुरू करते समय मालूम पड़ा कि और सड़कें चाहिए और अच्छी सड़कों एवं अच्छी संरचना की जरूरत है।

इन चार-साढ़े चार वर्षों के दौरान हमने जो-जो कार्य किये हैं, उनके प्रमुख अंशों का उल्लेख यहाँ किया जा रहा है।

- हमारी सरकार ने राज्य राजमार्ग की १२७० किमी. सड़क की २ लेनिंग का काम तथा २६७२ किमी. सड़क के चौड़ीकरण का कार्य पूरा किया है, जो कि एक नजीर है।
- एनएच-३४ के विकल्प के रूप में उत्तर में मोरग्राम से लेकर दक्षिण में मेछोग्राम तक North south Road corridor का निर्माण ₹३२०० करोड़ खर्च करके किया गया है।

- राज्य में परिवहन में नई गति आई है। दुर्गापुर में अण्डाल विमानपत्तन देश का सर्वप्रथम निजी उद्योग से निर्मित GreenField Airport के रूप में चिह्नित हुआ है। दुर्गापुर से कोलकाता होकर नई दिल्ली के लिए उड़ान चालू हो गयी है।
- एशियन हाइवे प्रोजेक्ट के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल को जोड़ने वाली नेपाल-बंगलादेश एशियन हाईवे-२ (एएच-२) एवं भूटान-बंगलादेश एशियन हाइवे ४८ (एएच-४८) का निर्माण कार्य चल रहा है।
- उत्तर बंगाल पूर्वोत्तर भारत का मूल प्रवेश मार्ग है। साथ ही साथ उत्तर बंगाल के साथ दूसरे पड़ोसी देशों की सीमाएँ जुड़ी हुई हैं - जैसे बंगलादेश, नेपाल व भूटान के साथ। उत्तर बंगाल का विकास तथा उद्योग संभावनाओं की उन्नति सारे राज्य में उन्नयन का एक ज्वार उत्पन्न कर सकता है। गत जून महीने में भूटान के थिम्पू में BBIN (Bangladesh, Bhutan, India and Nepal) Motor Vehicle Agreement पर हस्ताक्षर करके इन चारो देशों के मध्य यात्री एवं माल परिवहन का आवागमन सुगम हुआ है। इसके फलस्वरूप, भविष्य में इस क्षेत्र का समग्र आर्थिक और सांस्कृतिक विकास होगा।

- वाणिज्यिक रूप से गाड़ी चलाकर रोजगार वृद्धि के उद्देश्य से गतिधाराफ परियोजना चालू की गयी है।
- परिवहन क्षेत्र में असंगठित कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखकर "West Bengal Transport Workers' Social Security Scheme" चालू की गयी है।
- कोलकाता - ढाका - अगरतला बस सेवा चालू की गयी है।
- यात्रियों की सुविधा के लिए कोलकाता - मालदा, कोलकाता - बालुरघाट, कोलकाता - गंगासागर, कोलकाता - दीघा तक हेलीकॉप्टर सेवा चालू हो गयी है।
- AC बस सहित १५०० नई स्टेट बसें चालू हो गयी हैं। और २५० अदद नई बसें खरीदी जा रही हैं।
- १५ हजार No refusal Taxi सड़क पर उतारी गई हैं।
- निजी क्षेत्र की ४ हजार नई बसों को परमिट प्रदान की गई है।
- साँतरागाछी बस टर्मिनस सहित ८२ अदद नए बस टर्मिनस महत्वपूर्ण स्थानों पर स्थापित हुए हैं।

बंगाल के सर्वांगीण विकास की गति निरंतर जारी रखने के उद्देश्य से आगे आनेवाले दिनों के लिए इस क्षेत्र में प्रस्तावित योजनाओं का उल्लेख नीचे दिया गया है।

- कोलकाता - अण्डाल - बागडोगरा के साथ समन्वय स्थापित करके Expansion के लिए सक्रिय कदम उठाए जाएँगे, ताकि इन स्थानों में राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक विमान उड़ान भर सकें।

- गंगा के सौंदर्यीकरण एवं जलयानों की संख्या बढ़ायी जाएगी।
- "भोर सागर" का गहरा समुद्र बन्दरगाह (जिसे अभी हाथ में लिया गया है) हमारे राज्य की आर्थिक व सामाजिक उन्नति में पर्याप्त सहायता करेगा।
- कोलकाता व निकटवर्ती क्षेत्रों में मेट्रो रेल परियोजनाएँ भली प्रकार सम्पन्न होंगी।
- कई हजार नई बसों एवं टैक्सियों के माध्यम से परिवहन संबंधी जरूरतों को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। e-rickshaw project के ऊपर और नजर डाली जाएगी।

Jetty constructed by WBTIDCL at Dakshineswar, North 24 Parganas

Newly constructed Bus Terminus at Santragachi

पर्यटन

कवि ने कहा है, "बंगाल का चेहरा मैंने देखा है, इसलिए मैं पृथ्वी का रूप खोजना नहीं चाहता।" फिर भी उन्हें हमारे राज्य में दूर-दूर तक फैली प्रकृति की गोद इतने दिनों तक अछूती रह गई थी। हमने इन चार वर्षों में उन्हें ढूँढ़ निकाला है, पुनरुद्धार किया है एवं पहचान दिलाई है - इन क्षेत्रों को। पर्यटन क्षेत्र में व्यापक विस्तार हुआ है।

उस कर्मयज्ञ में से कुछेक का उल्लेख यहाँ किया गया है :

- वर्ष २०१०-११ में पर्यटन का बजट था ₹४० करोड़, जो २०१५-१६ में बढ़कर ₹२५७ करोड़ हो गया है।
- पर्यटन उद्योग में निजी क्षेत्र का स्वागत करते हुए हमने West Bengal Incentive Scheme २०१५ चालू किया है। यह नई Incentive Scheme निवेशकों को Eco-Tourism, Home-Tourism, Tea Tourism, Adventure Sports आदि क्षेत्र में निवेश के लिए प्रोत्साहित करेगी।
- दुर्गापुर में State Institute of Hotel Management का निर्माण किया गया है।
- Home Stay Tourism के विकास पर विशेष महत्व दिया गया है। Home Stay Tourism पर्यटकों के लिए एक नए आकर्षण का केन्द्र बन गया है।

- कोलकाता महानगरी को पर्यटकों तथा जनसाधारण की दृष्टि में और आकर्षक बनाने के लिए "मिलेनियम पार्क" तथा गंगा के दोनों तटवर्ती क्षेत्रों, रवीन्द्र सरोवर, बैष्णवघाटा-पाटुली जलाशय (बेनुवनछाया) इत्यादि का व्यापक सौंदर्यीकरण किया गया है। इसके अलावा, न्यूटाउन में नया इको-टूरिज्म पार्क-प्रकृति तीर्थ, रवीन्द्र तीर्थ, नजरूल तीर्थ, मदर्स वैक्स म्युजीयम इत्यादि की स्थापना के फलस्वरूप कोलकाता आज पर्यटकों के लिए आकर्षण का केन्द्र बन गया है।
- पूर्व मिदनापुर जिले में मात्र १८ माह के रिकॉर्ड समय में "दीघा गेट" (साढ़े छः करोड़ रुपये के व्यय से) का निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त, दीघा, शंकरपुर, ताजपुर और मंदारमणि में वाच टावर, दीघा में "विश्वबांग्ला उद्यान", दीघा युवा आवासन का आधुनिकीकरण, नया काली मंदिर तक समुद्र तटवर्ती सड़क, दीघा-मोहना सड़क सहित कुल ९ परियोजनाओं का काम पूरा हो गया है। अढ़ाई करोड़ रुपये के व्यय से दीघा में "विश्वबांग्ला उद्यान" का सम्प्रसारण सहित गाड़ी पार्किंग तथा उससे जुड़ी अन्य सभी सेवा का निर्माण कार्य चल रहा है।
- जलपाईगुड़ी के गाजोलडोबा में Public Private Partnership (PPP) Model में एक इको-टूरिज्म पार्क का निर्माण किया जा चुका है। लगभग ₹१०० करोड़ के खर्च से

यहाँ सड़क, बिजली, पेय जल तथा अन्य ढांचागत सुविधाओं का निर्माण किया गया है।

- दार्जिलिंग जाते समय सिलीगुड़ी से मात्र ८ किमी. की दूरी पर Bengal Safari Park (North Bengal Wild animal Park) हमने बनाया है। इस पार्क का नाम रखा गया है - बंगाल सफारी पार्क। इस बंगाल सफारी में विशेष रूप से तैयार गाड़ी में बैठकर सैलानी खुले परिवेश में स्वच्छंद विचरण करते हुए वन्य प्राणियों को देख सकेंगे और "अफ्रीकन सफारी" का आनन्द उठा सकते हैं। २९७ हेक्टेयर जमीन पर फैले इस पार्क का कुल परियोजना व्यय था ₹२५० करोड़, जिसमें से २२ हेक्टेयर क्षेत्र में Tiger Safari, २४ हेक्टेयर क्षेत्र में Leopard Safari, २२ हेक्टेयर में Himalayan Black Bear Safari तथा ९१ हेक्टेयर क्षेत्र में Herbivores Safari बनाया गया है।
- गंगा पुनर्जीवन परियोजना के अन्तर्गत दक्षिण २४ परगना के मूड़ीगंगा तट का सौंदर्यीकरण, रखरखाव इत्यादि की एक वृहद् परियोजना हाथ में ली गई है। गंगा सागर और कपिल मुनि आश्रम से जुड़े क्षेत्र पर्यटकों एवं तीर्थयात्रियों के सुविधार्थ नए रूप से सुसज्जित किए गए हैं।

- दक्षिण २४ परगना के सागर में "ढेऊ सागर" तथा "रूप सागर" नामक दो समुद्री टीले को विश्व-स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया है।
- दक्षिण २४ परगना के झड़खाली में लगभग २५ करोड़ रुपए का प्रावधान करके (विश्व में प्रथम मैनग्रोव्स जंगल के बीच चिड़ियाखाना), "व्याघ्र सुन्दरी-सुन्दरवन वन्य प्राण उद्यान" का निर्माण किया जा रहा है। लगभग ₹४00 करोड़ के प्रावधान से बड़खाली में एक इको-टूरिज्म परियोजना का निर्माण किया जा रहा है।
- मुर्शिदाबाद के लालबाग में मोतीझील एक नए Tourism Destination के रूप में उभर कर आया है।
- हुगली के बलागढ़ में सबुजद्वीप इको-टूरिज्म परियोजना में राज्य सरकार पी.पी. पी. मॉडल पर काम कर रही है। राज्य पर्यटन मंत्रालय के आर्थिक सहयोग से इस बीच WBTDC दो काठ की जेट्टी, हुगली जिला परिषद एवं सड़क सुधार, PHE

की पेय जल व्यवस्था इत्यादि का काम भी तेज गति से हो रहा है।

- पश्चिम मिदनापुर के झाड़ग्राम राजबाड़ी का कायाकल्प करके एक पर्यटन केन्द्र बनाने का काम पूरा हो गया है।
- पुरुलिया जिले के जयचण्डी पहाड़ पर ग्रामीण पर्यटन सहित कुल चार पर्यटन परियोजनाओं का काम समाप्त हुआ है। पाकबिड़रा, मुराडी तथा तेलकूपी इको-टूरिज्म परियोजना के कार्य सम्पन्न हुए।
- कोलकाता क्रिसमस उत्सव नामक वार्षिक कार्यक्रम का नाम परिवर्तित किया गया है। यह उत्सव दिसम्बर के अंत में दो सप्ताह तक पार्क स्ट्रीट एवं एलेन पार्क में आयोजित किया जाता है। पर्यटन विभाग के उत्सव कलेण्डर में इस कार्यक्रम को शामिल किया गया है।
- भूमि एवं भूमि सुधार विभाग की चाय पर्यटन नीति की घोषणा के बाद से चाय-पर्यटन में एक खास तरह का प्रोत्साहन प्रदान किया गया है। इस बीच एक प्रस्ताव मंजूर हुआ है और कई प्रस्ताव प्रतीक्षाधीन हैं।

पर्यटन क्षेत्र में पश्चिम बंगाल का भविष्य उज्ज्वल है। कई कार्य किए गए हैं। भविष्य में और भी बहुत से कार्यों के माध्यम से इस क्षेत्र का विकास करना हमारा लक्ष्य होगा। क्या करेंगे, उनमें से कुछ उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं।

- राज्य में पर्यटक आगमन की दर में कई प्रतिशत की वृद्धि का जाएगी।
- गाजलडोबा में स्टार एवं किफायती रिसॉर्ट सहित इको-टूरिज्म हब का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा भी रहेगा-गोल्फ कोर्स समेत रिसॉर्ट, हॉस्पिटलिटी

इंस्टीट्यूट, सुस्वास्थ्य केन्द्र। एलीफेण्ट सफारी, मछली पकड़ना, कयाकिंग, पक्षी दर्शन इत्यादि की व्यवस्था रहेगी। महानन्दा वाइल्ड लाईफ सेन्चुरी एवं गोरूमारा व चापड़ा मारी नेशनल पार्क के साथ सामने एवं पीछे इण्टीग्रेशन होगा।

- स्टार एवं किफायती रिसॉर्ट, पर्यटकों के लिए सुव्यवस्था एवं नदी विहार की व्यवस्था सहित झाड़खाली टूरिज्म हब का उन्नयन किया जाएगा।
- राज्य में कई हजार ब्राण्डेड होटल रूम का सृजन किया जाएगा।
- दीघा- मंदारमणि - शंकरपुर - बकखाली - हेनरी आइलैण्ड इत्यादि के किनारों से जुड़े इलाके का विकास किया जाएगा। इन सब स्थानों के सौंदर्यीकरण, ऐडवेंचर स्पोर्ट्स की शुरुआत, समुद्री बालू की सफाई, समुद्री बालू की सुरक्षा व्यवस्था की उन्नति, खाने-पीने के किओस्क, पैदल मार्ग का निर्माण कपड़े बदलने के कक्षा का निर्माण, शौचागार निर्माण, वृक्षारोपण आदि का कार्य किया जाएगा।
- चलचित्र निर्माता इस राज्य में और अधिक चलचित्र निर्माण के लिए आ सकें, इसके लिए विशेष प्रोत्साहन योजना की व्यवस्था की जाएगी।
- सुन्दरवन, गंगा एवं उनके किनारों के क्षेत्रों में हाउस बोट बनाए जाएँगे, जिससे लेजर टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा।

- राज्य द्वारा प्रायोजित एक मात्र पर्यटन कार्यक्रम के रूप में बंगाल ट्रैवेल मार्ट को एक कैलेण्डर कार्यक्रम के रूप में प्रतिष्ठित किया जाएगा एवं टूरिज्म फेयर (पर्यटन मेले) एवं फेस्टिवल तालिका में उन्हें शामिल किया जाएगा।
- सालभर विभिन्न कार्यक्रमों एवं ३६० डिग्री अभियान के माध्यम से पश्चिम बंगाल में पर्यटन विषय को हाईलाईट किया जाएगा। इन कार्यों के माध्यम से देशी एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पश्चिम बंगाल को पर्यटन-स्थल के रूप में स्थान दिलाया जाएगा।

इन सबके अलावा और भी कई नई परियोजनाएँ हमारे पास होंगी, जिनके ज़रिए बंगाल कृषि एवं उद्योग के क्षेत्र में अपना खास मुकाम हासिल करेगा। उद्योग की स्थापना एवं नई पीढ़ी की प्रधानता को लेकर तैयार होगा नए जमाने का '' नया बंगाल''।

जिस बंगाल को देखकर साधारण लोग कह उठेंगे What Bengal Thinks today, India thinks tomorrow.

विश्व अग्रणी बंगाल का गठन ही है हमारे आने वाले दिनों का लक्ष्य, सपना एवं शपथ।

जय हिन्द

आपकी

तृणमूल मतलब एगिये बांगला
उद्योग, शिक्षा, संस्कारों में
तृणमूल मतलब हर वादा
पूरा हुआ चार सालों में।

तृणमूल मतलब डट कर
दुष्कृतियों से मुकाबला
तृणमूल मतलब आज और कल
बंगाल का हो भला।

तृणमूल मतलब घासफूल की सुबह
अंधेरे में आशा का उजियारा
तृणमूल मतलब मेरा विकास
और साथ में तुम्हारा।

तृणमूल मतलब तनी कमर
बंगाल के विकास की
तृणमूल मतलब है ममता
माँ-माटी-मानुष के आस की।

आगामी सोलहवें राज्य विधानसभा चुनाव में
अखिल भारतीय तृणमूल कॉन्ग्रेस उम्मीदवारों को
इस चिह्न पर

वोट देकर विजयी बनाएँ

सुब्रत बक्सी, अध्यक्ष, राज्य तृणमूल कॉन्ग्रेस एवं पार्थ चटर्जी, महासचिव,
तृणमूल कॉन्ग्रेस द्वारा क्रमशः प्रचारित एव सी.डी.सी. प्रिंटर्स प्रा. लि., कोलकाता - ७०००१५ द्वारा मुद्रित